रजिस्ट्री सं० डी०(डी)-73

REGISTERED No. D.(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 18, 1975/पौष 28, 1896

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 18, 1975/PAUSA 28, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1974

का०आ० 132—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 272-माण्डू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उसमान गनी, मो० पो० स्वाग, थाना गोमिया जिला हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10–क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उसमान गनी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/272/72 (153)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 17th December, 1974

S.O. 132.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Usman Gani At & P.O. Swang P. S. Gomiya, Hazaribagh who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 272-MANDU constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Usman Gani to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/272/72(153)]

125 GI/74—1

का०आ० 133.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 272—माण्डू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कमला चन्द उपाध्याय ग्राम—पो० रेलीगड़ा, जिला हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण मे निर्वाचन निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कमला चन्द उपाध्याय को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/272/72(154)]

S.O. 133.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kamla Chand Upadhaya At & P.O. Religara Hazaribagh who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 272-MANDU constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kamla Chand Upadhaya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/272/72(154)]

का०आ० 134.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 272—माण्डू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री नन्द कुमार सिंह, गीदी 'सी' वासरी कोलोनी हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही हैं;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नन्द कुमार सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार वि० स०/272/72(155)]

S.O. 134.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nand Kumar Singh, Giddi 'C' Washery Hazaribagh who was a contesting candidate for electric to the Bihar Legislative Assembly from 272-MANDU constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nand Kumar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/272/72(155)]

का०आ० 135.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 272—माण्डू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम केयर सिंह, वेस्टबोकारो कोलियरी, पो० घाटोटांड, हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामकेयर सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/272/72(156)]

S.O. 135.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Keyar Singh, West Bokaro Collery P.O. Ghatoland, Hazaribagh who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 272-MANDU constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Keyar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/272/72(156)]

का०आ० 136.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 मे हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 272—माण्डू निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री सुरेन्द्र देव शर्मा ग्राम लहयो पो० दनिया, जिला हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग आयोग एतद्वारा उक्त श्री सुरेन्द्र देव शर्मा को ससद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश का तारीख से तीन वर्ष की कलावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[स० बिहार-वि०स०/272/72(157)]

S.O. 136.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Surendra Deo Sharma Village Laio P.O Dania, Hazaribagh who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 272-MANDU constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Surendra Deo Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No BR-LA/272/72(157)]

का०आ० 137.—यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 मे हुए मेघालय विधान सभा के निर्वाचन के लिए 46 रसुबेलपारा (अ० ज० जा०) स ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री पोलीकार्प जेम्स मार्क, ग्राम रसुबेलपारा, पो० रेसुबेलपारा, जिला गारो-हिल्स (मेघालय), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गये नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं,

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी सम धान हो गया है कि उसके पास इस इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है

अत अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा उक्त श्री पोलीकार्प जेम्स मार्क को ससद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लि इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[स० मेघा०-वि० स०/46/72]

S.O. 137.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Polycarp James Marak, Village Resubelpara, P.O. Resubelpara, District Garo Hills, (Meghalaya) a contesting candidate for general election to the Meghalaya Legislative Assembly held in March, 1972 from 46-Resubelpara (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of the section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Polycarp James Marak be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No MEG-LA/46/72]

का०आ० 138.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मेघालय विधान सभा के निर्वाचन के लिये 54-सेलसेल्ला (अ० ज० जा०) सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री रोसेन्द्रा हाजोग, ग्राम बान्दा बाक्स, पो० राजबाला, जिला गारोहिल्स, (मेघालय), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और ,यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अत अब ,उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रोसेन्द्रा हे जोग ,को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[स० मेघा०-वि० स०/54/72]

S.O. 138.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rosendra Hajong, Village Banda-Box, P.O. Rajabala District, Garo Hills (Meghalaya) a contesting candidate for general election to the Meghalaya Legislative Assembly held in March, 1972 from 54-Selsella (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rosendra Hajong to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No MEG-LA/54/72]

आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1974

का०आ० 139.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1974 में हुए पांडिचेरी विधान सभा के निर्वाचन के लिए 14-थिरुबुवनाय सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोविन्धन, 54, कालिथीरथालकुप्पम्पेट, मडगलीपेट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गोविन्धन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० पांडि-वि० स०/14/74]

ORDERS

New Delhi, the 18th December, 1974

S.O. 139.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Govindhan, 54, Kalitheerthalkuppampet, Madagalipet, a contesting candidate for the general election to the Pondicherry Legislative Assembly held in February, 1974, from 14-Thirubuvanai constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Govindhan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. POND-LA/14/74]

का०आ० 140.—यत., निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1974 को हुए पांडिचेरी विधान सभा के निर्वाचन के लिए 27-नेडुनकाडो (अ० जा०) सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एन० रासनगाम, थेरकुचेरी, अग्राकारुम्बागराम, पो० कुरुमबागराम, पांडिचेरी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रासनगाम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० पांडि-वि० स०/27/74(2)]

S.O. 140.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri N. Rasangam, Thekucherry, Agarakurumbagaram, Kurumbagaram Post, Pondicherry, a contesting candidate for the general election to the Pondhichery Legislative Assembly held in February, 1974, from 27 Naduncadu (SC) constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri N. Rasangam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either house of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. POND-LA/27/74(2)]

का०आ० 141.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अप्रैल, 1974 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन के लिए 140-चित्तूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एम० जयारमन, जनकरापल्ले, चित्तूर पो० तथा तालुक (आन्ध्र प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है;

अत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एम० जयारमन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आं० प्र०-वि० स०/140/74]

S.O. 141.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri M. Jayaraman, Janakarapalle, Chittoor P.O. and Taluk (Andhra Pradesh), a contesting candidate for the bye-election held in April, 1974 to the Andhra Pradesh Legislative Assembly from 140, Chittoor constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri M. Jayaraman to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No AP-LA/140/74]

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1974

का० आ० 142.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, पंजाब सरकार के परामर्श से श्री आई० सी० पुरी का उनके इस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से, पंजाब राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है ।

[सं० 154/पंजाब/74]

New Delhi, the 19th December, 1974

S.O. 142.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Punjab, hereby nominates Shri I. C. Puri as the Chief Electoral Officer for the State of Punjab, with effect from the date he takes charge of the office.

[No. 154/PB/74]

आदेश

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1974

का० आ० 143.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1974 में हुए मणिपुर विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये 42-टेन्नोउपाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एन० जी० हेरमाशिंग, कोमलाथाबी, बी० पी० ओ० लिवाचांगनिंग टेन्नोउपाल उपखण्ड, इम्फाल (मणिपुर), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एन० जी० हेरमाशिंग को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० मणि०-वि० स०/42/74]

ORDER

New Delhi, the 20th December, 1974

S.O. 143.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri N. G. Hermashing Komlathabi, B.P.O. Liwachangning, Tengnoupal Sub-Division, Imphal (Manipur) a contesting candidate for general election to the Manipur Legislative Assembly held in March, 1974 from 42-Tengnoupal (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri N. G. Hermashing, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MR-LA/42/74]

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1974

का० आ० 144.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से श्री डी० बालगोपालन को छुट्टी स्वीकृत किए जाने पर उनके स्थान पर श्री टी० वेन्कटस्वामी, अपर सचिव, कर्नाटक सरकार, विधि तथा संसदीय-कार्य विभाग को तारीख 1 जनवरी, 1975 से अगले आदेशों तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है ।

[सं० 154/मैसूर/74]

ORDERS

New Delhi, the 24th December, 1974

S.O. 144.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Karnataka, hereby nominates Shri T. Venkataswamy, Additional Secretary to Government, Department of Law and Parliamentary Affairs, as the Chief Electoral Officer with effect from the 1st January, 1975 and until further orders vice Shri D. Balagopalan granted leave.

[No. 154/MY/74]

का० आ० 145.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-मलेहरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वेशपाल सिंह, गांव और पो० सिमारिया, जिला बस्तरपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत. अब, उक्त श्री वेशपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म० प्र०-वि० स०/36/72(65)]

बी० नागसुब्रमण्यम, सचिव

S.O. 145.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Deshpal Singh, Village and Post Simariya, District Chhatarpur who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 36-Malehra constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Deshpal Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/36/72(65)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1975

का० आ० 146.—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स नार्दर्न डूआर्स टी कम्पनी लिमिटेड से कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 207/70 दिनांक 23-10-1970) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 2/25/74 एम-2]

वी० पी० उप्पल, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 3rd January, 1975

S.O. 146.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/S. NORTHERN DOOARS TEA CO. LTD. under the said Act (Certificate of registration No. 207/70 dated the 23rd October, 1970).

[No. 2/25/74-M-II]

V. P. UPPAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1974

का० आ० 147.—श्री ए० एन० प्रसाद को नियुक्ति, जिसे धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 12क के अधीन आदेश सं० 14 फा० सं 328/63/73-डब्लू-टी (कृषि-भूमि) तारीख, 13 मार्च, 1974 द्वारा कृषि भूमि का मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त किया गया था, रद्द की जाती है।

[सं० 94/74/फा० सं० 328/245/74-डब्लू टी (कृषि-भूमि)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

ORDERS

New Delhi, the 5th November, 1974

S.O. 147.—The appointment of Shri A. N. Prasad who was appointed as Valuation Officer for Agricultural Lands u/s 12A of the Wealth-tax Act, 1957 by order No. 14 in F. No. 328/63/73-WT (Agricultural Lands) dated 13th March, 1974 is hereby cancelled.

[No. 94/74/F. No. 328/245/74-WT (Agricultural Lands)]

का० आ० 148.—केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदनाम सहित मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त करती है :—

सारणी

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री एम० के० मिश्र	मूल्यांकन अधिकारी
2.	श्री बी० डी० सिंह	मूल्यांकन अधिकारी
3.	श्री बी० पी० शर्मा	मूल्यांकन अधिकारी

[सं० 95/74/फा० सं० 328/245/74-डब्लू टी (कृषि भूमि)]

S. O. 148.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) the Central Government hereby appoints the person specified in Column (2) of the Table below as Valuation Officer with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

TABLE

S. No	Name of the person	Designation
1	2	3
1.	Shri M.K. Misra	Valuation Officer.
2.	Shri B.D. Singh	Valuation Officer
3.	Shri B.P. Sharma	Valuation Officer

[F. No. 328/245/74-WT (Agricultural lands)]

का० आ० 149.— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर नियम 1957 के नियम 3क के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में कृषि भूमियों के सम्बन्ध में मूल्यांकन अधिकारी के कृत्यों का पालन करेगा।

सारणी

क्रम संख्या	मूल्यांकन अधिकारी	आयकर आयुक्त
1.	श्री एम० के० मिश्र, आय- कानपुर	I, II और III प्रभार कर अधिकारी
2.	श्री बी० सिंह, आयकर अधि- कानपुर	I, II और III प्रभार कारी
3.	श्री बी० पी० शर्मा, आयकर कानपुर,	I, II और III प्रभार अधिकारी

[सं० 96/74 फा० सं० 328/245/74 डब्ल्यू० टी० (कृषि-भूमि)]

एस० बापू, अवर सचिव

S. O. 149.— In exercise of the powers conferred by sub rule (2) of Rule 3A of the Wealth Tax Rules, 1957 the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Valuation Officer specified in column (2) of the Table appended hereto shall perform the functions of a Valuation Officer in respect of agricultural lands in the areas within the territorial jurisdiction of the Commissioner of income-tax specified in the corresponding entry in column (3) of the Table.

TABLE

S. No.	Valuation Officer	Commissioner of Income-tax
1.	Shri M.K. Misra, Income-tax Officer	Kanpur I, II & III Charges
2.	Shri B.D. Singh, Income-tax Officer	Kanpur I, II & III Charges
3	Shri B.P. Sharma, Income-tax Officer	Kanpur I, II & III Charges

[No. 96/74/F. No. 328/245/74-WT (Agricultural lands)]

S. BAPU, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1974

का० आ० 150.— केन्द्रीय सरकार, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में, की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदनाम सहित मूल्यांकन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पदनाम
1.	श्री के० के० मोहन बाबू	जिला मूल्यांकन अधिकारी
2.	श्री सी० वी० रेड्डी	मूल्यांकन अधिकारी

[सं० 97/74/फा० सं० 328/236/ 74-डब्ल्यू० टी०]

ORDER

New Delhi, the 6th November, 1974

S.O. 150.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12A of the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Valuation Officers with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No	Name of the person	Designation
1.	Shri K. K. Mohan Babu	District Valuation Officer
2	Shri C. V. Reddy	Valuation Officer

[No. 97/74/F. No. 328/236/74-W.T.]

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1974

का० आ० 151.— केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है जिसका पदनाम उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है।

सारणी

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पदनाम
1.	श्री ए० के० मजमदार	मूल्यांकन अधिकारी
2.	श्री पी० एन० भट्टाचारजी	सहायक मूल्यांकन अधिकारी

[सं० 103/74/फा० सं० 328/251/74 ध० क०]

ORDERS

New Delhi, the 14th November 1974

S.O. 151.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Wealth-tax

Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column 2 of the Table below as Valuation Officers with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table

TABLE

S. No	Name of the person	Designation
1.	Shri A.K Majumdar	Valuation Officer
2.	Shri P M. Bhattacharjee	Assistant Valuation Officer

[No. 103/74/F No 328/251/74-W T.]

का० आ० 152.—धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) की धारा 12-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदनाम सहित मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात :—

सारणी

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पदनाम
1	श्री ई० जे० राबर्ट	जिला मूल्यांकन अधिकारी (मशीनरी और प्लांट) कलकत्ता

[सं० 102/74 फा० सं० 328/250/74-ड०क० (मशीनरी और प्लांट)]

S.O. 152.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below as Valuation Officer with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Name of the person	Designation
1	Shri E. J. Robert	District Valuation Officer (Machinery & Plant) Calcuttta

[No. 102/74/F. No 328/250/74-W.T. (Machinery and Plant]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आदेश

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1974

का० आ० 153.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि फा० सं० 328/179/74-डब्लू० टी० से जारी किया गया आदेश सं० 74 तारीख 30 अगस्त, 1974 1-10-74 के बजाय 1-11-1974 से प्रभावी होगा ।

[सं० 91/74/फा०सं० 328/179/74 डब्ल्यू० टी०]

वी० डी० वखारकर, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ORDER

New Delhi, the 29th October, 1974

S.O. 153.—Central Board of Direct Taxes direct that their Order No. 74 dated the 30th August, 1974 issued from F. No. 328/179/74-W.T. will take effect from 1-11-1974 instead of 1-10-1974.

[No. 91/74/F. No. 328/179/74-W.T.]

V. D. WAKHARKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1975

का० आ० 154.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27-क की उपधारा (1) के खंड (ध), जैसा कि वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की तारीख 23 अगस्त, 1958 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 734 द्वारा भारतीय जीवन बीमा को लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा (1975) में पुरोधृत, 6 करोड़ रुपये के मूल्य के डिबेंचरों को उपरोक्त धारा के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित विनिधानों के रूप में इन्वेस्टमेंट एतद्द्वारा घोषित करती है ।

[फा० सं० 88(75)-बीमा 4/74]

New Delhi, the 13th January, 1975

S.O. 154.—In exercise of the powers conferred by clause (q) of sub-section (1) of Section 27A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as applied to the Life Insurance Corporation of India by the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. G.S.R. 734, dated the 23rd August, 1958, the Central Government hereby declare the debentures of the value of 6 crore Rupees issued in 1975 by the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited as scheduled investments for the purpose of the above section.

[F. No. 88(75) Ins. IV/74]

का० आ० 155.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27-ख की उपधारा (1) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 1975 में पुरोधृत छ करोड़ रुपये के मूल्य के डिबेंचरों को उपरोक्त धारा के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित विनिधानों के रूप में एतद्द्वारा घोषित करती है ।

[फा० सं० 88(75)-बीमा 4/74]

र० द० खानवलकर, अवर सचिव

S.O. 155.—In exercise of the powers conferred by clause (j) of Sub-Section (1) of Section 27B of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby declares the debentures of the value of 6 crore Rupees issued in 1975 by the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited as approved investments for the purposes of the above section.

[F. No. 88(75)-Ins. IV/74]

R. D. KHANWALKAR, Under Secy.

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

(लेखा एवंव्यय विभाग)

बम्बई, 4 जनवरी, 1975

शुद्धि पत्र

का० आ० 156.—दिनांक 16 नवम्बर, 1974 के भारत सरकार के राजपत्र के भाग II खंड 3(ii) में हिन्दी में प्रकाशित 18 अक्तूबर, 1974 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप के विवरण में निम्नलिखित शुद्धि कर ली जाए।

पृष्ठ 3189 पर ऋण और अग्रिम (i) "अनुसूचित वाणिज्य बैंक" के सामने दर्शाये गये रु० 67,57,50,00000 को रु० 67,57,50,000 पढ़ा जाये ।

[संदर्भ जी ई एन. सं० 329/4-74/75]

का० आ० 157.—दिनांक 16 नवंबर 1974 के भारत सरकार के राजपत्र के भाग II, खंड 3 (ii) में हिन्दी में प्रकाशित 25 अक्तूबर, 1974 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के इशू विभाग के कार्यकलाप के विवरण में निम्नलिखित शुद्धि कर ली जाए। पृष्ठ 3186 पर "रुपये के सिक्के" के सामने दर्शाये गये रु० 19,93,83,0000 को रु० 19,93,83,000 पढ़ा जाए।

[संदर्भ ०जी ई एन०सं०330/4-74/75]

ह०/- अपठ

कृते मुख्य लेखाकार

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Accounts and Expenditure)

Bombay, the 4th January, 1975

CORRIGENDUM

S.O. 158.—In the Statement of Affairs published in English of the Reserve Bank of India Banking Department for the week ended 15th November 1974 published in Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India dated 7th December 1974, the following corrigendum may be noted. On page No. 3484 the figures Rs. 608,24,94,000 shown under "Banks" (i) Scheduled Commercial Banks and Rs. 73,10,30,000 shown under Loans and Advances (ii) State Governments may be read as Rs. 608,34,94,000 and Rs. 75,10,30,000.

[Ref. Gen No. 328/4-74/75]

Sd. Illegible

P. Chief Accountant

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1974

शुद्धि पत्र

का० आ० 159.—28 सितम्बर, 1974 को जारी किये गये भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) के पृष्ठ 2774 पर सा० आ० 2488 के अंग्रेजी पाठ में इस विभाग की अधिसूचना सं० 15(14)-बी० ओ० III/74 की तारीख "9 सितम्बर, 1973" (जो गलती से छप गई है) के बजाय "9 सितम्बर, 1974" पढ़ा जाय।

[सं० 15(14)-बी० ओ०-3/74]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, the 28th December, 1974

CORRIGENDUM

S.O. 159.—The date of this Department's Notification No. 15(14)-B.O. III/74 appearing in its English version on page 2774 against S.O. 2488 in Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India issue of 28th September, 1974 may be read as "9th September, 1974" for "9th September, 1973" which has been incorrectly printed.

[No. 15(14)-B.O. III/74]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1975

का० आ० 160.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में दिसंबर 1974 की 27 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

(इशू विभाग)

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	49,69,22,000		सोने का सिक्का और बुलियन :–		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,52,68,000	
संचलन में नोट	5966,60,54,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	141,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		6016,29,76,000	जोड़		324,26,65,000
			रुपये का सिक्का		16,69,82,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5675,33,29,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयताएं		6016,29,76,000	कुल आस्तियां		6016,29,76,000

बी०बी० चारी, उप गवर्नर

तारीख : 1 जनवरी, 1975

27 दिसम्बर 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	49,69,22,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,82,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	284,00,00,000	छोटा सिक्का	3,50,000
		खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000	(क) देशी	159,02,07,000
		(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल	411,78,63,000
		विदेशों में रखा हुआ बकाया*	503,26,60,000
जमा राशियां :—		निवेश**	405,14,60,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम —	
(i) केन्द्रीय सरकार	55,22,74,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	7,04,99,000	(ii) राज्य सरकारों को†	133,68,09,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	526,26,50,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ×	162,55,00,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	19,36,00,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को × ×	364,86,56,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,52,44,000	(iii) दूसरों को	12,19,75,000
(iv) अन्य बैंक	59,58,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	67,77,20,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	15,65,49,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	63,50,00,000
(ग) अन्य	558,04,14,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,12,58,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
देय बिल	142,23,35,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	46,13,79,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
अन्य देयताएं	697,63,92,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	244,20,93,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	156,15,83,000
रुपये	2806,83,66,000	रुपये	2806,83,66,000

* नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

** राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं; परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवर-ड्राफ्ट शामिल हैं।

× रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 27,44,00,000 रुपये शामिल हैं।

× × राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

बी०बी० चारी, उप-गवर्नर

[सं० फा० 10(1)/74-बी० ओ०-I]

ब० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

तारीख : 1 जनवरी 1975

New Delhi, the 4th January, 1975

S.O.160.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 27th day of December 1974

(Issue Department)

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	49,69,22,000		Gold Coin and Bullion:--		
			(a) Held in India	182,52,68,000	
Notes in circulation	5966,60,54,000		(b) Held outside India	..	
Total Notes issued		6016,29,76,000	Foreign Securities	141,73,97,000	
			Total		324,26,65,000
			Rupee Coin		6,69,82, 0
			Government of India Rupee Securities		5675,33,29,000
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		..
Total Liabilities		6016,29,76,000	Total Assets		6016,29,76,000

Dated the Ist day of January 1975.

V.V. CHARI, Dy. Governor

C.W. Mirchandani, Under Secretary

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 27th December 1974

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	49,69,22,000
		Rupee Coin	3,82,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,50,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	(a) Internal	159,02,07,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	411,78,63,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Balances Held Abroad*	503,26,60,000
		Investments**	405,14,60,000
		Loans and Advances to:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	133,68,09,000
Deposits:—		Loans and Advances to:—	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks+	162,55,00,000
(i) Central Government	55,22,74,000	(ii) State Co-operative Banks++	364,86,56,000
(ii) State Governments	7,04,99,000	(iii) Others	12,19,75,000
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(b) Banks			
(i) Scheduled Commercial Banks	526,26,50,000	(a) Loans and Advances to:-	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	19,36,00,000	(i) State Governments	67,77,20,000
		(ii) State Co-operative Banks	15,65,49,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,52,44,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	63,50,00,000
(iv) Other Banks	59,58,000	(b) Investment in Central Land Mortgage	

(c) Others	558,04,14,000	Bank Debentures	11,12,58,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stablilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	46,13,79,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
Bills Payable	142,23,35,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	244,20,93,00
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
Other Liabilities	697,53,92,000	Other Assets	156,15,83,000
RUPEES	2806,83,66,000	RUPEES	2806,83,66,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short—term Securities.

** Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

+Includes Rs. 27,44,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

++Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the Ist day of January 1975.

V. V. Charri Dy. Governor
[No.F. 10 (1)/74—BO. I]
C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

आयकर आयुक्त का कार्यालय
करेल, 22 नवम्बर 1974
आय-कर

की०आ० 161—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 287 उपधारा (1) एवं वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) भारत सरकार के आदेश एफ०स० (16/202/67 ए० टी० बी० दिनांक 25 मार्च 1969 के अनुसार मैं निम्नलिखित करदाताओं के नाम एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूं ।

(अ) जिन पर व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिवार होने से, एक लाख रुपये से अधिक आयकर निर्धारित किया गया है । (नाम संलग्न अनुसूची (1) में है)

(आ) जिन पर फर्म या व्यक्तियों का संगम या कंपनी होने से, दस लाख रूपये से अधिक आय पर निर्धारित किया गया है (नाम संलग्न अनुसूची (2) में है)

अनुसूची-

1973-74 के वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक आय पर करदाता व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार के नाम

क्रम सं०	नाम और पता	स्थिति	निर्धारण वर्ष	निर्धारित आय	निर्धारित आय	आयकर-देय	आयकर-प्रदत्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स /श्री०							
1	के० हरसन कोया, मे० के० अस्सन-कोया, बिग बाजार, कालिकट् ।	व्यक्ति	1972-73	1238775	1239280	1187722	1187722
2	पी० बालकृष्ण पिल्ले, इण्डरनाशनल काय्यू ट्रेडेर्स, कोल्लम ।	—वही—	1973-74	146602	194960	147874	147874
3	ए० डब्लू० जे० केप्स्, जे एण्ड पी कोट्स्, इण्डिया (प्रा०) लि०, कोरटिट ।	—वही—	1973-74	165368	165400	119940	119940
4	के० जे० फ्रांन्सीस, फाषन फेब्रिक्स, ट्रिच्चूर ।	—वही—	1972—73	166007	183130	136280	136280
5	—वही—	—वही—	1973—74	114710	126830	84483	84483

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	जे० इ० फोरब्स, जे एण्ड पी कोट्स इण्डिया (प्रा०) लि०, कोरट्टि ।	व्यक्ति	1973-74	162299	162300	117116	117116
7	जे० इ० आर० ग्रिफिथ्स, जे एण्ड पी कोट्स् इण्डिया (प्रा०) लि०, कोरट्टि ।	–वही–	1973-74	171917	171920	125967	125967
8	एच० एच० गौरी पारवती बाई, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम ।	–वही–	1973-74	206260	208280	159894	159894
9	एच० एच० गौरी लक्ष्मी बाई, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम ।	–वही–	1973-74	152840	155540	110896	110896
10	एन गोविंद पिल्लै, मरचन्ट, कोट्टयम् ।	–वही–	1973-74	122440	124900	82708	82708
11	जोन इनोक, वेस्टेण मेडिकल स्टोरस्, कोल्लम ।	–वही–	1973-74	168290	171030	129269	124963
12	पी० पी० जोस, पुत्तुक्काट, चंगनाचेरी ।	–वही–	1971-72	2500	122500	104784	खाली
13	पी० के० कुरियन (पार्टनर), मे० मेनोन एण्ड पै, एरणाकुलम ।	–वही–	1972–73	100280	100530	60288	60288
14	एच० एच० लक्ष्मी बाई, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम ।	–वही–	1973-74	156080	163260	90361	90361
15	बी० माधव बालिगा, माण मरचन्ट, सी० बी०, कण्णूर ।	–वही–	1973-74	133125	133100	90252	90252
16	के० एम० माम्मेन (पार्टनर), मलबार टिम्बर कं०, एरणाकुलम ।	–वही–	1971-72	141763	143190	95207	95207
17	बी० माणिक् प्रसाद, (पार्टनर), इण्डिया सी फूड्स्, कोच्चिन ।	–वही–	1971-72	183650	191140	138117	130812
18	डी० डी० पीकोक, जे एण्ड पी कोट्स, इण्डिया (प्रा०) लि०, कोरट्टि ।	–वही–	1973-74	129678	129680	87105	87105
19	डी० पुरुषोत्तम कम्मत्त, द्वारामे० सदानन्द पै एण्ड कं०, टेल्लिचेरी ।	–वही–	1973-74	122920	125890	83573	83573
20	एच० एच० रामवर्मा, कौडियार पालस, । प्रिन्स, तिरुवनन्तपुरम ।	–वही–	1973-74	243660	241880	163454	163454
21	एच० एच० सेतु पारवती बाई, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम ।	–वही–	1973-74	472750	476280	421864	421864
22	आर० श्रीधर पणिकर, तैकाड, तिरुवनन्तपुरम ।	–वही–	1971-72	417517	435730	422847	251381
23	जी० बी० षट्टिलवर्त, ट्रावनन्कूर टी एस्टेटस, वण्डिपेरियार ।	–वही–	1973-74	105130	114800	69110	69110
24	आर० आर० टेयलर, जे० एण्ड पी० कोट्स् इण्डिया (प्र) लि० कोरटिट ।	–वही–	1973-74	135275	135270	92248	92248
25	–वही–	–वही–	1972-73	167432	167950	122314	122314
26	ओ० सोमस, द्वारा/फोरब्स इवार्ट एण्ड फिगिस लि०, कोल्लम ।	–वही–	1969–70	104602	106590	55960	55960
27	–वही–	–वही–	1971-72	108157	117730	69966	69966
28	वेल्किडेष नायिक मोहनदास, जुवल्लर, पालयम रोड, कोषिकोड ।	–वही–	1973-74	100850	103550	64352	64352

अनूसूची 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	फोरब्स इवार्ट एण्ड फिगिस लि०, कोच्चिन	कम्पनी	1968-69	842253	1043490	678269	678269
2	केरला फिनान्श्यल कोरपरेशन, तिरुवनन्त-पुरम ।	—वही—	1973-74	1141547	1145850	692579	692579
3	सौत इण्डिया कोरपरेशन (प्र) लि०, कोच्चिन ।	—वही—	1971-72	1031710	1150464	715052	715052
4	ट्रावन्कूर टैटानियम प्रोडक्ट्स, तिरुवनन्त-पुरम ।	—वही—	1973-74	5233611	8332440	4797145	4797145
5	युनैटेड इलक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज लि० ,कोल्लम	—वही—	1973-74	1201890	1232490	711764	711764
6	वेस्टेण इण्डिया कोट्टण लि०, पाप्पिनि-शेरी ।	—वही—	1973-74	1094450	1110640	647203	647203
7	वेस्टेण इण्डिया प्लैवुड लि०, बलियपट्टम ।	—वही—	1973-74	4431273	4507420	2605017	2605017

[सी० स० 10-बी/टेक/ए/74-75 (1)]

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX

Kerala- the 22nd November, 1974

Income-tax

S.O.161—In pursuance of the sub section (1) of Section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in pursuance of the Order F. No.16/202/67-ITB dated 25th March, 1969 of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), Government of India, I hereby publish the names of the assessees:—

(a) being the individuals or Hindu Undivided Families, who have been assessed on an income of more than one lakh of rupees, in Schedule 1 appended hereto;

(b) being Firms, Association of Persons or Companies who have been assessed on an income of more than 10 lakhs of rupees, in Schedule II appended hereto,

SCHEDULE—I

Names of all individuals and Hindu Undivided Families assessed on an income over Rs. 1 lakh in the financial year 1973-74

Sl. No.	Name and address	Status	Asst. year	Income returned	Inome assessed	Income tax payable	Income-tax paid
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sri. K. Hassan Koya, M/s. K. Assankoya Big Bazar, Calicut	Individual	1972-73	1238775	1239280	1187722	1187722
2.	Sri. P. Balakrishna Pillai, International Cashew Traders Quilon	Do.	1973-74	146602	194960	147874	147874
3.	A.W.J. Capes, J&P Coats India (P) Ltd., Koratti	Do.	1973-74	165368	165400	119940	119940
4.	K.J. Francis, Fashion Fabrics, Trichur	Do.	1972-73	166007	183130	136280	136280
5.	Do.	Do.	1973-74	114710	126830	84483	84483
6.	J.E. Forbes, J&P. Coats India (P) Ltd., Koratti	Do	1973-74	162299	162300	117116	117116
7.	J.E.R. Griffiths, J & P. Coats India (P) Ltd , Koratti	Do	1973-74	171917	171920	125967	125967

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	H.H. Gouri Parvathi Bai, Kaudiar Palace, Trivandrum	Individual	1973-74	206260	208280	159894	159894
9.	H.H. Gouri Lakshmi Bai, Kaudiar Palace, Trivandrum	Do.	1973-74	152840	155540	110896	110896
10.	N. Govinda Pillai, Merchant, Kottayam.	Do.	1973-74	122440	124900	82708	82708
11.	John Enoch, Western Medical Stores, Quilon	Do.	1973-74	168290	171030	129269	124963
12.	P.P. Jose, Pullukat, Changanaherry	Do.	1971-72	2500	122500	104784	Nil
13.	P.K. Kurien (Partner), M/s. Menon & Pai, Ernakulam	Do.	1972-73	100280	100530	60288	60288
14.	H.H. Lekshmi Bai, Kaudiar Palace, Trivandrum	Do.	1973-74	156980	163260	90361	90361
15.	Sri. B. Madhava Baliga, Yarn Merchant, C.P. Cannanore	Do.	1973-74	133125	133100	90252	90252
16.	K.M. Mammen (Partner) Malabar Timber Co. Ernakulam	Do.	1971-72	141763	143190	95207	95207
17.	B. Manicka Prasad, (Partner), India Sea Foods, Cochin	Do.	1971-72	183650	191140	138117	130812
18.	D.D. Peacock, J & P Coats India (P) Ltd., Koratti	Do.	1973-74	129678	129680	87105	87105
19.	D. Purushothama Kamath, C/o. M/s. Sadananda Pai & Co., Tellicherry	Do	1973-74	122920	125890	83573	83573
20.	H.H. Ramavarma, Kaudiar Palace, 1st Prince, Trivandrum	Do.	1973-74	243660	241880	163454	163454
21.	H.H. Sethu Parvathy Bai, Kaudiar Palace, Trivandum	Do.	1973-74	472750	476280	421864	421864
22.	R. Sreedhara Panicker Thycaud, Trivandrum	Do.	1971-72	417517	435730	422847	251381
23.	G.B. Shuttleworth, Travancore Tea-Estates, Vendiperiar	Do.	1973-74	105130	114800	69110	69110
24.	R.R. Taylor, J&P Coats India (P) Ltd., Koratti	Do.	1973-74	135275	135270	92248	92248
25.	Do.	Do.	1972-73	167432	167950	122314	122314
26.	O. Thomas, C/o Forbes Ewar & Figgis Ltd., Quilon	Do.	1969-70	104602	106590	55960	55960
27.	Do.	Do.	1971-72	108157	117730	69966	69966
28.	Venkitesh Naik Mohandas, Jeweller, Palayam Road, Calicut	Do.	1973-74	100850	103550	64352	64352

SCHEDULE—II

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Forbes Eward & Eiggis Ltd., Cochin	Company	1968-69	842253	1043490	678269	678269
2.	Kerala Financial Corporation, Trivandurm	Do.	1973-74	1144547	1145850	692579	692579
3.	South India Corporation (P) Ltd., Cochin	Do.	1971-72	1031710	1150464	715052	715052
4.	Travancore Titanium Products, Trivandurm	Do.	1973-74	523611	8332440	4797145	4797145
5.	United Electrical Industries Ltd., Quilon	Do.	1973-74	1201890	1232490	711764	711764
6.	Western India Cotton Ltd., Pappinissery	Do.	1973-74	1094450	1110640	647203	647203
7.	Western India Plywwod Ltd. Bali patam	Do.	1973-74	4431273	4507420	265017	260501

[C.No. 10-B/Tech/A/74-75 (1)]

का. आ. 162.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 287 की उपधारा (1) एवं वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग), भारत सरकार के आदेश एफ सं० 16/202/67 ए० टि० बी० दिनांक 25 मार्च 1969 के अनुसार, जिन करदाताओं पर 1973-74 वित्तीय वर्ष में कम सेवा कम रु० 5,000/- अर्थ दण्ड लगाया गया, या अपीलीय अधिकरण से किसी दण्ड के विरुद्ध अपील नियत किया गया, उनके नाम तथा अन्य विवरण में नीचे प्रकाशित कर रहा हूं ।

अनुसूची

आयकर अधिनियम 1961 के खण्ड 271(1) (सी) के अनुसार आय की सूचना छिपाने के कारण जिन्हें दण्डित किया गया है या जहां गत वर्षों के दण्डों पर दिये हुए अपील की फैसला 1973-74 दिया जा चुका है ।

क्रम सं०	नाम और पता	स्थिति	दण्ड की रकम	निर्धारण वर्ष
1	2	3	4	5
			रु.	
(1)	अम्बलूर टैल वर्कस अक्तूबर	फर्म (रजिस्टर्ड)	8,000	1971-72
(2)	पी० एल० जोसेफ चापियन फायर वर्कस इरिंजालकुडा	व्यक्ति	15,330	1969-70
(3)	—वही—	—वही—	12,460	1970-71
(4)	स्व० बी० एस० श्री धरन उण्णी तैकाड, त्रिवेन्द्रम	वही	7,000	1966-67

[सी०स 10-बी/टेक/अ/74-75(1)]

एस०टी० तिरुमलाचारी, आय-कर आयुक्त

S. O. 162.—In pursuance of sub-Section (1) of Section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in pursuance of order F.N.o. 16/202/67-ITB, dated 25th March, 1969 of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Government of India, I hereby publish the names and other particulars r a g to the assessees on whom a penalty not less than Rs. 5000/- was imposed or appeals against penalties have been disposed by the Appellate Tribunal during 1973-74 as in Schedule.

D L

Persons who have been penalised for concealment of income u/s. 271(1)(c) of the Income-tax Act, 1961 or where appeals against penalties levied in earlier years have been decided during the financial year 1973-74.

Sl. No.	Name and address	Status	Amount of penalty	Asst. year
			Rs.	Rs.
1.	Annallur Tile Works, Annallur.	Firm (Regd)	8,000	1971-72
2.	P.L. Ouseph, Champion Fire Works, Irinjalakuda	Individual	15,330	1969-70
3.	—do—	—do—	12,460	1970-71
4.	Late B.N. Sreedharan Unni, Tycaud, Trivandrum.	—do—	7,000	1966-67

[C. No. 10-B/Tech./A74-75(1)]

S. T. TIRUMALACHARI, Commissioner of Income-tax,

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1974

(रबर बोर्ड)

का० आ० 162.—सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 6 ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने रबड़ बोर्ड में उप रबड़ उत्पादन आयुक्त श्री पी० मुकंदन मेनन को 21 अक्तूबर, 1974 के पूर्वाह्न से रबड़ उत्पादन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है ।

[फाइल सं० 21 (9)/73-प्लांट(बी)]

एस० महादेव अय्यर, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 24th December, 1974

(Rubber Control)

S.O. 163.—It is hereby published for the information of public that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6A of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the Central Government have appointed Shri P. Mukandan Menon, Deputy Rubber Production Commissioner in the Rubber Board, as Rubber Production Commissioner with effect from the forenoon of the 21st October, 1974.

[File No. 21(9)/73-Plant(B)]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

बंगलौर, 29 अक्तूबर, 1974

का० आ० 164.—सर्वश्री बेबी चैम्पियन प्रोडक्टस, 72 मैनेजर रंगाना लेन, नालबन्दवाडी, बंगलौर 560002, कर्नाटक राज्य को सुगंधित रसायनों, प्राकृतिक सुगंध तेल और रेजिनायडस के आयात के लिए 3,000/- रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस संख्या पी०/एस०/1829678/सी०/ क्स एक्स/50/एक्स/37-38, दिनांक 29-3-74 प्रदान किया गया था । फर्म ने सूचना दी है कि उपर्युक्त लाइसेंस उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और डाक प्राधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उक्त वस्तु डाक मार्ग में खो गई थी ।

मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई है और निदेश देता हूं कि इनकी अनुलिपि प्रतियां आवेदक को जारी की जानी चाहिएं । उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[संख्या आई०टी० सी०/एस०एस० आई०/ए-560/ए०एम०-74/एन०पी०]

आर० जयराम नायडू, उप-मुख्य नियंत्रक,

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Bangalore, the 29th October 1974

S.O. 164.—M/s. Baby Champion Products, 72-Manager Ranganna Lane, Nalbandwadi, Bangalore-560002, Karnataka State were granted an Import Licence No. P/S/1829678/C/XX/50/X/37-38, dated 29-3-74 for Rs. 3,000 for import of Aromatic Chemicals, Natural Essential Oils and Resinoids. The firm have reported that they have not received the above Import licence and the Postal authorities have also confirmed that the said article was lost during the course of transmission by post.

I am satisfied that the original Customs and Exchange Control purposes copies of the above licence have been lost and direct that a duplicate copy of the Customs purposes and Exchange Control purposes copy of the above licence should be issued to the applicant. The original Customs purposes and Exchange Control purposes copies of the above licence are hereby cancelled.

[No. ITC/SSI/A-560/AM-74/NP]

R. JAYARAM NAIDU, Dy. Chief Controller

आदेश

गोवा, 3 अक्टूबर, 1974

का.आ. 165.—सर्वश्री जोस फ्रांसिस्को पेरेरा एंड फिल्होस, मार्गो, गोवा, को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से, क्रम सं० 82/4 के अन्तर्गत आने वाले एलि, बीयर पोर्टर, साइडर और अन्य फर्मेन्टिड लिकर के आयात के लिए 1250 रु० का एक आयात लाइसेंस स० पी/ई 2659258/सी/एक्स एक्स/48/जी /37-38, दिनांक 18-7-73 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उसी की मूल प्रति बिना उपयोग किए और किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई है।

आवेदक ने नोटरी पब्लिक, मार्गो के सम्मुख विधिवत् साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० पी/ई/2659258/सी/एक्स एक्स/48/जी/37-38, दिनांक 18-7-73 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए।

यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं।

आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैंडबुक, 1974-75 की कंडिका 320 की व्यवस्थाओं के अनुसार उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जा रही है।

[संख्या ई 1/82-4/16/ए एम 74]

सी० के० रामचन्द्र राव, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

Goa, the 3rd October, 1974

S.O. 165.—M/s. Jose Francisco Pereira & Filhos, Margo, Goa, were granted import licence No. P/E/2659258/C/XX/48/G/37-38, dated 18-7-73 for Rs. 1.250 from General Area for import of Ale, Beer, Porter Cider and other fermented liquors under S. No. 82/IV.

They have applied for issue of duplicate Custom Purpose Copy of the said licence on the ground that the original copy thereof has been lost having been unutilised and without being registered with any Custom Authority.

The applicant has filed an affidavit on stamped paper duly attested before the Notary Public, Margao. The undersigned is satisfied that the original Custom Purpose copy of the licence P/E/2659258/C/XX/40/G/37-38, dated 18-7-73 has been lost and direct that a duplicate Custom Purpose Copy of the said licence should be issued to the applicant.

In exercise of the powers conferred on me under Section 9(cc) of Imports (Control) Order 1955 as amended I order the cancellation of the original Custom Purpose Copy of the said licence.

The applicants are now being issued a duplicate copy of Custom Purpose only of the aforesaid licence in accordance with the provisions of para 320 of the ITC Hand Book of Rules and Procedure 1974-75.

[No. EI/82-IV/16/AM 74]

C. K. RAMACHANDRA RAO, Dy. Chief Controller

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय,

आदेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1974

का. आ. 166.—सर्वश्री कान्सोलिडेटिड न्यूमेटिक टूल्स क०, (इंडिया) लि०, प्लाट न० 301/302, आगरा रोड, मुलन्द, बम्बई-80, को यू के० से 259 नग डबल रा एन्गुलर बाल बेयरिंग्स पार्ट स० ए-23071 के आयात के लिए 3, 713/- रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस्स सं० पी/आई/3033276/टी/एक्स एक्स/49/एच/37-38 आर एम-1 दिनांक 13-12-1973 प्रदान किया गया था। उन्होंने सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया है क्योंकि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। लाइसेन्सधारी द्वारा आगे यह सूचना दी गई है कि उक्त लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल ही उपयोग किए बिना खो गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदकों ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेन्स सं० पी/आई/3033276/टी एक्स एक्स/49/एच/37-38/ आर एम-1 दिनांक 13-12-1973 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश देता है कि इस की अनुलिपि प्रति उनको जारी की जानी चाहिए। उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[स० टूल्स/23 ए/आर एम/73-74 आर एम-1]

आई० वी० चुनकत, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 12th December, 1974

S.O. 166.—M/s. Consolidated Pneumatic Tools Co. (I) Ltd., Plot No. 301/302, Agra Road, Muland, Bombay-80, were granted import licence No. P/I/3033276/T/XX/49/H/37-38/RM-I, dated 13-12-1973 for Rs. 3,713 from U.K. for the import of double row angular ball bearings part No. S-23071-259 Nos. They have requested for issue of duplicate custom copy as the original have been lost. It has been further reported by the licensee that the said licence was lost without having been registered with any customs authorities and utilised at all.

In support of their contention the applicant has filed in an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs copy of the licence No. P/I/3033276/T/XX/49/H/37-38/RM-I, dated 13-12-1973 has been lost and directs that a duplicate customs purposes copy of the said licence should be issued to them. The original customs purposes copy of the said licence is hereby cancelled.

[No. Tools/23-A/RM/73-74/RM-I]

I. V. CHUNKATH, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 20, दिसम्बर, 1974

का.आ. 167.—मध्य प्रदेश राज्यपाल के उप सचिव, कैम्प मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली, को प्रतिबंधित स्टाक से प्राप्त करने के लिये 367/-रुपये मूल्य की व्हिस्की और ब्रान्डी के आयात के लिये सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. जी/जे/3041311/एम/एम एस/51/एच/39-40/ए एस एम, दिनांक 5-8-74

प्रदान किया गया था । उन्होंने सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया / अस्थानस्थ हो गया है । मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय मे पंजीकृत नही कराया गया था और उस का उपयोग नहीं किया गया था । मैं संतुष्ट हू कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० जी/जे/3041311, दिनाक 5-8-74 खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता हूं कि इसकी अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिए । मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द की जाती है ।

[संख्या गव/5/ए एम 75/ए एन एस/1647]

ORDER

New Delhi, the 20th December, 1974

S.O. 167.—The Deputy Secretary to the Governor of Madhya Pradesh Camp Madhya Pradesh Bhavan, New Delhi was granted a CCP No. G/J/3041311/N/MN/51/H/39-40/ALS, dated 5-8-74 for the import of Whisky and Brandy worth Rs. 367 to be obtained from bonded stock. They have applied for a duplicate copy of the C.C.P. on the grounds that the original CCP has been lost/misplaced. The original CCP was not registered with any Customs House and not utilized. I am satisfied that the original CCP No. G/J/3041311, dated 5-8-74 has been lost/misplaced and direct that a duplicate CCP should be issued to the applicant. The original C.C.P. is cancelled.

[No. GoV/5/AM-75/A.L.S./1647]

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1975

का०आ० 168.—सर्वश्री इनक्लाब डेली, 156-डी, तारदेव रोड, बम्बई-34, को 1,21,849, रुपए (एक लाख इक्कीस हजार आठ सौ उनचास रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1377223/आर/के के/47/एच/35-36, दिनांक 4-5-73 स्वीकृत किया गया था । उन्होने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिया खो गई/अस्थानस्थ हो गई है । आगे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास पजीकृत नही करवाई गई थी और उनमें 12-11-74 को 1,21,849 रुपए शेष था ।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने उप-पंजीयक महानगरीय मजिस्ट्रेट कोर्ट एस्प्लेनेड इस्टेट, बम्बई, द्वारा एक प्रमाण-पत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मै तदनुसार संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन एंव मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं । इसलिए यथा, संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उप-धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर सर्वश्री इनक्लाब डेली बम्बई को जारी किए लाइसेंस सं०पी/ए/1377223/आर/के के/47/एच/35-36, दिनांक 4-5-73 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती हैं ।

3 लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं ।

[संख्या 3-I/67-5/72-73/एन पी एस०]

जे० शकर, उपमुख्य नियंत्रक ।

ORDER

New Delhi, the 3rd January, 1975

S.O. 168.—M/s. Inquilab Daily, 156-D, Tardes Road, Bombay-34, were granted an import licence No. P/A/1377223/R/KK/47/H/35-36, dated 4-5-73 for Rs. 1,21,849 (Rupees One lakh twenty one thousand eight hundred & forty nine only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes/Exchange Control Purposes copies of the said licence on the ground that the original Customs Purposes/Exchange Control Purposes copies have been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes/Exchange Control copies were not registered with the Customs authorities and therefore the balance available on them was Rs. 1,21,849/- as on 12-11-74.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from the Deputy Registrar, Metropolitan Magistrate Court, Esplanade, Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes and Exchange Control Purposes copies of the said licence have been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended the said original Customs Purposes and Exchange Control Purposes copies of licence No. P/A/1377223/R/KK/47/H/35-36, dated 4-5-73 issued to M/s. Inquilab Daily, Bombay are hereby cancelled.

3. Duplicate Customs Purposes/Exchange Control Purposes copies of the said licence are being issued separately to the licensee.

[No. 3-I/67-V/72-73/NP Sec.]

J. SHANKAR, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1975

का०आ० 169.—श्रीमती तेज कोहली, स्टेट हास्पिटल, अकूरी, पश्चिमी नाईजीरिया (यू०आर०टी०ई०जे०सी०—62, फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली) को वाल्वो-144 (1342) कार, शैसी स० 391426 के आयात के लिए 30,000/- रुपये मूल्य का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट स० पी०/जे०/3046434/एन/एन पी/51/एच/39-40, दिनांक 24-4-74 प्रदान किया था। उसने सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि के लिये आवेदन किया है कि क्योंकि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया है ।

इस तर्क के समर्थन में श्रीमती तेज कोहली ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । उसने सीमाशुल्क निकासी परमिट यदि बाद मे पाया जाए तो उसको इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देने का वचन दिया है । मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/ 304-6434/एन/एन पी/51/एच/39-40 दिनांक, 24-4-74 खो गया है और निदेश देता हूं कि इसकी अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट रद्द किया गया समझा जाए।

[फ०संख्या 2(बी-242)/73-74/बी एल एस/3215]

ह०/-अपठ

उप-मुख्य नियंत्रक ।

ORDER

New Delhi, the 2nd January, 1975

S.O. 169.—Mrs. Tej Kohli, State Hospital, Akure, W. Nigeria, (URTEJ, C-62, Friends Colony, New Delhi), was granted Custom Clearance Permit No. P/I/304643/N/MP/51/H/39-40 dated 24-4-74 for Rs. 30,000 for import of a Volvo-144(1342) Car, Chassis No. 391426 has applied for a duplicate copy of the Custom Clearance Permit as the original C.C.P. has been lost. It is further stated that the original C.C.P. was not registered with any Custom House and not utilised.

In support of this contention Mrs. Tej Kohli has filed an affidavit. He has undertaken to return the C.C.P. if traced later to this office for record. I am satisfied that the original C.C.P. No. P/J/3046434/N/MP/54/H/39-40, dated 24-4-74 has been lost and direct that a duplicate C.C.P. should be issued to her. The original Custom Clearance Permit may be treated as cancelled.

[F. No. 2 (B-242)/73-74/BLS/3215]

Sd/- Illegible
Dy. Chief Controller.

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1975

का० आ० 170.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन् चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी०एम०एल०-535, 557, 639, 1171 और 1407 जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए है, लाइसेंसधारी द्वारा अपना नाम मैसर्स पावर केबल्स प्राइवेट लि० से बदल कर मैसर्स अपार प्राइवेट लिमिटेड कर लेने के कारण 16 नवम्बर, 1974 से रद्द कर दिए गए हैं।

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी०एम०/एल०-535 30 अप्रैल, 1963	मैसर्स पावर केबल्स प्राइवेट लि०, विट्ठलवाड़ी, कल्याण (महाराष्ट्र)	पी०वी०सी० रोधित केबल, केवल एलुमिनियम चालकों वाले, 250/440 वोल्ट और 650/1100 वोल्ट ग्रेड— मार्का :—"इंसुलास्ट"	IS 694 (भाग 2)—1964 पी० वी० सी० रोधित केबल की विशिष्ट (1100 वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए) की विशिष्ट, भाग 2 एलुमिनियम चालक— (पुनरीक्षित)
2.	सी०एम०/एल०-557 2 जुलाई, 1963	,,	पूर्ण एलुमिनियम चालक और इस्पात प्रबलित एलुमिनियम चालक—	IS : 398—1961 शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए सख्त खिचे लड़दार एलुमिनियम और इस्पात/की कोर वाले एलुमिनियम चालको की विशिष्टि (पुनरीक्षित)
3.	सी०एम०/एल-639 27 फरवरी, 1964	,,	पी०वी०सी० रोधित (भारी ड्यूटी) 1100 वोल्ट और उससे तक कार्यकारी वोल्टता के लिए बिजली के केबल—	IS : 1554(भाग 1)—1964 पी०वी० सी० रोधित (भारी ड्यूटी) 1100 वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए बिजली के केबलो की विशिष्टि (पुनरीक्षित)
4	सी०एम०/एल०-1171 6 दिसम्बर, 1965	,,	शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए इस्पात की कोर वाले एलुमिनियम चालकों के कोर के लिए इस्पात के तार—	IS : 398—1961 शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए सख्त खिचे लड़दार एलुमिनियम और इस्पात की कोर वाले एलुमिनियम चालको की विशिष्टि (पुनरीक्षित)
5.	सी०एम०/एल०-1407 14 मार्च, 1967	,,	पोलीइथाइलीन रोधित और पी०वी० सी० खोल वाले केवल एलुमिनियम चालको वाले इकहरी कोर और दुहरे खपटे वाले— मार्का. "इंसुलास्ट"	IS : 1596—1970. 250 वोल्ट तक की वोल्टता के लिए पोलीइथाइलीन रोधित और पी०वी०सी० खोल वाले केबलो की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)

[सी०एम०डी० / 55. 535 (इटी)]

ए० के० गुप्ता, कार्यकारी महानिदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 6th January, 1975

S.O. 170.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licences No. CM/L535 557, 639, 1171 & 1407 particulars of which are given below have been cancelled with effect from 16 November, 1974 due to change in licensee's name from M/s. Power Cables Private Ltd. to M/s. APAR Private Ltd :—

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licencee	Article/Process Covered by the Licences Cancelled	Relevant Indian Standard(s)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-535 30 April 1963	M/s. Power Cables Private Ltd., Vithalwadi, Kalyan (Maharashtra)	PVC insulated cables with aluminium conductors only, 250/440 volts and 650/1100 volts grade Brand —'INSULAST'	IS : 694 (Part II)-1964 Specification for PVC insulated cables (for voltages upto 1100 V) Part II with aluminium conductors (Revised)
2.	CM/L-557 2 July 1963	—do.—	All aluminium conductors and ACSR conductors.	IS : 398-1961 Specification for hard-drawn stranded aluminium and steel-cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes (Revised)
3.	CM/L-639 27 February 1964	—do.—	PVC insulated (heavy duty) electric cables for wroking voltages upto and including 1100 volts	IS : 1554 (Part I)-1964 Specification for PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages upto and including 1100 volts (Revised)
4.	CM/L-1171 6 December 1965	—do.—	Steel wire for the core of steel-cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes.	IS : 398-1961 Specification for hard-drawn stranded aluminium and steel-cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes (Revised)
5.	CM/L-1407 14 March 1967	—do.—	Polyethylene insulated and PVC sheathed cables, single core and twin flat with aluminium conductors. Brand : 'INSULAST'	IS : 1596-1970 Specification for polyethylene insulated and PVC sheathed cables upto and including 250 V (First Revision)

[CMD/55 : 535 (ET)]

A. K. GUPTA,
Acting Director General

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1974

का० आ० 171.—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 की संख्या 26) की धारा 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा के उड़ीसा संवर्ग के अधिकारी तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री के० एस० बावा को 3 अक्तूबर, 1974 के दोपहर के पहले से आगे और आदेश न होने तक के लिये भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के उनके अपने कर्तव्यों के अलावा निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है ।

[एफ० संख्या आई 12011/7/74-आ० का० अ० ए०]

आर० श्रीनिवासन, उप-सचिव

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 18th December, 1974

S.O. 171.—In exercise of the powers conferred by Section 8(1) of the National Cooperative Development Corporation Act, 1962 (No. 26 of 1962) the Central Government, in consultation with the National Cooperative Development Corporation, have appointed Shri K. S. Bawa, an Officer of the Orissa cadre of the Indian Administrative Service and Joint Secretary to the Government of India in the Department of Civil Supplies and Cooperation, as Managing Director of the Corporation w.e.f. the forenoon of the 3rd October, 1974 till further orders, in addition to his own duties as Joint Secretary to the Government of India.

[F. No. I. 12011/7/74-IWSU]
R. SRINIVASAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1974

का० आ० 172.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार कागज (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1974 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम कागज (उत्पादन का नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 है।

(2) यह 1 अगस्त 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2 कागज (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1974 में, खंड 6 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जायेगा—

'छूट देने की शक्ति केन्द्रीय सरकार, इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुये कि किसी विनिर्माता की सम्स्थापित क्षमता कागज की कतिपय विशिष्ट

किस्मों के विनिर्माण के लिये है या इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुये विनिर्माता खंड 3 में निर्दिष्ट कागज की किसी किस्म का, भारी खर्च करने के सिवाय, उसमें विनिर्दिष्ट सीमा तक उत्पादन नहीं कर सकता है, ऐसे विनिर्माता को, ऐसी अवधि के लिये, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, खंड 3 की किसी अपेक्षा से पूर्णत या भागत छूट दे सकती है।'

'कागज (उत्पादन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974' के साथ सम्मिलित व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कागज की जो एक आवश्यक वस्तु है, सप्लाई बनाये रखने तथा उसे बढ़ाने के लिये कागज (उत्पादन नियंत्रण) आदेश, 1974 नामक एक आदेश 1 अगस्त, 1974 को जारी किया है।

2. इस आदेश के अन्तर्गत कागज के सभी निर्माताओं को किन्तु ऐसे निर्माताओं को छोड़कर जो 1 अगस्त, 1974 को अथवा से, तथा 1 अक्तूबर, 1974 को अथवा से प्रारम्भ होने वाली प्रत्येक तिमाही में 20 मीट्रिक टन या इससे कम प्रतिदिन कागज तथा गत्ता बनाते है, निम्नलिखित किस्मों का कागज नीचे दिये गये ब्यौरे के निम्नतम प्रतिशत के अनुसार कागज का उत्पादन करना अपेक्षित था।

क्रमांक	कागज की किस्म	महीनों/तिमाही में हुये उत्पादन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत
1	छपाई का सफेद कागज	30%
2.	क्रीम वक्ष अथवा जूट का कागज (मोम पेपर)	16%
3.	छपाई का रंगीन कागज	1.5%
4	डुप्लीकेटिंग कागज	2.5%
5	आफसैट तथा लीथो कागज	6.5%
6.	टाइप का कागज	0 5%

3. उक्त आदेश के खंड 5 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जहां उपर्युक्त प्रतिशत के अनुसार किसी भी निर्माता के पास कागज बनाने की पर्याप्त अधिष्ठापित क्षमता न हो, वहां उपर्युक्त प्रतिशतता में किस प्रकार समायोजन किया जाये। आदेश का खंड 6 केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि उन मामलों में जिनमें उपर्युक्त आदेश के खंड 3, उपखंड (क) में बताये गये छपाई के सफेद कागज के मामले में किसी निर्माता की अधिष्ठापित क्षमता किसी विशिष्ट प्रकार के कागज बनाने की हो अथवा जहां कोई निर्माता अधिक लागत लगाये बिना निर्दिष्ट प्रतिशत में छपाई का सफेद कागज नहीं बना सकता है वहां केन्द्र सरकार निर्माता को संपूर्ण अथवा उसके किसी अंश तक छूट दे।

4. जांच करने पर यह पाया गया कि ऐसे भी प्रकरण हो सकते है कि जहां किसी निर्माता को न केवल छपाई का सफेद कागज बनाने में छूट देना जरूरी होगा अपितु उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में दी गई बातों पर विचार करते हुये ऊपर दिये गये पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट किसी एक अथवा अन्य सभी किस्मों के कागज के बारे में भी छूट देना आवश्यक हो सकता है। अतएव विद्यमान संशोधन आदेश जारी किया जाता है।

चूंकि इस प्रकार दी जाने वाली छूटें भिन्न भिन्न प्रकार के कागज बनाने की अधिष्ठापित क्षमता से सम्बन्ध रखती है तथा उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रतिशत की प्राप्ति हेतु उत्पादन ढांचे में संशोधन करने से लगने वाली लागत अन्य प्रकार के कागज निर्माताओं पर भी समान रूप से लागू होगी है, अत: यह महसूस किया जाता है कि यह प्रमुख आदेश के प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् 1 अगस्त, 1974 से ही लागू होगा। और भी यदि संशोधन आदेश को भूतलक्षी न बनाया गया तो छपाई का सफेद कागज बनाने वालों को प्रमुख आदेश के प्रारम्भ होने तथा संशोधन आदेश के प्रारम्भ होने के बीच न मिलने वाला लाभ मिल जायेगा जो अन्य प्रकार के कागज निर्माताओं को उपलब्ध नहीं होगा।

[सं० 14(1)/74-कागज]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 1974

S.O. 172.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to amend the Paper (Control of Production) Order, 1974, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Control of Production) Amendment Order, 1974.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st of August, 1974.

2. In the Paper (Control of Production) Order, 1974, for clause 6, the following clause shall be substituted, namely :—

"6. Power to exempt.—The Central Government may, having regard to the fact that the installed capacity of a manufacturer is for the manufacture of certain specialised varieties of paper or to the fact that a manufacturer cannot produce any of the varieties of paper referred to in clause 3 to the extent specified therein except at a heavy cost, exempt such manufacturer from the whole or part of any of the requirements of clause 3 for such period as may be specified in the Order."

EXPLANATORY MEMORANDUM APPENDED TO THE "PAPER (CONTROL OF PRODUCTION) AMENDMENT ORDER, 1974"

In order to maintain and increase the supplies of paper, an essential commodity, the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) issued an order called the Paper (Control of Production) Order, 1974, on the 1st August, 1974.

2. Under this Order, all the manufacturers of paper excluding those who produce less than twenty tonnes of paper and paper boards per day were required to manufacture in every month commencing on and from 1st day of August, 1974 and every quarter commencing on and from the 1st October, 1974 a minimum percentage of their production in the following varieties of paper as per details given below :—

S.No.	Type of paper	Minimum percentage to be produced based on months quarterly production
1.	White Printing paper	30%
2.	Cream Laid or wove paper	16%
3.	Coloured printing paper	1.5%
4.	Duplicating paper	2.5
5.	Off-set and Litho paper	6.5%
6.	Typing paper	0.5%

3. Clause 5 of the said order specifies how the above percentages may be modified where the installed capacity of a manufacturer is not sufficient to manufacture paper according to the above percentages. Clause 6 of the order empowers the Central Government to exempt a manufacturer from the whole or part of the requirements of sub-clause (a) of clause 3 of the said order which lays down the percentage of manufacture of white printing paper in cases where the installed capacity of a manufacturer was for the manufacture of certain specialised varieties of paper or where a manufacturer cannot produce white printing paper to the specified percentage except at a heavy cost.

4. On examination it was found that there might be cases where it might be necessary to exempt a manufacturer not only from the manufacture of white printing paper but also of any or all of the other varieties of paper specified in paragraph 2 above having regard to the considerations mentioned in the paragraph 3 above. Hence the present amendment order. Since the exemptions to be given are related to the installed capacity for the manufacture of different types of paper and as the cost involved in modifying the pattern of production in order to achieve the percentages specified in paragraph 2 above will be applicable equally to the manufacturers of other types of paper also, it is felt that the amendment order should take effect from the date of commencement of the principal order that is, 1st August, 1974, Further, if the amendment Order is not made retrospectively, the manufacturers of white printing paper would get an unintended benefit from the commencement of the principal Order to the commencement of the amendment Order which would not be available to the manufacturers of other varieties of paper.

5. The retrospective operation of the amending Order is absolutely necessary and no one will be adversely affected by the retrospective operation of the amending Order.

[No. 14(1)/74-Paper]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1975

का० आ० 173.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन रोहतक कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड रोहतक द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर बायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त एक्सचेंज को गुड़ की अग्रिम संविदाओं के बारे में 28 दिसम्बर, 1974 से 27 दिसम्बर, 1975 (जिसमे ये दोनों दिन सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2 एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो बायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[सं० 12(24)—आई० टी०/74]

ए० एफ० कुटो, संयुक्त-सचिव

New Delhi, the 3rd January, 1975

S.O. 173.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Rohtak Krishna Trading Co. Ltd., Rohtak, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Company for a further period of one year from the 28th December, 1974 to the 27th December, 1975 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Company shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(24)-IT/74]

A. F. COUTO, Joint Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1974

का० आ० 174.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नागरीय विकास विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 544 तारीख 4 फरवरी, 1970 को अधिक्रान्त करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिकारियों को, सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टियों विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में क्रमशः अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

1	2	3
क्रम सं०	अधिकारी का पदनाम	सरकारी संस्थानों के प्रवर्ग और क्षेत्राधिकारा की स्थानीय सीमाये
1	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) (परिष्करण शाला प्रभाग) इण्डियन आयल भवन, जनपथ, नई दिल्ली।	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) (परिष्करणशाला और पाइपलाइन प्रभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्थान।
2	ज्येष्ठ कार्मिक और प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) (परिष्करणशाला प्रभाग), गोहाटी परिष्करण शाला, डाकघर नूनमाटी, गोहाटी (असम)।	असम राज्य के भीतर भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) (परिष्करण शाला और पाइपलाइन प्रभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्थान।
3	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) (परिष्करणशाला, प्रभाग) बरौनी परिष्करणशाला, जिला बेगुसराय बिहार।	बिहार राज्य के भीतर भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) परिष्करणशाला और पाइपलाइन प्रभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्थान।
4	मुख्य कार्मिक और प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) (परिष्करणशाला प्रभाग), गुजरात परिष्करणशाला, डाकघर जवाहरनगर, बड़ोदा।	गुजरात राज्य के भीतर भारतीय तेल निगम लि० (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) परिष्करण शाला और पाइपलाइन प्रभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्थान।

(1)	(2)	(3)
5	मुख्य कार्मिक और प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड), हल्दिया परिष्करणशाला परियोजना, डाकघर हल्दिया, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल ।	पश्चिमी बंगाल राज्य के भीतर भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) (परिष्करणशाला और पाइपलाइन प्रभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्थान ।
6	प्रबन्धक (प्रशासन और परिवहन), भारतीय तेल निगम लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड), 9 सैय्यद अमीर अली एवेन्यू, पार्क सर्कस, कलकत्ता ।	कलकत्ता शहर के भीतर भारतीय तेल निगम लि० (इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड), (परिष्करणशाला और पाइपलाइन प्रभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्थान ।
7	उपप्रबन्धक (प्रशासन और परिवहन), भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (इण्डियन आयल कारपोरशन लिमिटेड) परिष्करणशाला प्रभाग) 225-सी, डा०ऐनी बेसन्ट रोड, प्रभादेवी, बम्बई-25 ।	बम्बई शहर के भीतर भारतीय तेल निगम लिमिटेड, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (परिष्करणशाला और पाइपलाइन प्रभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्थान ।

(फा० सं० आई एम 11021/1/73-ओ०आर०-1)

बी०आर० भल्ला, अवर सचिव ।

Ministry of Petroleum & Chemicals
(Department of Petroleum)
New Delhi, the 13th December, 1974

S.O.—174.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development, Department of Works, Housing and Urban Development under S.O. No. 544 dated the 4th February, 1970, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below, being officers equivalent to the rank of gazetted officers of Government, to the estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duities imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of Jurisdiction
1	2	3
1.	Senior Administrative Officer, Indian Oil Corporation Limited (Refineries Division), Indian-Oil, Bhavan, Janpath, New Delhi	Public Premises under the administrative control of Indian Oil Corporation Limited (Refineries & Pipelines Division) within the Union territory of Delhi.
2.	Senior personnel and Administrative Officer, Indian Oil Corporation Limited (Refineries Division), Gauhati Refinery, P.O. Noonmati, Gauhati (Assam)	Public Premises under the administration control of Indian Oil Corporation Limited (Refineries and Pipelines Division) within the State of Assam.
3.	Senior Administrative Officer Indian Oil Corporation Limited (Refineries Division), Barauni Refinery, District Begusarai, Bihar.	Public Premises under the administrative control of Indian Oil Corporation Limited (Refineries & Pipelines Division) within the State of Bihar.
4.	Chief Personnel and Administrative Officer, Indian Oil Corporation Limited, (Refineries Division), Gujarat Refinery, P.O. Jawaharnagar, Baroda.	Public Premises under the administrative control of Indaian Oil Corporation Limited, (Refineries & Pipelines Division) within the State of Gujarat.
5.	Chief Personnel and Administrative Officer, Indian Oil Corporation Limited, Haldia Refinery Project, P.O. Haldia, District Midnapur, West Bangal	Public Premises under the Administrative control of Indian Oil Corporation Limited (Refineries & Pipelines Division) within the State of West Bengal.
6.	Manager (Administration and Transport) Imdian Oil Corporation Limited, 9, Sayed Amir Ali Avenue, Park Circus, Calcutta.	Public Premises under the administrative control of Indian Oil Corporation Limited (Refineries & Pipelines Division) within the city of Calcutta.
7.	Deputy Manager (Administration & Transport), Indian Oil Corporation Limited (Refineries Division) 254-C Dr. Annie Basant Road, Prabha Devi, Bombay-25.	Public Premises under the administrative control of Indian Oil Corporation Limited (Refineries & Pipelines Division) within the city of Bombay.

[F. No. IS-11021/1/73-OR-I]

B.R. BHALLA Under Secy,

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1974

का० आ० 175.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के-159 से सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध, कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी कथन करेगा क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

डी एम एस के–159 से सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला महसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	सेंटी ए आर ई
सैज	192	0	33	30
	कार्ट ट्रैक	0	01	53
	190/1	0	18	42
	190/3	0	11	34
	188/2	0	06	75
	188/3	0	06	85
	188/4	0	06	85
	कार्ट ट्रैक	0	01	72
	31/1	0	06	99
	30/1	0	07	62
	30/2	0	05	94
	30/3	0	07	46
	33/1	0	00	50
	28	0	30	97
	25/2/6	0	05	13
	कार्ट ट्रैक	0	02	97
	374/1	0	11	61
	375/1	0	10	70
	375/2	0	04	59
	378/1	0	01	00
	376/1	0	01	98
	376/3	0	08	55
	376/6	0	05	31
	376/7	0	05	76
	376/8	0	01	71
	377/1/डी	0	03	78
	कार्ट ट्रैक	0	02	06
	391/4	0	01	00
	391/3	0	01	00
	331	0	35	46
	530/4	0	03	60
	530/3	0	02	94
	530/2	0	03	00
	530/1	0	05	50
	533	0	18	38
	कार्ट ट्रैक	0	08	53
	668/1	0	70	62
	658	0	14	77
	657/3	0	03	55
	657/1	0	06	75
	655/2	0	08	91
	655/1	0	00	50
	653	0	07	67
	659/4/ए	0	01	10
	659/2	0	04	85
	654/1	0	01	00
	654/1	0	03	04
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	681/2	0	01	00
	681/1	0	11	01
	681/3	0	02	22
	681/4	0	02	50
	682	0	05	00
	686/4	0	02	59
	683	0	05	27
	688/5	0	02	02
	688/3	0	02	00
	688/1	0	03	62
	712	0	26	39

[सं० 12016/7/74-एल एण्ड एल/1]

New Delhi, the 27th December, 1974

S.O. 175.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. K-159 to CTF in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from D.S. No. K. 159, to CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluk : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are.	Cent Area
Saij	192	0	33	30
	Cart Track	0	01	53
	190/1	0	18	42
	190/3	0	11	34
	188/2	0	06	75
	188/3	0	06	85
	188/4	0	06	85
	Cart Track	0	01	72
	31/1	0	06	99

1	2	3		
	30/1	0	07	62
	30/2	0	05	94
	30/3	0	07	46
	33/1	0	00	50
	28	0	30	97
	25/2/6	0	05	13
	Cart Track	0	02	97
	374/1	0	11	61
	375/1	0	10	70
	375/2	0	04	59
	378/1	0	01	00
	376/1	0	01	98
	376/3	0	08	55
	376/6	0	05	31
	376/7	0	05	76
	376/8	0	01	71
	337/1/D	0	03	78
	Cart track	0	02	36
	391/4	0	01	00
	391/3	0	01	00
	531	0	35	46
	530/4	0	03	60
	530/3	0	02	94
	530/2	0	03	00
	530/1	0	05	50
	533	0	18	36
	Cart track	0	01	53
	668/1	0	07	62
	658	0	14	77
	657/3	0	03	55
	657/1	0	06	75
	655/2	0	08	91
	855/1	0	00	50
	653	0	07	67
	659/4/A	0	01	10
	659/2	0	04	85
	654/1/B	0	01	00
	654/1/C	0	03	04
	Cart track	0	01	00
	681/2	0	01	00
	681/1	0	11	01
	681/3	0	12	22
	681/4	0	02	50
	682	0	05	00
	686/4	0	02	59
	683	0	05	27
	688/5	0	02	02
	688/3	0	02	00
	688/1	0	03	62
	712/P	0	26	39

[No. 12016/7/74-L.&L./I]

का० आ० 176.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के-166 से सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

125 GI/74—4

अतः अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, ———— तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

डी० एस० संख्या के-166 से सी० टी० एफ० तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला: कलोल तालुका कलोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	सैंटी ए आर ई
सैज	230	0	12	82
	229	0	10	65
	203	0	19	06
	204/2	0	08	02
	198/2	0	12	23
	198/1	0	01	58
	204/1	0	09	30
	197	0	04	65

[सं० 12016/7/74-एल एण्ड एल/2]

S.O. 176.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. K-166 to C.T.F. in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from D.S. No. K-166 To CTF

State : Gujarat	District : Kalol	Taluka : Kalol		
Village	Survey No.	Hec-tare	Are.	Cent. Are.
Saij	230	0	12	82
	229	0	10	65
	203	0	19	06
	204/2	0	08	02
	198/2	0	12	23
	198/1	0	01	58
	204/1	0	09	30
	197	0	04	65

[No. 12016/7/74-L&L/II]

का० आ० 177—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे जी जी एस II से सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी० जी० एस०–II से सी० टी० एफ० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला: महसाना	तालुका : कलोल		
गांव	सर्वेक्षण सख्या	हैक्टर	ए आर ई	सेंटी ए आर ई
1	2	3	4	5
सैज	712/बी	0	01	90
	700/1	0	13	30
	वी पी कन्स	0	01	15
	696/2	0	05	70
	696/1	0	15	77
	697	0	09	05
	699	0	14	25
	1212	0	11	40
	1216	0	11	21
	1210/2	0	01	70
	1210/1	0	04	00
		0	01	90
	993	0	18	00
		0	20	00
	97/82	0	02	00
	980	0	15	00
	977	0	04	00
	976	0	19	00
	970	0	07	00
	971	0	00	50
	969	0	03	00

[सं० 12016/7/74-एल एण्ड एल/3]

S.O. 177.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. II to C.T.F. in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from GGS II To CTF

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kalol		
Village	Survey No.	Hec-tare	Are.	Cent Are.
Saij	712/1	0	01	90
	700/1	0	13	30
	V.P. Kana	0	01	15
	696/2	0	05	70
	696/1	0	15	77
	697	0	09	05

1	2	3	4	5
	699	0	14	25
	1212	0	11	40
	1216	0	11	21
	1210/2	0	01	70
	1210/1	0	04	00
	V.P. Kans	0	01	90
	993	0	18	00
	V.P.	0	20	00
	978/2	0	02	00
	980	0	15	00
	977	0	14	00
	976	0	19	00
	970	0	07	00
	971	0	00	50
	969	0	03	00

[No. 12016/7/74-L&L/III]

का० आ० 178 --यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे के- 34 से सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत', अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कुआं संख्या 34 कलोल से सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : महसाना तालुका कालोल

गांव	ब्लाक संख्या	हैक्टर	ए आर ई	सेन्टी ए आर ई
धर्मसाना	204	0	04	27
	203	0	03	07
	199	0	36	30
	198	0	07	20
	197	0	15	15
	काट ट्रैक	0	02	55
	323	0	01	05
	काट ट्रैक	0	00	50
	326	0	23	12
	328	0	09	90
	329	0	05	85
	330	0	05	55
	काट ट्रैक	0	01	05
	721	0	01	80
	720	0	06	23
	719/1	0	12	68
	718	0	12	02
	716	0	04	20
	715	0	13	73
	701	0	04	35
	काट ट्रैक	0	00	50
	700	0	15	15
	731	0	01	00
	698	0	01	00
	697	0	07	05
	696	0	10	28
	काट ट्रैक	0	00	60
	803	0	14	17
	804	0	13	43
	810	0	12	75
	811	0	05	10
	812	0	06	75
	827	0	15	33
	766	0	12	60
	527	0	10	35
	820	0	17	36
	831	0	14	72
गांव कलोल	सर्वेक्षण सं०			
	251/48	0	53	06
	काट ट्रैक	0	01	24
	251/6	0	02	70
	251/5	0	20	61
	251/4	0	03	56
	काट ट्रैक	0	02	09
	251/60	0	11	32
	251/67	0	16	52
	251/68	0	12	32
	251	0	05	35
	251/143	0	05	27
	252/30	0	05	04
	252/32	0	10	00
	252/34	0	09	07
	252/37	0	15	04
	252/40	0	09	30
	252/43	0	15	97
	232/44	0	01	00

1	2	3	4	5
	252/42	0	08	06
	232/43	0	08	38
	252/93	0	17	36
	262/94	0	09	00
	कार्ट ट्रैक	0	03	02
	252/172	0	11	70
	252/173	0	10	93
	252/174	0	01	00
	252/192	0	32	32
	252/194	0	01	00
	252/191	0	16	35
	252/190	0	14	39
	252/183	0	08	66
	252/200	0	03	50
	252/202	0	08	08
	कार्ट ट्रैक	0	01	16
	252/307	0	08	37
	252/306	0	06	51

[संख्या 12016/7/74-एल एण्ड एल/4]

S.O. 178.—Whereas it appears to the Central Government the it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d s. K-34 to CTF in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from Well No. 34 Kalol to CTF

State : Guarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are.	Centi Are.
1	2	3	4	5
Dhamasana	204	0	04	27
	203	0	03	07
	199	0	36	30
	198	0	07	20
	197	0	15	15
	Cart Track	0	02	55
	325	0	01	05
	Cart Track	0	00	50
	326	0	23	12
	328	0	09	20
	329	0	05	85
	330	0	05	55
	Cart Track	0	01	05
	721	0	01	80
	720	0	06	23
	719/P	0	12	68
	718	0	12	02
	716	0	04	20
	715	0	13	73
	701	0	04	35
	Cart Track	0	00	50
	700	0	15	15
	731	0	01	00
	698	0	01	00
	697	0	07	05
	696	0	10	28
	Cart Track	0	00	60
	803	0	14	17
	804	0	13	43
	810	0	12	75
	811	0	05	10
	812	0	06	75
	827	0	15	33
	766	0	12	60
	827	0	10	35
	829	0	17	36
	831	0	14	72
Village : Kalol	Survey No.			
	251/48	0	53	06
	Cart Track	0	01	24
	251/6	0	02	79
	251/5	0	20	61
	251/4	0	03	56
	Cart Track	0	02	09
	251/66	0	11	32
	251/67	0	16	52
	251/68	0	12	32
	251	0	05	35
	251/143	0	05	27
	252/30	0	05	04
	252/32	0	10	00
	252/34	0	09	07
	252/37	0	15	04
	252/40	0	09	30
	252/43	0	15	97
	252/44	0	01	00
	252/42	0	08	06
	252/45	0	08	38
	252/95	0	17	36
	252/94	0	09	00
	Cart Track	0	05	02
	252/172	0	11	70
	252/173	0	10	93
	252/174	0	01	00
	252/192	0	32	32
	252/194	0	01	00
	252/191	0	16	35
	252/100	0	14	89

1	2	3	4	5
	252/183	0	08	66
	252/200	0	05	50
	252/202	0	02	08
	Cart Track	0	01	16
	252/307	0	08	37
	252/306	0	06	51

[No. 12016/7/74-L&L/IV]

का० आ० 179.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के-159, 162 से सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बैरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कुओं संख्या 159, 162 के टी ई से सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य . गुजरात जिला . महसाना तालुका . कलोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	पी ए आर ई
1	2	3	4	5
कलोल	44	0	16	32
	कार्ट ट्रैक	0	01	50
	59	0	12	56
	58/1	0	06	24
	58/2	0	08	08
	56	0	09	92
	75	0	01	92
	73	0	40	78
	72	0	03	08
	कार्ट ट्रैक	0	01	76
	174/1	0	04	00
	174/2	0	08	00
	176	0	13	76
	177/1	0	10	24
	196	0	04	16
	195	0	16	96

[संख्या 12016/7/74-एल एण्ड एल/5]

S.O. 179.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. K-159, 162 to C.T.F. in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas, it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state separately whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For laying Pipeline from Well Nos. 159, 162 to CTF

State : Gujarat . District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are.	Centi Are.
Kalol	44	0	16	32
	Cart Track	0	01	50
	59	0	12	56
	58/1	0	06	24
	58/2	0	08	08
	56	0	09	92
	75	0	01	92
	73	0	40	78
	72	0	03	08
	Cart Track	0	01	76
	174/1	0	04	00
	174/2	0	08	00
	176	0	13	76
	177/1	0	10	24
	196	0	04	16
	195	0	16	96

[No. 12016/7/74-L&L/V]

का० आ० 180.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एस 120 (के०आई०जेड) से जी० जी० एस 1/11 तक पेट्रोलियम के परिवहन के

लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बरोडा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों की भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कुआं संख्या 120 (के आई जेड) से जी जी एस-1/11 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : गांधी नगर तालुका: गांधीनगर

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	पी ए आर ई
1	2	3	4	5
टिटोडा	597	0	07	67
	596	0	15	91
उवरसाद	1195/1	0	04	48
	1195/3	0	12	54
	1195/4	0	03	25
	1195/16	0	96	16
	1195/17 और 18	0	10	79
	1194/2	0	07	32
	1194/3	0	05	11
	1195/3	0	01	00
	1198	0	13	45
	1201/1	0	14	73
	1201/2	0	02	86
	1201/3	0	10	10
	1202	0	05	53
	1203	0	23	25
	1184/2	0	33	47
	1180/1	0	00	50
	1183/2	0	06	50
	1183/1	0	05	82
		0	00	52
	1147/1	0	06	69
	1147/2	0	15	56
	1148	0	16	80
	1145	0	01	04
	कार्ट ट्रैक	0	01	17
	1149/1	0	04	68
	कार्ट ट्रैक	0	00	52
	1109/1	0	12	98
	1108	0	03	00
	1107	0	04	16
	1110	0	04	16

[संख्या 12016/7/74-एल एण्ड एल/6]

पी०पी० गुप्ता, उप सचिव

S.O. 180.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. 120 (KIZ) to G.G.S. VII in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For laying Pipeline from Well No. 120 (KIZ) to GGS-VII

State : Gujarat District : Gandhinagar Taluka : Ghandinagar

Village	Survey No.	Hectare	Are.	Centare.
1	2	3	4	5
Titoda	597	0	07	67
	596	0	15	91
Uvarsad	1195/2	0	04	48
	1195/3	0	12	54
	1195/4	0	03	25
	1195/16	0	06	16
	1195/17 & 18	0	10	79
	1194/2	0	07	32
	1194/3	0	06	11
	1195/5	0	01	00
	1196	0	13	45
	1201/1	0	14	73
	1201/2	0	02	86
	1201/3	0	10	10
	1202	0	05	33
	1203	0	25	26
	1184/2	0	33	47
	1180/1	0	00	50
	1183/2	0	06	50

1	2	3	4	5
	1183/1	0	05	82
	Cart Track	0	00	52
	1147/1	0	06	69
	1147/2	0	15	56
	1146	0	16	80
	1145	0	01	04
	Cart Track	0	01	17
	1149/1	0	04	68
	Cart Track	0	00	52
	1109/1	0	12	98
	1108	0	03	00
	1107	0	04	16
	1110	0	04	16

[No 12016/7/74-L&L/VI]

P. P. GUPTA, Dy. Secy.

परमाणु उर्जा विभाग

आदेश

बम्बई, 9 दिसम्बर, 1974

का० आ० 181.—केन्द्रीय सरकार, परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33वा अधिनियम) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उस अधिकारी को, जिसका नाम तथा पदनाम नीचे दी गई अनुसूची मे दिया गया है, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 तथा 2 मे उल्लिखित प्रवेश एव निरीक्षण सम्बन्धी शक्तियों एव अन्य सभी शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

श्री ए० सी० सारस्वत, वैज्ञानिक अधिकारी (एस ई)

[फाइल सं० 1/2(2)/74-पीएमयू]

एस० जी० नायर, अवर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ORDER

Bombay, the 9th December, 1974

S.O. 181.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Atomic Energy Act, 1962 (Act No. 33 of 1962), the officer whose name and designations is given in the schedule is hereby authorised by the Central Government to exercise power of entry and inspection and all other powers as mentioned in sub-sections 1 and 2 of Section 8 of the Act

SCHEDULE

Shri A C Saraswat, Scientific Officer (SE)

[F. No 1/2(2)/74-PSU]

S G NAIR, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(शक्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 1974

का०आ० 182.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 133 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त नियमो के

(i) नियम 188 (क)
(ii) नियम 119 (1) (क)
(iii) नियम 118 (ग) और
(iv) नियम 123 (7)

के उपबंध, मैसर्स भिलाई स्टील प्लाट लिमिटेड की राझारा आयरन और माइन मे रूसी विद्युत शावेल के डिजाइनो की, मैसर्स एच० एम० बी० पी०, राची द्वारा प्रदाय किये गये 6 6 के० वी० ई० केटी 4 6 क्रम स० 10 विद्युत शावेल के सहयोजन मे निम्नलिखित उपकरण

1 एच आर सी फ्यूजिज और स्टार्टर 100 ए एम पी एस के साथ 6 6 के०वी० आईसोलेटर। शावेल पर लगाये गये 6 6 के० वी० रूसी चेक ।

2 250 कि० वा० 6 6 के० वी० 3 फेज एसी मोटर टाइप ए 3-113-4 टी भारत हेवी इलेक्ट्रीक मेक क्रम सं० 3002-4-ए3-1

3. सेकण्डरी ऊदासीन भूसपर्कित रूसी मेक क्रम स० 14553 टाइप टी एम-30/60 टी के साथ 30 के० वी० ए० 6.6 के० वी०/230 वी स्टार/स्टार ।

4. 6 6 ट्रासफार्मर के० वी० 100/5 ए एम पी एस पी/बी एच ओ ओ सी बी रूसी मेक (एफ एल पी के बिना) क्रम सं० 12411 से प्रदाय प्राप्त करने वाले 6.6 के० वी० के लिए रबड ने मढ़ी हुई 3X35X3X10 मिली० मी०2 कवचित लचीली केबल 250 मीटर 4-कोर के प्रयोग की बाबत, निम्नलिखित सीमा तक शिथिल किए जा सकेंगे कि मैसर्स भिलाई स्टील प्लांट लिमिटेड की राझारा आयरन और माइन मे ओपनकास्ट खान में (i) नियम 118(क) को शिथिल करके उत्खनित में सुवाह्य मोटर चालन जनक समुच्चय को 6.6 के० वी० पर प्रयोग किया जा सकेगा (ii) नियम 119 (1) (क) को शिथिल करके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले सवाह्य उत्खनित्र मे लगे होने के कारण, ऊर्जा को उच्च वोल्टता पर प्रयोग करने वाले सचित उपस्करो सहित 30 के० वी० ए० 6 6 के० वी०/230 वोल्ट स्टार/स्टार ट्रासफार्मर 3 फेज अचल उपकरण नही होगा, अर्थात् वह सुवाह्य होगा , (iii) नियम 118 (ग) को शिथिल करके शावेल के भीतर 30 के० वी० ए० 6 6 के० वी०/230 वोल्ट 3 फेज स्टार/स्टार ट्रासफार्मर क्रम स० 14553 टाइप टी एम-30/60 टी, सेकण्डरी उदासीन भूसपर्कित प्रकाश के प्रयोजनो के लिए आशयित प्रदाय पद्धति फेज और उदासीन के मध्य 133 वोल्ट पर प्रयोग की जा सकेगी , और (iv) नियम 123(7) को शिथिल करके, कवचित लचीला केस जो सम्भाई मे 250 मीटर से अनधिक होगा, सुवाह्य मशीन के साथ प्रयोग किया जा सकेगा और कि यह शिथिलीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगा :

1. लचीले केबल के लिए 6.6 के०वी० (का अमूसंपर्कित उदासीन) प्रदाय, स्वचालित ट्रिपिंग व्यवस्था तथा धारण संरक्षण सहित किया जाएगा ।

2. लचीले कवचित केबल के लिए 6 6 के वी का नियंत्रण करने वाले परिपथ खंडित्रों के ओवर करेंट ट्रिपस, सुवाह्य तीन, पर लगाए गए 6.6 के वी मोटर चालन जनक सेट के अनुमतांक के अनुसार होंगे ।

3. शावेल पर किए गए संस्थापन और वायरिंग भारतीय विद्युत नियम, 1956 के सुसगत उपबधो, विशेषतया नियम 115, 117, 131, 124 और 125 के अनुरूप होंगे ।

4. लचीले कवचित केबल, समुचित रूप से सरेखित अनुयोजक बक्सो या पूर्णतया परिवेष्टित सुरक्षित संलग्नो द्वारा, विद्युत प्रदाय पद्धति और मशीन से जोड़े जाएगे और जब मशीन प्रयोग मे नही होगी सब केबल निष्प्रभाव हो जाएगा ।

5. लचीले कवचित केबल सहित उत्खनित्र मशीन पर सम्यक सावधानी से कार्य किया जाएगा और चलाया जाएगा ताकि किसी विद्युत खराबी से होने वाले खतरे या उसके प्रयोग से बचा जा सके । उच्च वोल्टता साधित्र, परिपथ जिसमे चालन मोटर सम्मिलित है, का विद्युतरोधी का प्रतिरोध किसी समय भी 5 मेघो एमस से कम नहीं होगी ।

6. खनिज के प्रचालकों को, खतरे से बचने के लिए मशीन को दक्षता-पूर्वक और सम्यक् सावधानी से प्रचालन के लिए प्रशिक्षित और प्राधिकृत किया जाएगा ।

7. कवचित लचीले केबल को हुआ कोई नुकसान तुरन्त ठीक किया जाएगा । अस्थायी जोड़ वाले केबल का कभी प्रयोग नही किया जाएगा । केबल वल्कनीकृत जोड़ बनाए जाएंगे ।

8. धारा ग्राही छल्ला कक्ष में प्रवेश के लिए मैनहोल ढक्कन, यदि कोई हो, तालें और चाबी के अधीन बंद रखा जाएगा ।

परन्तु पूर्वोक्त शिथिलीकरण उसी समय तक विधिमान्य रहेगा जबकि उक्त मशीन प्रयोग में हो और ज्यो ही मशीन खान से बाहर निकाली जाए उप-निदेशक खान सुरक्षा (विद्युत) के द्वारा, केन्द्रीय सरकार को सम्यक सूचना दी जाएगी ।

यह शिथिलीकरण आदेश, किसी अन्य विधि जो लागू हो या किसी समय लागू होने वाली हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जारी किया जाता है और यदि सुरक्षा के हित में किसी समय आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित किया जा सकेगा या वापिस लिया जा सकेगा ।

[सं० ई एल-2-6(2)/74]

सुरेन्द्र प्रकाश जैन, उपनिदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1974

S.O. 182.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 133 of the Indian Electricity Rules, 1956, the Central Government hereby directs that the provisions of:

(i) Rule 118(a),

(ii) Rule 119(1)(a),

(iii) Rule 118(c) and

(iv) Rule 123 (7)

of the said rules shall be relaxed in respect of the use of the following apparatus in conjunction with 6.6 KV EKT-4.6 serial No. 10 electric shovel supplied by M/s. HMBP Ranchi on the designs of Russian Electric shovel at Rajhara Iron Ore Mine of M/s. Bhilai Steel Plant Ltd.

(1) 6.6 KV Isolator with HRC fuses and starter 100 amps. 6.6 KV USSR make installed on the shovel.

(2) 250 KW 6.6 KV 3 phase AC motor type A3-113-4T Bharat Heavy Electric make Sl. No. 3002-4-A3.

(3) 30 KVA 6.6 KV/230V star/star transformer with secondary neutral earthed USSR make Sl. No. 14553 type TM-30/60T.

(4) 250 metres 4-core armoured flexible cable $3\times35\times3\times10$ mm 2 rubber sheathed suitable for 6.6 KV receiving supply from 6.6KV 100/5 amps. PBHO OCB Russian make (without FLP) Sl. No. 12411.

in the opencast mine at Rajhara Iron Ore Mine of M/s. Bhilai Steel Plant Ltd., to the extent that (i) in relaxation of rule 118 (a), the portable motor driving generation set in the excavator may be used at 6.6 KV; (ii) in relaxation of rule 119 (1) (a), 30 KVA 6.6 KV/230V star/star transformer 3 phase with associated equipments using energy at high voltage may not be fixed apparatus as being installed on portable excavator moving from place to place, the same having portable sense; (iii) in relaxation of rule 118 (c), the system of supply intended for lighting purposes within the shovel from 30 KVA 6.6 KV/230V 3 phase star/star transformer Sl. No. 14553 type TM 30/60T with earthed secondary neutral may be used at 133 volts between phase and neutral; and (iv) in relxation of rule 123 (7), the armoured flexible case shall not be exceeding 250 metres in length may be used with portable machine and that this relaxation shall be subject to the following conditions:

1. The 6.6 KV (unearthed neutral) supply to the flexible cable shall be provided with earth leakage protection with automatic tripping arrangement.

2. The overcurrent trips of the circuit breakers controlling 6.6 KV supply to flexible armoured cable shall be in keeping with the rating of the 6.6 KV motor driving generator set installed on the portable machine.

3. The installation and wirings installed on the shovel shall comply with the relevant provisions of the Indian Electricity Rules, 1956 in particular rules 115, 117, 121, 124 and 125.

4. The flexible armoured cable shall be connected with the electric supply system and the machine by properly constructed connector boxes or totally enclosed safe attachments and cable shall be dead when machine is not in use.

5. The excavating machine alongwith the flexible armoured cable shall be worked and handled with due care so as to avoid danger arising out of any electrical defect or to the use. The insulation resistance of the high voltage apparatus, circuits including the driving motor shall at no time be less than 5 megohms.

6. The operators of the excavator shall be trained and authorised for operating the machine with competency and due care to avoid danger.

7. Any damage to the armoured flexible cable shall immediately be attended to and the same shall forthwith be replaced by cable in good condition. Cable with temporary joint shall never be used. Only volcanised joint shall be made.

8. The manhole covers, if any, for entry into the collector ring chamber shall be kept under lock and key.

Provided that the aforesaid relaxation shall be valid for such time as the said machine is in use and due information shall be given to the Central Government through the Deputy Director of Mines Safety (Electrical) as soon as the machine is taken out of the mine.

This relaxation order is being issued without prejudice to any other law which are applicable or may be applicable at any time and is liable to be amended or withdrawn at any time if considered necessary in the interest of safety.

[No. EL. II-6(2)/74]

S. P. JAIN, Dy. Director

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1974

का०आ० **183.**—यत: भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) के अनुसरण में डा०बी० राजगुरू प्रधानाचार्य बी०एस०एस० मेडिकल कालेज बुर्ला, जिला सम्बलपुर (उड़ीसा) विश्वविद्यालय द्वारा 28 अगस्त, 1974 से भारतीय चिकित्सा परिषद् के एक सदस्य चुने गये हैं ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59-एम 1 में एतद्द्वारा आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बदले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएं, नामत:—

"40. डा० बी० राजगुरू,
प्रधानाचार्य, बी०एस०एस० मेडिकल कालेज, बुर्ला,
जिला सम्बलपुर, उड़ीसा सम्बलपुर विश्वविद्यालय"

[सं०बी० 11013/1/74-एम०पी०टी० (सी)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 19th December, 1974

S.O. 183.—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. B. Rajguru, Principal, V.S.S. Medical College, Burla, District Sambalpur (Orissa) has been elected by the Sambalpur University to be a member of the Medical Council of India, with effect from the 28th August, 1974;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", for serial No. 40 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be substituted, namely :—

"40. Dr. B. Rajguru, Principal, V.S.S. Medical College, Burla, District Sambalpur (Orissa), Sambalpur University."

[No. V. 11013/1/74-MPT(C)]

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1975

का०आ० **184.** यत: दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (ङ०) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए नागालैण्ड राज्य सरकार ने नागा अस्पताल, कोहिमा के दन्त शल्य चिकित्सा डा०जे० एन० सिन्हा को 5 सितम्बर, 1974 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है ।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 17 अक्तूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या 3-2/62-चि० 2 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के खण्ड (ङ०)" के अन्तर्गत मनोनीत शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 15 पर उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय :

"डा० जे० एन० सिन्हा
दन्त शल्य चिकित्सा,
नागा अस्पताल, कोहिमा ।"

[सं० बी० 12013/1/74-एम० पी० टी०]

New Delhi, the 4th January, 1975

S.O. 184.—Whereas in pursuance of clause (c) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Dr. J. N. Sinha, Dental Surgeon, Naga Hospital, Kohima, has been nominated by the Government of the State of Nagaland, to be a member of the Dental Council of India, with effect from the 5th September, 1974 ;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 3-2/62-MII, dated the 17th October, 1962, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (c) of section 3", against serial No. 15, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. J. N. Sinha,
Dental Surgeon,
Naga Hospital,
Kohima."

[No. V. 12013/1/74-MPT]

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1975

का०आ० **185.** यत: भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 27 मार्च, 1962 की अधिसूचना सं० 16-15/61-चि०-1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए "लाइसेनसिआडो-एन-मेडिसिना सिरुगिया' यूनिवर्सिटी आफ वेलेन्सिया (स्पेन) द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी;

और यत: डा० पेरेडा अर्टिज डे जारते अमालिया को जिसके पास उक्त अर्हता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल नजरिथ अस्पताल, शिलांग असम के साथ सम्बद्ध है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (i) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा —

(1) 13 अक्तूबर, 1974 से दो वर्ष की अवधि,

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० परेडा अर्टिज डे जारते,

अमलिया, नजरिथ अस्पताल, शिलांग (असम) के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमे पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे ।

[सं० वी० 11016/21/74-एम०पी०टी०]

सती नायर, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th January, 1975

S.O. 185.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-15/61-MI, dated the 27th March, 1962, the Central Government has directed that the medical qualification, "Licenciado en Medicina Cirngia" granted by the University of Valencia (Spain) shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Pereda Ortiz Zarate Amalia who possesses the said qualification is for the time being attached to the Nazareth Hospital, Shillong (Assam) for the purposes of charitable work:

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies:—

(i) a further period of two years with effect from the 13th October, 1974, or

(ii) the period during which Dr. Pereda Ortiz de Zarate is attached to the said Nazareth Hopital, Shillong (Assam), whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/21/74-MPT]

MRS. SATHI NAIR, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1975

का० आ० 185.—यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जोन डी-3 (कर्जन रोड क्षेत्र) के जोनल डवैल्पमैंट प्लान में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया है:—

संशोधन :

"लगभग 1137.111 वर्ग मीटर (1360 वर्ग गज) का क्षेत्र जो उत्तर में आवासीय क्षेत्र, पूर्व में सर्विस लेन, दक्षिण मे सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र तथा पश्चिम में तानसेन मार्ग द्वारा घिरा हुआ है, इसे अब 'आवासीय' से 'सामाजिक सास्कृतिक संस्थाओं के उपयोग' मे परिवर्तन करने का प्रस्ताव है"।

प्रस्तावित संशोधन भारतीय गजट के पृष्ठ सं० 1856 नोटिस सं० एस०ओ० 1811 भाग II—धारा 3—उपधारा (ii) दिनांक 20-7-74 के अनुसार जो दिल्ली डिवैल्पमेंट एक्ट 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 11ए की उपधारा (3) के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव मांगने के लिये प्रकाशित किया गया है ।

तथा जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में उक्त संशोधन के सबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

अत अब दिल्ली विकास प्राधिकरण को उक्त एक्ट की धारा 11ए की उपधारा (i) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जोन-डी-3 (कर्जन रोड क्षेत्र) के जोनल डवैल्पमेंट प्लान में उक्त संशोधन किया जाता है ।

[सं० एफ० 9(10)/71-एम०पी०]

एच० एन० फोतेदार, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 18th January, 1975

S.O. 186.—Whereas the Delhi Development Authority has proposed to make the following modification in the zonal development plan for zone D-3 (Curzon Road area):—

MODIFICATION :

"An area measuring about 1137.111 sq. metres (1360 sq. yds.) surrounded by residential area in the north, service lane in the east, social and cultural area in the south and Tansen Marg in the west, is proposed to be changed from 'residential' to 'social-cultural institutional use'.

The proposed modification having been published as notice No. S.O. 1811 dated the 20th July, 1974 at page 1856 of the Gazette of India, Part II—Section 3—sub-section (ii) dated the 20th July, 1974 as required by Sub-section (3) of section 11A of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) inviting objections and suggestions;

And whereas the Delhi Development Authority has received no objection in regard to the modification mentioned above;

Now, therefore, the Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the said Act hereby makes the above modification in the said zonal development plan for zone D-3 (Curzon Road area).

[No. F. 9(10)/71-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1974

का० आ० 187.—निम्नलिखित कतिपय नियम प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खली श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1962 को अधिक्रान्त करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

जो आपत्ति या सुझाव उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किए जाएंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—इन नियमों का नाम वनस्पति खली (पैरी गई या विलायक निस्सारित) श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1974 है ।

2. परिभाषा:—इन नियमों में,—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ।

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. श्रेणी अभिधान:— (पैरी गई या विलायक निस्सारित) खली की क्वालिटी उपवर्णित करने वाले श्रेणी अभिधान वे होंगे जो अनुसूची 2 क से 9 ख के स्तंभ 1 में उपवर्णित हैं ।

4. क्वालिटी की परिभाषा :— श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित की गई क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 2 क से 9 ख तक में के प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित है ।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न :— श्रेणी अभिधान चिह्न में एक लेबल होगा जिस पर अनुसूची (i) में उपवर्णित नमूना होगा और उसमें श्रेणी अभिधान, खली का नाम तथा यह पैरी गई है या विलायक निस्सारित है या नहीं, विनिर्दिष्ट होंगे ।

6. चिह्नन की पद्धति:— (i) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक आधार पर सुरक्षित रूप से उस रीति में चिपकाया जाएगा या उस पर स्टेंसिल किया जाएगा जो कृषि विपणन सलाहकार अनुमोदित करे और उसमें कृषि विपणन सलाहकार द्वारा पैकर को जारी किए गए प्राधिकरण प्रमाणपत्र का संख्यांक भी दर्शाया जाएगा ।

(ii) इसके अतिरिक्त प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः और अमिट रूप से चिह्नित की जाएंगी :—

(क) लाट संख्यांक

(ख) पैकर का नाम,

(ग) पैकिंग की तारीख ;

(iii) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, आधान पर अपना निजी व्यापार चिह्न उस रीति में चिह्नित कर सकेगा जो उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, परन्तु निजी व्यापार चिह्न से खली की उस क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी न व्यक्त हो । जो इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित की गई है ।

7. पैकिंग की पद्धति :—(1) खली केवल साफ, शुष्क और मजबूत जूट के आधानों में ही बन्द की जाएगी । ये कीट, बाधा या फफूंद दूषण से मुक्त होंगे और अवांछनीय गन्ध से भी मुक्त होंगे ।

(ii) प्रत्येक आधान मजबूती से बन्द किया जाएगा और सील किया जाएगा और उसमें एक व्यापार वर्णन तथा एक श्रेणी अभिधान की खली ही होगी ।

8. प्राधिकरण प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें — साधारण श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1937 के नियम 4 के विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें इन नियमों के प्रयोजनों के लिए जारी किए गए प्राधिकरण प्रमाणपत्र के लिए शर्तें भी होंगी, अर्थात्:—

(i) प्रत्येक प्राधिकृत पैकर एरण्डी के बीज और एरण्डी की खली के साथ खली की मिलावट की रोकथाम के लिए सभी पूर्वावधानियां बरतेगा ।

(ii) यदि प्राधिकृत पैकर उन्हीं परिसरों में एक से अधिक प्रकार की खली का कार्य करता है तो वह विभिन्न खलियों की मिलावट की रोकथाम के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां बरतेगा । परिसर साफ एवं स्वास्थ्यकर होने चाहिए और उन्हें कालिक रूप से धुवारित किया जाना चाहिए ।

(iii) प्राधिकृत पैकर खलियों के परीक्षण के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं और नमूनों के विश्लेषण का उचित अभिलेख भी रखेगा ।

(iv) नमूना बनाने और विश्लेषण करने, पैकिंग और चिह्नन और अभिलेख रखने की पद्धतियों के बारे में सभी अनुदेशों का, जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, अनुपालन किया जाएगा ।

(v) उस रीति में जैसा कि कृषि विपणन सलाहकार विहित करे, प्रत्येक लाट से खली का नमूना ऐसी नियंत्रण—प्रयोगशाला को अग्रेषित किया जाएगा जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए ।

अनुसूची I

(नियम 5 देखिए)

लेबलों के लिए श्रेणी अभिधान चिह्न

(केवल भारत का मानचित्र अधिसूचित किया जाएगा)

अनुसूची II (क)

(नियम 3 और 4 देखिये)

मुंगफली की खली (पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	8.0	50.0	8.0	9.0	7.0	1.5	कुछ नहीं	(1) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की खली केवल छिलके रहित मूंगफली की पैदावार होगी जो बिजली चालित मशीनरी द्वारा पेरने के बाद प्राप्त की जाती है।
स्वच्छ	8.0	50.0	5.0	9.0	7.0	2.0	कुछ नहीं	(2) धानी खली केवल छिलके रहित मूंगफली की पैदावार होगी जो पशुचालित धानी या चक्की के द्वारा तेल पेरने के बाद प्राप्त की जाती है।
धानी खली	10.0	45.0	10.0	9.0	7.0	2 5	कुछ नहीं	(3) पदार्थ दृढ़ बनावट का होगा। (4) यह हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगी। (5) यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और किण्वित, सड़त या अन्य आपत्तिजनक गन्ध से मुक्त होगी। (6) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पणी :—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-चारे के रूप में छिलके रहित मूंगफली की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया। (आई० एस० 1713-1960)

अनुसूची II (ख)

(नियम 3 और 4 देखिए)

मूंगफली की खली (विलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन (6 25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8
अच्छी	10 0	51.0	1 0	10 0	2.5	कुछ नहीं	(1) विलायक निस्सारित मूंगफली की खली (मील) एक्सपैलर या घानी से पैरी गई मूंगफली की खली से विलायक के साधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी।
स्वच्छ	10 0	47 0	1 5	12 0	2 5	कुछ नहीं	(2) मील कुछ प्रारम्भिक शोधन के बाद सीधे मूंगफली के बीजों से भी प्राप्त की जा सकती है निस्सारण के लिए काम में लाई जाने वाली एक्सपेलर या घानी से पैरी गई मूंगफली की खली साफ व ठोस मूंगफली (आरकिस हेपोजिया—एस) के पैरने से प्राप्त की गई होगी। प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने और विलायक के लेशों हटाने के लिए मील नियंत्रित और विनियमित दशाओं के अधीन ऊष्मा और भाप शोधन के अधीन रखी जाएगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी या दोनों महुवा की खली से मुक्त होगा। यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और सडन दुर्गन्ध से मुक्त होगी।

टिप्पणी. (1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन—चारे के रूप में विलायक निस्सारित मूंगफली की खली (मील) के लिए भारतीय मानक विनिर्दिष्ट से लिया गया। (आई०एस० 3441–1966)

(2) निस्सारण के लिए विलायक—निस्सारण के प्रयोजनों के लिए केवल फूड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जाएगा।

विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी–

क्वथन बूरी 63° से० से 71 से० तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम) 1 प्रतिशत

आघाष्पशील तत्व (अधिकतम) 0 00 ग्राम। 100 मी०लि०

अनुसूची III क

(नियम 3 और 4 देखिए)

छिलके रहित बिनौले की खली– (पैरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन नाइट्रोजन (6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	8 0	40 0	8 0	10 0	7.0	1 5	कुछ नहीं	(1) केवल साफ बिनौले की पैदावार होगी मूलरूप से गिरी के साथ छिलके और रेशे के उन अपरिहार्य प्रभागों से बनी हो जो तेल विनिर्माण के समय छूट गए हों।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वच्छ	8.0	41.0	5.0	12.0	8.0	2.0	कुछ नहीं	(2) पदार्थ ठोस होगा लेकिन घृढ़ बनावट का न हो।
नं० 2	8.0	37.0	5.0	14.0	9.0	2.5	कुछ नहीं	(3) यह हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली व भूसी से मुक्त होगी।
								(4) यह खटवास, अपमिश्रण कीट या फफूंदबाधा और किण्वित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी।
								(5) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पणी– स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित हैं।

पशुधन-चारे के रूप में बिनौले की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया (आई०एस० 1712–1960)

अनुसूची III ख

(नियम 3 और 4 देखिए)

छिलके सहित बिनौले की खली (पैरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथरी सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख की प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख की प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	10.0	24.0	7.0	24 0	9.0	2.5	कुछ नहीं	(1) केवल साबूत, साफ और जहां कहीं आवश्यक है (विशेष कर रोयेदार बीज की दशा में) बिनौले से तेल निकालने के बाद प्राप्त पैदावार होगी।
								(2) पदार्थ ठोस होगा लेकिन घृढ़ बनावट न हो।
स्वच्छ	10.0	24.0	7.0	28.0	9.0	2.5	कुछ नहीं	(3) यह हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली और भूसी से मुक्त होगी।
								(4) यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और किण्वित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी।
								(5) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पणी:—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित हैं।

पशुधन-चारे के रूप में बिनौले की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया (आई०एस० 1712–1960)

अनुसूची III ग

(नियम 3 और 4 देखिए)

छिलके रहित बिनौले की खली (मील)—(विलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन (6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	8.0	42.0	1.5	12.0	2.0	विलायक निस्सारित बिनौले की खली (मील) छिलके रहित बिनौले की खली से विलायक के साधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। मील कुछ प्रारम्भिक शोधन के बाद सीधे छिलके रहित बिनौले से भी प्राप्त की जा सकती है। निस्सारण के लिए काम में लाई जाने वाली बिनौले की खली साफ और ठोस छिलके रहित बिनौले के पेरने से प्राप्त की गई होगी। विलायक के रेशे हटाने के लिए मील नियंत्रित और विनियमित दशाओं के अधीन ऊष्मा और भाप शोधन के अधीन रखी जाएगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी या दोनों और महुवा की खली से मुक्त होगा। यह सड़ने दुर्गन्ध से मुक्त होगी।
स्वच्छ	8.0	40.0	2.0	14.0	2.5	

टिप्पण :—1. स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगठित हैं।

पशुधन-चारे के रूप में विलायक निस्सारित बिनौले की खली (मील) के लिए आपत्तिकालीन भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया (आई० एस 3592 ई०—1966)

2. निस्सारण के लिए विलायक :—निस्सारण के प्रयोजनों के लिए केवल हैक्सेर-फूड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जाएगा। विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

क्वथन दूरी—63° से० से 71° से० तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम) 1 प्रतिशत

अवाष्पशील तत्व (अधिकतम 0.001 ग्राम/100 मि० लि०

अनुसूची IV क

(नियम 3 और 4 देखिए)

अलसी की खली (मील)—(पैरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.65) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	
अच्छी	10.0	29.0	8.0	10.0	8.0	1.5	कुछ नहीं	(1) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की खली बिजली चालित मशीनरी द्वारा अलसी के बीजों से तेल पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वच्छ	10.0	29 0	8.0	10.0	8.0	1.5	कुछ नहीं	(2) घानी खली पशुचालित घानी द्वारा अलसी के बीज से तेल पैरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी । (3) पदार्थ हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगा ।
पानी खली	10.0	26.0	15.0	6.0	9.0	2.5	कुछ नहीं	(4) यह खटवास, अपमिश्रण कीट या फफूंद बाधा और किण्वित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी । (5) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी ।

टिप्पण :—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है ।

पशुधन चारे सू रूप में अलसी की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया । (आई० एस०—1935-1961)

अनुसूची V ख

(नियम 3 और 4 देखिए)

अलसी की खली (मील)—(विलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	10.0	33 0	1 0	9.0	2 5	विलायक निस्सारित अलसी की खली (मील) एक्सपैलर या घानी से पेरी गई अलसी की खली से विलायक के साधनों द्वारा तेल निस्सारिण से प्राप्त की जाएगी । मील कुछ प्रारम्भिक शोधन के बाद सीधे अलसी के बीज से भी प्राप्त की जा सकती है। निस्सारण के लिए काम में लाई जाने वाली एक्सपैलर या घानी से पैरी गई अलसी की खली साफ और ठोस अलसी (लिनूम यूसीटेटीस्सीमम् एल०) पैरने से प्राप्त की गई होगी । प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने और विलायक के लेशे हटाने के लिए मील नियन्त्रित और विनियमित दशाओं के अधीन ऊष्मा और भाप शोधन के अधीन रखी जाएगी । पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी या दोनों या महुवा की खली से मुक्त होगा । यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद बाधा और सड़न दुर्गन्ध से मुक्त होगी ।
स्वच्छ	10.0	29.5	1.5	11.0	2.5	

टिप्पण —(1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित हैं ।

पशुधन-चारे के रूप में विलायक निस्सारित अलसी की खली (मील) के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया (आई० एस० : 3440-1966)

(2) निस्सारण के लिए विलायक :—निस्सारण के प्रयोजनों के लिए केवल हेक्सेन—फुड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जाएगा ।

विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

क्वथन दूरी———————63° से० से 71° से० तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम)————1 प्रतिशत

अवाष्पशील तत्व (अधिकतम) 0 001 ग्राम / 100 मि० लि०

अनुसूची V क

(नियम 3 और 4 देखिए)

*सरसों की खली—(पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेसे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अमल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	10.0	35.0	8.0	9.0	8.0	1.5	कुछ नहीं	(1) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की खली बिजली चालित मशीनरी द्वारा सरसों के बीज से तेल पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी
स्वच्छ	10.0	37.0	5.0	10.0	9.0	2.0	कुछ नहीं	(2) धानी की खली पशु चालित या कोल्हू द्वारा सरसों के बीज से तेल पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी
घानी खली	12.0	33.0	12.0	7.0	8.0	2.5	कुछ नहीं	(3) पदार्थ आर्जीमोन और एरण्डी की खली या भूसी सहित हानिकारक अवयवों से मुक्त होगा। (4) यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और किण्वित, गडन या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (5) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

*सरसों के बीज शब्द के अन्तर्गत राई (ब्रेसिका जन्सिया कास) सरसों (ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैराइटी सरसों), तोरिया (ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैराइटी तोरिया) और तारामिरा) एरुका स्टाइवा) आते हैं।

अनुसूची V ख

(नियम 3 और 4 देखिये)

सरसों की खली—(विलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेसे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	10.0	45.0	1.0	11.0	1.8	विलायक निस्सारित सरसों की खली (मील) अवचालित एक्सपेलर या घनी से पेरी गई खली से विलायक के साधनो द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। मील प्रारम्भिक शोधन के बाद सीधे ठोस सरसो के बीज (राई-ब्रेसिका जन्सिया), सरसों (ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस), तोरियां (ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस) और तारामिरा (एरुका सेटाइवा)

स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-चारे के रूप मे सरसों और तोरिया की खली के लिये भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया (आई० एस० 1932-1961)

अनुसूची 6क

(नियम 3 और 4 देखिये)

सेसमम (तिल) की खली (पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटिन (नाइट्रोजन 6.25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	10.0	37.0	8.0	7.0	13.0	1.5	कुछ नहीं	(1) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की खली बिजली चालित मशीनरी द्वारा सेसम्म (तिल) के बीज से तेल पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी।
स्वच्छ	10.0	37.0	5.0	7.0	13.0	2.0	कुछ नहीं	(2) घानी की खली पशु चलित घानी द्वारा सेसम्म (तिल) बीजों से तेल पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी।
घानी खली	10.0	36.0	14.0	7.0	13.0	2.0	कुछ नहीं	(3) पदार्थ हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगा। (4) यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद बाधा और किण्वित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (5) यह धूल या बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पण :—स्तम्भ 3 से 7 तक मे निर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-चारे के रूप में सेसम्म (तिल) की खली के लिये भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया। (आई० एस० : 1934–1961)

1	2	3	4	5	6	7
स्वच्छ	10.0	43.0	1.5	12.0	2.3	से भी प्राप्त की जा सकती है; प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने और विलायक के लेशे हटाने के लिये कोटक नियंत्रित और विनियमित दशाओं के अधीन ऊष्मा और भाप शोधन के अधीन रखी जायेगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी या दोनों या महुवा की खली या आर्जीमोन की खली से मुक्त होगा। यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद बाधा और सड़न दुर्गन्ध से मुक्त होगी।

टिप्पणी :—(1) स्तम्भ 3 से 6 तक विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणीत हैं।

भारतीय मानक संख्या विनिर्देश से नहीं लिया गया।

(2) निस्सारण के लिये विलायक. निस्सारण के प्रयोजनों के लिये केवल हैक्सेन—फूड श्रेणी का काम मे लाया जायेगा।

विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

क्वथन दूरी——————63° से० से 71° से० तक

ऐरोमैटिक तत्व (अधिकतम)——————1 प्रतिशत

अवाष्पशील तत्व (अधिकतम)——————0.011 ग्राम । 100 मि० ली०

अनुसूची 6 क

(नियम 3 और 4 देखिए)

सेसमम (तिल) की खली (विलायक निस्सारित) की क्वालिटी की श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6 25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	10 0	44 0	1 0	8 5	1 8	विलायक निस्सारित सेसमम् (तिल) की खली एक्सपेलर या घानी से पेरी गयी सेसमम् (तिल) की खली से विलायक के साधनो द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। खली कुछ प्रारम्भिक शोधन के बाद सीधे सेसमम् (तिल) के बीजा से भी प्राप्त की जा सकती है। निस्सारण

अनुसूची 7 क

(नियम 3 और 4 देखिए)

नारियल की खली (पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी की प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन) 6 25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	10 0	21 0	8 0	12 0	8 0	1 5	कुछ नही	(1) अच्छी श्रेणी की नारियल की खली बिजली चालित मशीनरी द्वारा खोपरे (सूखे नारियल की गिरी) से प्राप्त पैदावार होगी। (2) घानी श्रेणी की खली पशु चलित घानी या चक्कू द्वारा खोपडे (सूखे नारियल की गिरी) से तेल पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी।
घानी	12 0	18 0	13 0	12.0	8 5	2 0	कुछ नही	(3) पदार्थ हानिकारक अवयवो और एरण्डी की खली या भूसी स मुक्त होगा। (4) यह खटमॉस अपमिश्रण, कीट या फफूंद बाधा और किण्वित, सड़न और अन्य आपत्तिजनक दुर्गंध से मुक्त होगी। (5) यह धूल और बाह्य पदार्थ स मुक्त होगी

टिप्पण —स्तम्भ 3 से 7 तक मे विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर सगणित हैं।

पशुधन-चारे के रूप मे नारियल की खली के लिये भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया। (आई० एस० 2154—1962)

अनुसूची 7 ख

(नियम 3 और 4 देखिए)

नारियल की खली (भील) (विलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन) 6.25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रस का (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	10.0	23.0	1.0	14.0	1.5	विलायक निस्सारित की खली (भील) एक्सपेलर या घानी से पेरी गई नारियल की खली से विलायक के साधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। निस्सारण के लिये काम में लाई जाने वाली एक्सपेलर या घानी से पेरी गई नारियल की खली स्वच्छ और ठोस नारियल पेरने से प्राप्त की गई होगी।
स्वच्छ	10.0	21.0	1.5	15.0	2.0	विलायक के लेशों हटाने के लिये भील नियंत्रित और विनियमित दशाओं के अधीन ऊष्मा और भाप शोधन के अधीन रखी जायेगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगी। यह हानिकारक अपमिश्रणों और एरण्डी की खली या भूसी या दोनों और महुआ की खली से मुक्त होगी। यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और सड़न से मुक्त होगी।

टिप्पण :— (1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी होनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-चारे के रूप में विलायक निस्सारित नारियल की खली (भील) के लिये आपातकालीन भारतीय मानक विनिदेश से लिया गया (आई० एस० 3591 ई० 1966)

(2) निस्सारण के लिये विलायक निस्सारण के प्रयोजनों के लिये केवल ऐक्सेन-फूड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जायेगा। विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

क्वथन दूरी————63° से० से 71° से० तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम)————1 प्रतिशत

अवाष्पणील तत्व (अधिकतम)————0.001 ग्राम/100 मि० लि०

अनुसूची 8 क

(नियम 3 और 4 देखिए)

कुसुम की खली—(पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन) 6.25 (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथरसार का (प्रतिशत) (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	8.0	41.0	8.0	13.0	8.0	1.0	कुछ नहीं	(1) अच्छी और स्वच्छ श्रेणियों की खली कुसुम के बीज (कार्थमस टिण्टोरियस एच) की पैदावार होगी जो बिजली चालित मशीनरी द्वारा ठोस और स्वच्छ बीजों से तेल पेरने के बाद प्राप्त की गई होगी।
स्वच्छ	8.0	39.0	10.0	15.0	8.0	2.0	कुछ नहीं	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
घानी खली	10 0	38 0	13 0	12 0	3 0	1 0	कुछ नहीं	(2) घानी खली पशु चालित घानी का बक्का के द्वारा स्वच्छ और ठोस कुसुम के बीज (कार्थमस टिण्टोरियस) से तेल पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी। (3) पदार्थ दृढ़ बनावट का होगा। (4) यह हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगी। (5) यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और किण्वित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गंध से मुक्त होगी। (6) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पण—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

अनुसूची 8 ख

(नियम 3 और 4 देखिए)

कुसुम की खली (विलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन) 6 25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	110 0	50 0	1 0	1 5	15 0	विलायक निस्सारित कुसुम की खली (मील) घानी या एक्स-पेलर से पेरी गई कुसुम की खली से विलायक के साधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। घानी या एक्स-पेलर से पेरी गई कुसुम की खली साफ और ठोस कुसुम के बीज (कार्थमस टिण्टोरियस) पेरने से प्राप्त की गई होगी। प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने और विलायक के लेशे हटाने के लिये निस्सारित खली नियंत्रित और विनियमित
स्वच्छ	10 0	47 0	1 0	2 5	18 0	घनाओं के अधीन रखी जायेगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों या एरण्डी की खली से मुक्त होगी। यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और सड़न से दुर्गंध मुक्त होगी।

टिप्पण— (1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

(2) विनिर्देश प्रारूप की अवस्था में भारतीय मानक संस्था के पास है और अभी तक उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(3) निस्सारण के लिये विलायक—निस्सारण के प्रयोजनों के लिये केवल हैक्सेन-फ्रेक्शन श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जायेगा। विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं —

क्वथन दूरी————63° से० 71° से० तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम)————1 प्रतिशत

अवाष्पशील तत्व (अधिकतम)————0 001 ग्राम । 100 मि० लि०

अनुसूची 9 क

(नियम 3 और 4 देखिए)

तिल्ली की खली—(पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन नाइट्रोजन का 6.25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल खरा का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	9.0	29.0	8.0	9.0	8.0	1.0	कुछ नहीं	(1) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की खली तिल्ली के बीज (ग्यूजोटिया एबीगीनिका कासे) की पैदावार होगी जो बिजली चालित मशीनरी द्वारा ठोस और स्वच्छ तिल्ली के बीज से तेल पेरने के बाद प्राप्त होगी।
स्वच्छ	9.00	28.0	10.0	12.0	8.0	2.0	कुछ नहीं	
घानी खली	10.0	27.0	13.0	9.0	8.0	1.0	कुछ नहीं	(2) घानी खली पशु चालित घानी या चक्की द्वारा स्वच्छ और ठोस तिल्ली के बीज (ग्यूजोटिया एबीसिनिका कास) से तेल पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी। (3) पदार्थ वृद्ध बनावट का होगा। (4) यह हानिकारक अयस्कों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगी। (5) यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और किण्वित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (6) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पण :—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित हैं।

अनुसूची 9 ख

(नियम 3 और 4 देखिए)

तिल्ली की खली (विलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन) 6.25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	9.0	35.0	1.0	1.5	12.0	विलायक निस्सारित तिल्ली की खली (मील) घानी या एक्सपेलर से पेरी गई तिल्ली की खली से विलायक के साधनों

1	2	3	4	5	6	7
स्वच्छ	9.0	29.0	1.0	2.5	15.0	द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जाएगी। घानी या एक्सपेलर में पेरी गई तिल्ली की खली साफ ठोस तिल्ली के बीज (ग्यूजोटिया एबीसिनिका कास) पेरने से प्राप्त की गई होगी। प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने या विलायक के लेशों हटाने के लिये मील नियंत्रित और विनियमित दशाओं के अधीन ऊष्मा और भाप शोधन के अधीन रखी जाएगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों या एरण्डी की खली या भूसी या दोनों या महुवा की खली से मुक्त होगा। यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और सड़न दुर्गन्ध से मुक्त होगी।

टिप्पण :—(1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

(2) विनिर्देश प्रारूप की अवस्था में भारतीय मानक संस्था के पास है और अभी तक उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(3) निस्सारण के लिये विलायक प्रारूप निस्सारण के प्रयोजनों के लिये केवल हैक्सेन-फूड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जाएगा। विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

क्वथन दूरी . 63° से० से 71° से० तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम) . . .1 प्रतिशत

अवाष्पशील तत्व (अधिकतम) . . .0.0001 ग्राम । 100 मी० लि०

[सं० 13-5/71 ए० एम०]

के० एन० चटर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 27th December, 1974

187

S.O.182.—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and in supersession of the Oil Cakes Grading and Marking Rules, 1962 is hereby published, as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and application.—These rules may be called the Vegetable Oil Cakes (Expressed or Solvent Extracted) Grading and Marking Rules, 1974.

2. Definition.—In these rules,—

   (a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

   (b) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designations.—The grade designations to indicate the quality of oil cakes (expressed or solvent extracted) shall be as set out in column (1) of Schedules IIA to IXB.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designations shall be as set out against each grade designation in Schedules IIA to IXB.

5. Grade Designation Marks.—The grade designation mark shall consist of a Label bearing the design set out in Schedule I and specifying the grade designation, the name of the cake and whether it is expressed or solvent extracted.

6. Method of marking.—(i) The grade designation mark shall be securely affixed or stencilled on each container in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser and shall also indicate the number of the Certificate of Authorisation, issued to the packer by the Agricultural Marketing Adviser.

(ii) In addition on every container the following particulars shall clearly and indelibly be marked :

(a) Lot number

(b) Name of packer.

(c) Date of packing.

(iii) The authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said officer, provided that the private trade mark does not represent quality or grade of the oil cake different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules.

7. Method of packing.—(i) The oil cake shall be packed only in containers made of clean, dry and sound jute. They shall be free from any insect infestation or fungus contamination and also free from any undesirable smell.

(ii) Each container shall be securely closed and sealed and shall contain oil cake of one trade description and of one grade designation only.

8. Special conditions of Certificate of Authorisation.—In addition to the conditions specified in rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, the following conditions shall also be the conditions of every Certificate of Authorisation issued for the purpose of these rules, namely :—

(i) each authorised packer shall take all precautions to avoid admixture of oil cakes with castor seed and castor cake.

(ii) if an authorised packer handles more than one type of oil cake in the same premises, adequate precautions shall be taken by him to avoid mixing of different oil cakes. The premises should be clean and hygienic and should be periodically fumigated.

(iii) the authorised packer shall make such arrangements for testing oil cakes as may be specified from time to time by the Agricultural Marketing Adviser and shall also maintain proper records of analysis of the samples.

(iv) all instructions regarding methods of sampling and analysis, packing and marking and maintenance of records, which may be issued from time to time by the Agricultural Marketing Adviser, shall be observed.

(v) a sample of oil cake, drawn in the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser from each lot shall be forwarded to such control laboratory as may be notified from time to time.

SCHEDULE I

(See rule 5)

Grade Designation Mark for labels :

(Only the map of India shall be notified)

SCHEDULE IIA

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of groundnut oil cake-expressed

Grade Designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25) per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Total ash, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	8.0	50 0	8.0	9.0	7.0	1.5	nil	1. Oil cake of good and fair grade shall be the products of decorticated groundnut alone obtained after the expression of oil by power-driven machinery.
Fair	8.0	50.0	5.0	9.0	7.0	2 0	nil	2. Ghani oil cake shall be the product of decorticated groundnut alone obtained after the expression of oil by animal-driven ghani or chakki.
Ghani Cake	10.0	45.0	10.0	9.0	7.0	2.5	nil	3. The material shall be of firm texture.
								4. It shall be free from harmful constituents and castor cake or husk.
								5. It shall be free from rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour.
								6. It shall be free from dirt and extraneous matter.

NOTE.—The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

Adopted from the Indian Standard Specification for decorticated groundnut oil cake as livestock feed (IS : 1713—1960).

SCHEDULE IIB

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of groundnut oil cake-solvent extracted

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen ×6.25) per cent by weight (minimum)	Crude or other extract, per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8
Good	10.0	51.0	1.0	10.0	2.5	nil	1. The solvent extracted groundnut oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by mean of a solvent from the expeller or ghani pressed groundnut oil cake. The meal may also be obtained directly from groundnut seeds after a certain preliminary treatment. The expeller or ghani pressed groundnut oil cake used for extraction shall have been obtained by pressing clean and sound groundnuts (Arachis hypogea L). The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and removal of traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both or Mahua cake. It shall be free from rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	47.0	1 5	12 0	2.5	nil	

NOTE : (1) The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis.
Adopted from the Indian Standard Specification for solvent extracted groundnut oil cake (meal) as livestock feed (IS : 3441—1966).

(2) Solvent for extraction : Only Food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows :—

Boiling range	63°C to 71°C.
Aromatic content (Maximum)	1 per cent.
Non-volatile content, max.	0.00 1 1 0.001 g./100 ml.

SCHEDULE IIIA

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of decorticated cotton seed oil cake-expressed

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen ×6.25) per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Total ash, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	8.0	40 0	8.0	10 0	7.0	1.5	nil	1. Shall be the product of clean cotton seed only. Composed principally of the kernel with such unavoidable portions of the hull and fibre as may be left in the course of manufacture of oil.
Fair	8:0	41.0	5.0	12 0	8.0	2.0	nil	2. The material shall be firm but not flinty in texture.
No. 2	8 0	37.0	5.0	14 0	9 0	2 5	nil	3. It shall be free from harmful constituents and castor cake or husk.
								4. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour.
								5. It shall be free from dirt and extraneous matter.

NOTE.—The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.
Adopted from the Indian Standard Specification for cotton seed oil cake as livestock feed (IS : 1712—1960).

SCHEDULE IIIB

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of undecorticated cotton seed oil-cake-expressed

Grade designation	Moisture, percent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen x6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or ether extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Total ash, percent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	10.0	24.0	7.0	24 0	9.0	2 5	nil	1. Shall be the porduct resulting from the whole, clean and wherever necessary (specially) in the case of (fuzzy seeds) cotton seed only after the expression of oil.
Fair	10 0	24.0	7.0	28 0	9 0	2 5	nil	2. The material shall be firm, but not flinty in texture.
								3. It shall be free from harmful constituents and castor cakes or husk.
								4. It shall be free from rancidity, adulterants, insects or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour.
								5. Shall be free from dirt and extraneous matter.

NOTE.—The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

Adapted from Indian Standard Specification for cotton seed oil cake as livestock fee (IS: 1712-1960).

SCHEDULE III C

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of decorticated cotton seed oil cake (meal)--solvemt extracted

Grade designation	Moisture per cent by weight maximum	Crude protein (nitrogen x6.25) per cent by weight (minimum)	Crude fat or extract, per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	8.0	42.0	1.5	12.0	2.0	The solvent extracted cotton seed oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the decorticated cotton seed oil cake. The meal may also be obtained directly from decorticated cotton seed after a certain preliminary treatment. Cotton seed oil cake used for extraction shall have been obtained by pressing clean and sound decorticated cotton seed. The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both under and mahua cake. It shall be free from musty odour
Fair	8.0	40.0	2.0	14.0	2 5	

NOTE.—1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis.

Adapted from the Emergency Indian Standard Specification for solvent extracted cotton seed oil cake (meal) as livestock feed (IS: 3592E-1966).

2. Solvent from extraction: Only hexane-food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirement of the solvent shall be as follows:

Boiling range— 63°C to 71°C

Aromatic content max....1 per cent

Non volatile content max....0.001 gm./100ml.

SCHEDULE IV A

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of linseed oil cake (meal)– expressed

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or ether extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	7	8 9
Good	10.0	29.0	8.0	10.0	8.0	1.5	nil	1. Oil cake of good and fair grades shall be the product obtained after the expression of oil from linseed by power-driven machinery.
Fair	10.0	29.0	5.0	10.0	8.0	1.5	nil	
Ghani cake	10.0	26.0	15.0	6.0	9.0	2.5	nil	2. Ghani oil cake shall be the product obtained after the expression of oil from linseed by animal-driven ghani. 3. The material shall be free from harmful constituents and castor cake or h sk. 4. It shall be free fom rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour. 5. It shall be free from dirt and extraneous matter.

NOTE.—The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

Adapted from the Indian Standards Specifications for linseed oil cake as livestock feed (IS: 1935—1961).

SCHEDULE IV B

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of linseed oil cake (meal)-solvent extracted

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or ether extract, per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10 0	33 0	1 0	9.0	2.5	The solvent extracted linseed oil cake (meal shall be obtained by extraction of oil by means of solvent from the expeller or ghani pressed linseed oil cake. The meal may also be obtained directly from linseeds after a certain preliminary treatment. The extraction shall have been obtained by pressing clean and sound linseed (Linum usitatissimum L.) The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constitutents and castor cake or husk or both or mahua cake. It shall be free from rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	29.0	1.5	11.0	2 5	

NOTE: 1. The values, specifies in columns 3 to 6 are calculated or moisture free basis Adapted from the Indian Standard Specfcation for solvent extracted linseed oil cake (meal) as livestock fee (IS: 3440-1966).

2. Solvent from extraction: Only hexane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows: —

Boiling range.... 63°C to 71°C. Aromatic content max. 1 per cent.

Non-volatile content, max. 0.001 gm./100ml.

SCHEDULE V A

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Mustard Oil Cake—expressed

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash, per cent by wieght (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	10.0	35.0	8.0	9 0	8 0	1.5	Nil.	1. Oil cake of good and fair grades shall be the product obained after the ex-pression of oil from mustard seed* by power-driven machinery.
Fair	10.0	37.0	5.0	10 0	9.0	2.0	Nil.	
Ghani Cake	12.0	33.0	12.0	7 0	8.0	2.5	Nil.	2. Ghani oil cake shall be the product obtained after the ex-pression of oil from mustard seed* by animal-driven ghani or kolhu.
								3. The material shall be free from harmful constitutents including argemone and castor cake or husk.
								4. It shall be free from rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour.
								5. It shall be free from dirt and extraneous matter.

*The term mustard seed includes rai (Brassica juncea Coss), Sarson (Brassicae compestri Var Sarson), toria (N Brassica compestris, Var, toria) and taramira (Eruca sativa).

The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

Adapted from the Indian Standard Specifications for mustard and range rape oil cake as livestock feed (IS: 1932-1961).

SCHEDULE V B

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of mustard oil cake—solvent extracted

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract, per cent by wight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10.0	45.0	1.0	11.0	1.8	The solvent extracted mustard oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the hydraulic expeller or rotary pressed oil cake. The meal may also be obtained directly from sound mustard seed (rai-Brassica juncea), sarson (Brassica compestris), Toria (Brassica compestris) and tara Mira (Erucea sativa) after a preliminary treatment. The meal shall have been subjetced to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions, so as to prevent denaturation of the protein and to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both or mahua cake or argemone cake. It shall be frem from rancidity, adulterants, insects or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	43.0	1.5	12.0	2.3	

NOTES: 1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated in moisture free basis. Not adopted from Indian Standards Institution specifications.

2. Solvent for extraction: Only haxane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows:

Boiling range 63°C to 71°C. Aromatic content max. 1 per cent.

Non-volatile content maximum 0 001 gm./100 ml.

SCHEDULE VI A

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of sesamum (till) Oil cake—expressed

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract, per cent by weight minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	10.0	37.0	8.0	7.0	13.0	1.5	Nil.	1. Oil cakes of good and fair grades shall be the products obtained after the expression of oil from seasamum (till) seed by power-driven machinery.
Fair	10.0	37.0	5.0	7.0	13.0	2.0	Nil.	
Ghani Cake	10.0	36.0	14.0	7.0	13.0	2.0	Nil.	2. Ghani cake shall be the product obtained after the expression of oil from sesamum (till) seeds by animal-driven ghani.
								3. The material shall be free from harmful constitutuents and castor cake or husk.
								4. It shall be free from rancidity, adulterants, insects or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour.
								5. It shall be free from dirt or extraneous matter.

NOTE: The value specified in coloumns 3 to 7 are calculated on moisture free basis. Adapted from the Indian Standards Specifications for sesamum (till) oil cake as livestock feed (IS: 103 1934-1961).

SCHEDULE VI B

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of sesamum (till) Oil cake—solvent extracted

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein, (nitrogen x 6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10.0	44.0	1.0	8.5	1.8	The solvent extracted sesamum (till) oil cake shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the expeller or ghani pressed sesamum (till) oil cake. The oil cake may also be obtained directly from sesamum (till) seeds after a certain preliminry treatment. The expeller or ghani pressed sesamum (till) seeds oil cake used for extraction shall have been obtained by pressing clean and sound sesamum (till) seeds. The oil cake shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of protein and to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both or mahua cake. It shall be free from rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	44.0	1.5	8.5	1.8	

NOTES: 1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis. Not adopted from the Indian Standard Specification as the same are not yet finalised.

2. Solvent for extraction: Only hexane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows:—

Boiling range 63°C to 71°C. Aromatic content maximum 1 per cent.

Non-volatile content maximum 0.001 gms./100 ml.

SCHEDULE VII A

Grade designations and definition of quality of cocoanut oil cake—expressed

Grade designation	Moisture, per cent by weight (Maximum)	Crude protein (nitrogen ×6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or ether extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Total ash per cent by weight (maximum)	Acid insoluble as per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	10.0	21.0	8.0	12.0	8.0	1.5	Nil.	1. Coconut oil cake of grade Good shall be the product obtained after the expression of oil from copra (dried cocoanut kernels) by power-driven machinery.
Ghani	12.0	18.0	13.0	12.0	8.5	2.0	Nil.	2. Ghani grade oil cake shall be the product obtained after the expression of oil from copra (dried cocoanut kernels) by the animal driven ghani or chakka.
								3. The material shall be free from harmful constituents and castor cake or husk.
								4. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus infestation and from fermented, musty and other objectionable odour.
								5. It shall be free from dirt and extraneous matter.

NOTE: The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis. Adapted from the Indian Standard Specification for cocoanut oil cake as livestock feed (IS : 2154 : 1962).

SCHEDULE VII B

Grade designations and definition of quality of cocoanut oil cake (meal) solvent extracted

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen ×6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or ether extract, per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10.0	23.0	1.0	14.0	1.5	The solvent extracted cocoanut oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the expeller or ghani pressed coconut oil cake. The expeller or ghani pressed coconut oil cake used for extraction shall have been obtained by pressing clean and sound coconut. The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder. It shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both and mahua cake. It shall be free from rancidity, adulterants, insects or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	21.0	1.5	15.0	2.0	

NOTES: 1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis. Adapted from Emergency Indian Standard specification for solvent extracted coconut oil cake (meal) as livestock feed (IS : 3591 E-1966).

2. Solvent for extraction: Only hexane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows:—

Boiling range—63°C to 71°C.
Aromatic content max.— 1 per cent.
Non-volatile content max.— 0.001 gms./100 ml.

SCHEDULE VIII A

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of safflower oil cake—expressed

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen ×6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or ether extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Total ash, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	8.0	41.0	8.0	13.0	8.0	1.0	Nil.	1. Oil cake of good and fair grades shall be the product of safflower seeds (Carthamus tinetorius L.) obtained after the expression of oil from sound and clean seeds by power-driven machinery.
Fair	8.0	39.0	10.0	15.0	8.0	2.0	Nil.	
Ghani Cake	10.0	38.0	13.0	12.0	8.0	1.0	Nil.	2. Ghani oil cake shall be the product obtained after the expression of oil from clean and sound safflower seeds (Carthamus tinetorius L.) by animal driven ghani or chakka.
								3. The material shall be of firm texture.
								4. It shall be free from harmful constituents and castor cake or husk.
								5. It shall be free from rancidity, adulterants and insect or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour.
								6. It shall be free from dirt and extraneous matter.

NOTE: The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

SCHEDULE VIII B

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of safflower oil cake—solvent extracted.

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen ×6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or ether extract, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10.0	50.0	1.0	1.5	15 0	The solvent extracted safflower oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the ghani or expeller pressed safflower oil cake. The ghani or expeller pressed safflower oil cake shall have been obtained by pressing clean and sound safflower seeds (Carthamus tinetorius L.). The extracted oil cake (meal) shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents or castor cake or husk or both of mahua cake. It shall be free from rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	47.0	1.0	2 5	18.0	

NOTE: 1. The values specified under columns 3 to 6 are on moisture free basis.

2. The specifications are at draft stage with the Indian Standards Institution and not yet finalised.

3. Solvent for extraction : Only hexane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows:—

Boiling range— 63° C to 71°C.

Aromatic content max.— 1 per cent.

Non-volatile content max.— 0.001 gm./100 ml.

SCHEDULE IX A

(*See* rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of niger seed oil cake-expressed

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25) per cent by weight (minimum)	Crude fat or ether extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Total ash, per cent by weight (maximum)	Acid soluble ash, per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	9.0	29.0	8.0	9.0	8.0	1.0	Nil.	1. Oil cake of good and fair grade shall be the product of Niger seeds (Guizotia abyssinica Cass) obtained after the expression of oil from sound and clean niger seeds by power-driven machinery.
Fair	9.0	23.0	10.0	12.0	8.0	2.0	Nil.	2. Ghani oil cake shall be the product obtained after the expression of oil from clean and sound Niger seeds (Guizotia abyssinica Cass) by animal-driven ghani or chakku.
Ghani cake	10.0	27.0	13.0	9.0	8.0	1.0	Nil.	3. The material shall be in firm texture.
								4. It shall be free from harmful consstituents and castor cake or husk.
								5. It shall be free from rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from fermented, musty or other objection able odour.
								6. It shall be free from dirt and extraneous matter.

NOTE: The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

SCHEDULE IX-B

(*See* rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of niger seed oil cake-solvent extracted

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25), per cent by weight (minimum)	Crude fat or either extract, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	9.0	35.0	1.0	1.5	12.0	The solvent extracted niger oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the ghani or expeller pressed niger seed oil cake. The ghani or expeller pressed niger seed oil cake shall have been obtained by pressing clean, sound niger seeds (Guizotia abyssinica Cass). The meal shall have been subjected to heat and Steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and to remove traces of solvent. The material shall be in the firm of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents of castor cake or husk or both or mahua cake. It shall be free from rancidity adulterants, insect or fungus infestation and from musty odour.
Fair	9.0	29.0	1.0	2.5	15.0	

NOTE: 1. The values specified under columns 3 to 6 are on moisture free basis.

2. The specifications are at draft stage with Indian Standards Institution and not yet finalised.

3. Solvent for extraction: Only hexane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows:

Boiling range.	63* C to 71*C.
Aromatic content max.	1 per cent.
Non-volatile content, max	0.001 gm./100 ml.

[No. 13.5/71 AM]

K. N. CHATTERJEE, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1974

का० आ० 188.— यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की पूर्व कत्रास कोलियरी, डाकघर कत्रासगढ़ (धनबाद) के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की पूर्व कत्रास कोलियरी, डाकघर कत्रासगढ़, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र का श्री भुरा सिंह सामान्य मजदूर को 14 मार्च, 1973 से काम से रोकना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-2012 (28)/74-एल.आर.-2]

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 1974

S.O. 188.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Katras Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Katrasgarh (Dhanbad) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Goverment considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, (No. 2) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of East Katras Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad are justified in stopping Shri Bhura Singh, General Mazdoor, from work with effect from the 14th March, 1973 ? If not to what relief is the concerned workman entitled ?

[File No. L-2012/28/74-LRII]

आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1974

का० आ० 189.— यतः केन्द्री सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, डाकघर निरसाचट्टी, जिला धनबाद की खुदिया कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिकरण नियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, डाकघर निरसाचट्टी, जिला धनबाद की खुदिया कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की श्री सपन कुमार चौधरी, लेखा लिपिक के काम को 23 अगस्त, 1973 से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बद्ध कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-2012/172/73-एल० आर०-2]

ORDER

New Delhi, the 2nd December, 1974

S.O. 189.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Khudia Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Khudia Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, in stopping the work of Shri Sapan Kumar Chowdhury, Accounts Clerk with effect from the 23rd August, 1973, is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?

[No. L-2012/172/73-LRII.]

आदेश

का. आ. 190.— यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स नरेश कुमार एण्ड कम्पनी, ठेकेदार, डिग्वाडिह कोलियरी, चोपड़ा विला, बस्ताकोला डाकघर धनसार, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मेसर्स नरेश कुमार एण्ड कम्पनी, ठेकेदार, डिग्वाडिह कोलियरी, चोपड़ा विला, बस्ताकोल्ला, डाकघर धनसार, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र की श्री बी सी बनर्जी, केबिनमैन को 29 मई, 1974 से सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो सम्बन्ध कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-2012/116/74-एल आर.-2]

ORDER

S.O. 190.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs. Naresh Kumar and Company, Contractor, Digwadih Colliery, Chopra Villa, Bastacolla, Post Office Dhansar, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs. Naresh Kumar and Company, Contractor, Digwadih Colliery, Chopra Villa, Bastacolla, Post Office Dhansar, District Dhanbad in dismissing from service Shri B. C. Banerjee, Cabinman with effect from the 29th May, 1974 is justified ? If not to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. L-2012/116/74-LR. II]

New Delhi, the 9th January, 1975

S.O. 191.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri Vijaylalji Kumrawat, Village Suthera, Post Office Dabi (District Bundi) and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st December, 1974

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

CAMP AT JAIPUR

Dated December 24, 1974

Case No. CGIT/LC(R)(24) of 1974

(Notification No. L-29011/42/74-LRIV, dated 30th September, 1974).

PARTIES:

Enmployers in relation to the management of Shri Vijaylalji Kumrawat, Village Suthera, Post Office Dabi (District Bundi) and their workmen represented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh, E-3/97, Near New Railway Colony, Kota-2(Rajasthan).

APPEARANCES:

For workmen —Shri Nainu Ram

For employers—None.

INDUSRTY : Pathar Khan.

DISTRICT : Bundi (Rajasthan).

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

The Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (hereinafter called the Union) has prayed for the grant of 10 paid national and festival holidays on behalf of the workmen of the Suthera Sand Stone Mines which are owned by Shri Vijaylalji Kumrawat, Mine Owner.

The question referred to this Tribunal for its adjudication as set out in the schedule to the reference is as follows:—

"Whether the workmen employed in Suthera Sand Stone Mine of Shri Vijayalji Kumrawat, Village Suthera, Post Office Dabi (District Bundi) are entitled to grant of any paid National and Festival holidays?"

The Union had made a demand for the grant of the aforesaid holidays from the Mine owner but since there was no response from him the dispute was referred to the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota. Neither the Mine Owner nor any one of his representative appeared before the Asstt. Labour Commissioner (Central) Kota and the conciliation proceedings ended in failure. Thereafter the dispute was referred to this Tribunal for its adjudication.

Shri Nainu Ram (W.W. 1) gave evidence on behalf of the Union. The owner neither filed any written statement nor did he appear before this Tribunal. The workmen have claimed for the grant of the following holidays as paid National and Festival holidays from 4-1-1974 :—

1.	26th January (Republic Day)	— 1 day.
2.	Holika Dahan (Dhulendi)	— 1 day.
3.	1st May (Labour Day)	— 1 day.
4.	Rakshabandhan	— 1 day.
5.	Krishna Janmastmi	— 1 day.
6.	15th August (Independence Day)	— 1 day.
7.	Dushehra	— 1 day.
8.	Dipawali	— 1 day.
9.	2nd October (Gandhi Jayanti)	— 1 day.
10	Id or Local Festival	— 1 day.

I have already held in several references where this very question came before this Tribunal that in view of the national importance of the aforesaid holidays and festivals the workmen are entitled to the grant of the said holidays as paid national and festival holidays irrespective of the provisions of the Mines Act. My answer to the reference is in the affirmative. My award is that the workmen employed in Suthera Sand Stone Mine of Shri Vijaylalji Kumrawat, Village Suthera, Post Office Dabi (District Bundi) are entitled to the grant of the aforesaid ten holidays as paid National and Festival holidays from 4-1-1974.

It is a matter of regret that the owner or his representative neither appeared before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota nor before this Tribunal. I award Rs. 100 as costs to the workmen.

S. N. KATIU, Presiding Officer,

[No. L-29011(42)/74-LR. IV]

LALFAK ZUALA, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1974

का० आ० 192.—यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नियोजक श्री विजयलाल जी कुमारावत, खान स्वामी, गाँव सुथेरा, डाकघर दाबी (जिला बूंदी) और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ,

और यत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या श्री विजयलाल जी कुमरावत की सुथेरा बलुवा पत्थर खान, गाँव सुथेरा, डाकघर दाबी (जिला बूंदी) में नियोजित कर्मकारों की, 1965-66 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 और 1971-72, के लेखा वर्षों के लिए मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से बोनस के संदाय की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार इन वर्षों में से प्रत्येक के लिए बोनस की किस मात्रा के हकदार है ?

[सं० एल-29011 (41)/74-एल०आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 15th November, 1974

S.O. 192.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers Shri Vijaylalji Kumrawat, Mine Owner, Village Suthera, Post Office Dabi (District Bundi) and his workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer to the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workers employed in Suthera Sand Stone Mine of Shri Vijayalalji Kumrawat, Village Suthera, Post Office Dabi (District Bundi) for payment of bonus @20 of wages for the Accounting years 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72 is justified? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of these years?

[No. L-29011(41)/74-LR. IV]

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1974

का०आ० 193.—यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में व्यास बांध परियोजना, तलवाड़ा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोढी होंगे, जिनका मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या व्यास बांध परियोजना, तलवाड़ा के प्रबंधतंत्र की श्री पवित्तर सिंह, टोकन सं० 1229-एल, को 9 जनवरी, 1971 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[स० एल० 42012/14/71-एल० आर०-3]

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1974

S.O. 193.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Beas Dam Project, Talwara and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Beas Dam, Talwara in dismissing Shri Pawittar Singh, Token No. 1229 L from service with effect from the 9th January, 1971 is justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. L. 42012/14/71/LR. III]

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1974

का० आ० 194.— यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड, चर्खी दादरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री ओ० पी० शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय फरीदाबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण, को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड, चर्खी दादरी के प्रबंधतंत्र की, श्री ईश्वर सिंह, लदान मट की सेवाओं को 12 जनवरी, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सख्या एल-29012/19/74-एल०आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 27th November, 1974

S.O. 194.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annxede;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri O. P. Sharma as Presiding Officer with headquarters at Faridabad, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri in terminating the services of Shri Ishwar Singh, loading Mate, with effect from the 12th January, 1974 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-29012/19/74-LR.IV]

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1974

का० आ० 195 —यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पाइराइट्स फासफेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड अमझोर के प्रबंध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या (2) धनबाद को न्यानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या पाइराइट्स, फौसफेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, अमझोर के प्रबंधतंत्र की, उनके कर्मकार श्री रामलखन सिंह, कम्प्रेसर चालक की सेवाओं को 3 फरवरी; 1973 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-29012/10/74-एल०आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 28th November, 1974

S.O. 195.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, Amjhore and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. (2) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action taken by the management of Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, Amjhore in dismissing the services of their workmen, Shri Ramlakhan Singh, Compressor Operator with effect from the 3rd February, 1973 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-29012/10/74-LR. IV]

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1974

का० आ० 196.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड, चर्खी दादरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री ओ० पी० शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय फरीदाबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड, चर्खी दादरी के प्रबन्ध-तंत्र की श्री मान सिंह लदान मेट की सेवाओं को 12 जनवरी, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[संख्या एल-29012/21/74-एल०आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1974

S.O. 196.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen in respect of the matters specified in the Scheduled hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Indusrial Tirbunal with Shri O. P. Sharma, as Presiding Officer with headquarters at Faridabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri in terminating the services of Shri Man Singh, Loading Mate, with effect from the 12th January, 1974 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-29012/21/74-LR.IV]

New Delhi, the 30th December, 1974

S.O. 197.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the Indian Airlines Corporation and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd December, 1974.

IN THE MATTER OF ARBITRATION

BETWEEN

Indian Airlines having its Headquarters at Airlines House 113, Gurdwara Rakabganj, Road, New Delhi.

AND

Its workmen, represented by Indian Flight Engineers' Association.

AWARD

I Chandra Kisan Daphtary, Senior Advocate, Supreme Court having been appointed the sole arbitrator in pursuance of the provisions of sub-section 1 of section 10-A of the Industrial Disputes Act 1947 (XIV of 1947), by the parties viz. the Flight Engineers employed by the Indian Airlines Corporation (workmen) represented by the Indian Flight Engineers' Association of the one part and the Indian Airlines Corporation (employers) of the other part to investigate and decide the disputes between them viz.

(a) whether there is any justification for the demands of the association for payment of meal allowance in lieu of meals for the day-return flights, as is paid to the First Officers;

(b) whether there is any justification in the demand of the association for payment of light refreshment allowance as is paid to the First Officers;

(c) what should be the date of effect to the relief, if any, of the above payments:

and the said agreement having been published by the Central Government on the 3rd day of February 1973 having accepted and entered upon the said reference on the 21st day of March 1974* and having perused such papers as the parties referred to and having perused the evidence on affidavits and having heard counsel for the parties on several days and having investigated the matter I do make my award as follows :—

I do award :

that there is justification for payment of a meal allowance in lieu of meals (for day return flights) to the Flight Engineers of the Indian Airlines Corportion. And, I award that each of them be paid Rs. 35.00 for each return flight in the same manner as the First Officers are paid.

I also award that the Flight Engineers are entitled to the said payment from the 1st of March 1972. If however any meals have been provided and supplied since 1st March, 1972 or payment in lieu thereof have been actually received by the Flight Engineers then the cost of such meals on the basis of Rs. 8.00 per meal or the payment made as the case may be shall be adjusted and set off against the payment to be made under this award.

I do further award that there is justification for the payment of a refreshment allowance I do award Rs. 5.00 per day in the same manner as the First Officers are paid. The said payment of Rs 5.00 per day to be effective from the 1st of March 1972. Payment for refreshment if any made subsequent to that date upto the date of this award to be set off and adjusted against the said sum of Rs. 5.00.

The counsel for the parties have stated before me that my award will apply notwithstanding the settlement arrived at in January, 1974 between the association and the Indian Airlines Corporation.

I do also award that the Indian Airlines Corporation do bear its own costs of the arbitration and do pay the costs of the Indian Flight Engineers' Association including the arbitrator's fees.

Sd/-

C. K. DAPHTARY,
28-11-1974.

*And Whereas time was extended by consent of the parties on November 12, 1974 by a writing to the end of December, 1974.

Sd/-

C. K. DAPHTARY,
28-11-1974.

[No. L. 11013/1/73/LRIII]

S.O. 198.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the Beas Sutlej Link Project, Sundernagar and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th December, 1974.

BEFORE THE ASSISTANT LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) KANPUR & ARBITRATOR UNDER SECTION 10-A OF INDUSTRIAL DISPUTE ACT, 1947

Reference No. KC 224(5)74

PARTIES :

The Employer in relation Beas Sutlej Link Project, Sundernagar, Himachal Pradesh.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employer.—Shri Rattan Lal Kaith, Personnel Officer, Beas Sutlej Link Project, Sundernagar.

For the workman.—Shri M. S. Toggar, President, Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar.

Dated the 21st December, 1974

ARBITRATION AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi in persuance of sub-section (3) of Section 10-A of the Industrial Dispute Act, 1947 referred the arbitration agreement arrived on 22-6-1974 under sub-section 1 of Section 10-A of the Industrial Dispute Act, 1947 between the aforesaid parties vide their order No. L. 42012/30/74 dated the 6th July, 1974 for publication in the gazette of India, endorsing a copy of the same to me. The aforesaid parties had agreed to refer the following dispute to me for arbitration within a period of six months.

"Whether the action of the management of Beas Sutlej Link Project, Sundernagar in terminating the services of Shri Mukhtiar Singh, Pipe Fitter, Token No. 293-AC with effect from the 9th June, 1973 was legal & justified? If not, what relief is the workman entitled."

2. The hearings in the case were held at Camp Chandigarh on 17-8-74, 1-10-74 and 19-12-1974

3. The facts of the case are that the workman Shri Mukhtiar Singh absented from duty without sanctioned leave for more than ten days w.e.f. 7-6-1973 and onwards, hence the management as per the Certified Standing Orders considered him having resigned/abondoned the serivces.

4. The representative of the workman stated that it was wrong to say that the workman had absented himself from duty. On the contrary, he pointed out, that the workman had approached the management on 9-6-1973 for work but he was refused work giving a slip to him, which is placed on the records & reads as under :—

"Shri Mukhtiar Singh Fitter, T. No. 293-AC as per order of XEN. M.II, your attendance cannot be marked onward."

Under the circumstances the union representative stated the allegation of the management is motivated and unjustified.

5. The representative of the management stated that the Executive Engineer, Field Machanical-II had already issued orders that whenever a workman joins duty after unauthorised leave, he should get the same sanctioned from the Executive Engineer before he is allowed to join duties. It was in compliance of this that the workman concerned was given the slip with the advice to approach the Executive Engineer for the purpose, but the workman never approached him and preferred to remain absent. He has, otherwise, been also absenting quite frequently as his absence and leave without pay records would so. He stated that the workman had absconded from Sundernagar in order to avoid arrest & prosecution as he was wanted in a case under Section 307 of I.P.C.

6. On examination of the case and the arguments of the parties I come to the following conclusion.

7. There is, no doubt, that the workman had approached the management for work on 9-6-1973 after absenting for only two days on 7th & 8th June, 1973 but he was clearly refused in writing that his attendance cannot be marked onwards

8. There is no indication in the slip that the workman had to approach the Executive Engineer for getting his leave sanctioned and to report for duty thereafter. The slip is clear and categorical which indicate that the workman's attendance cannot be marked onwards. Again, against the decision of the management the union representative took up the matter on 18-6-1973 before the Asstt. Labour Commissioner (C), Chandigarh who asked the Superintending Engineer, who was present in his office, the same day, to hear the workman's case in appeal and give decision, before which he did not think there was proper industrial dispute as the union had not exhausted the channel of appeal. The management heard the appeal on 25-7-1973 and upheld the management's decision.

9. There is no doubt that the workman was stopped from work by the management, but I have not been able to reconcile why he did not immediately react to such a situation and approach the Executive Engineer or made appeal against the order or stand of the management. After a period of lapse of more than five weeks his dispute was raised before the Asstt. Labour Commissioner (C), Chandigarh. This delay may be due to his ignorance of the law and the practices and deserves condonation. Under the circumstances I hold that the action of the management in treating the workman having resigned the job and refusing employment to him is not justified and the workman deserves reinstatement. However, as the workman has not been active in pursuing his case which has resulted in such a long non-productive period for him, he does not deserve benefits of full wages. I accordingly, direct that the workman be reinstated with all benefits of the continuity of service, He will however, be paid for the entire period of his absence only @ 50 per cent of his wages that might have been due to him, had he been working.

10. I, therefore, direct that the workman be reinstated and paid the awarded wages within one month from the date this award becomes enforceable.

VIJAI SHANKER, Arbitrator and Asstt. Labour Commissioner (Central)

Kanpur

Dated the 21st December, 1974.

[No. L. 42012/30/74/LRIII]

S.O. 199.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following, award of the arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the Beas Sutlej Link Project, Sundernagar and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th December, 1974.

BEFORE THE ASSISTANT LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) KANPUR & ARBITRATION UNDER SECTION 10-A OF INDUSTRIAL DISPUTE ACT, 1947

REFERENCE NO. KC-224(6)74

PARTIES:

The Employer in relation Beas Sutlej Link Project, Sundernagar, Himachal Pradesh

AND

Their workman

APPEARANCES :

For the employer—Shri Ratan Lal Kaith, Personnel Officer, Beas Sutlej Link Project, Sundernager.

For the workman—Shri M. S. Toggar, President, Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar.

Dated the 21st December, 1974.

ARBITRATION AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi in persuance of sub-section (3) of Section 10-A of the Industrial Dispute Act, 1947 referred the arbitration agreement arrived on 22-6-1974 under sub-section 1 of Section 10-A of the Industrial Dispute Act, 1947 between the aforesaid parties vide their order No. L.42012/31/74 dated the 6th July, 1974 for publication in the gazette of India, endorsing a copy of the same to me. The aforesaid parties had agreed to refer the following dispute to me for arbitration within a period of six months.

"Whether suspension of Shri Prem Singh, Asstt. Loco Operator, Beas Sutlej Link Project Sundernagar from 14th May, 1971 to the 7th June, 1972 and consequential punishment of stopage of one increment without future effect was legal and justified. In either case to what relief the workman is entitled ?"

2. The hearing in the case was held at Camp—Chandigarh on 17-8-74, 1-10-74 and 19-12-1974.

3. The facts of the case are that on 13-5-1971 at about 4.30 A.M. Shri Prem Singh, Asstt. Loco Operator, the workman concerned was operating Loco LL.9. He was asked to bring with crew & some material upside the tunnel. After unloading the crew & the material he was returning downward. As he reached the main tunnel his loco collied with another loco LL.37 coming upward.

4. The workman was charge-sheeted for misconduct under clause 17(b), (vi) & (xix) of the Certified Standing Orders which are reproduced as below:—

(vi) Negligence of duty, laziness, malingering or slowing down of work or negelect of work.

(xix) Wilful disregard of any operational or maintenance instructions or carelessness in operation and maintenance.

5. The representative of the workman argued that the workman was improperly charge-sheeted & full opportunity to defend himself in the domestic enquiry was not afforded to him. Besides he was awarded two punishments viz (1) stoppage of workman's one increment without future effect and (ii) as well as denial of full wages to him for the suspended period, for one misconduct, which was arbitrary & unjustified.

6. The representative of the management stated that the workman was given full opportunity to defend his case in the domestic enquiry but since he admitted his guilt, no further proceeding was considered necessary and he was rightly awarded punishment as above.

7. On examination of the case, documents and the arguments of the parties in detail I come to the following conclusion.

8. The workman had admitted his guilt on 6-4-1972 and prayed for lenient view before the Enquiry Officer and had signed the inquiry proceedings making a record of this

9. The management had intended & awarded punishment to the workman under clause 17(a) (ii) of Certified Standing Order' of stoppage of one annual increment without future effect' This is clear from the show-cause notice issued to the workman vide his management's letter No. 2892—93/4E/P.S./dated 12-5-1972 This show-cause notice does not mention of the denial of full wages to the workman for the suspension period.

10. The last three sentences of the final order of punishment communicated to the workman vide No. 3344-48/4-E dated 7-6-1972 reads as under :—

"It is considered that only the penalty of stopping your one increment without future effect would meet the ends of justice. Your one increment without future effect is therefore, hereby stopped with immediate effect. You will not be entitled to duty pay except the subsistence allowance already drawn during the suspension period".

11. The last sentence which is unjustified appears to have inadvertently occured in the punishment order. This is wrong also in view of clause 19(III) Proviso—first, which read as under:—

"Provided that when an order of dismissal or discharge is passed under this clause, the workman shall be deemed to have been absent from duty during the period of suspension and shall not be entitled to any remuneration for such period, but the subsistence allowance already paid to him shall not be recovered".

12. Further, it is not the case of the management that the workman concerned took up employment anywhere during the period of suspension.

13. In view of the above, I consider the punishment of stoppage of one annual increment without future effect, quite commensurate with the misconduct committeed & admitted by the workman. I hold accordingly.

14. While the punishment effected due to denial of full wages for the entire suspended period from 14th May, 1971 to 7th June, 1972 is unjustified. Once a punishment is given of stoppge of increment, the workman is entitled for full wages for the suspended period, this is, therefore, being revoked. The workman shall, therefore, be paid full wages for the above suspended period minus the subsistence allowance already received by him

15. I, therefore, direct that the amount so due shall be paid to the workman within one month from the date this award becomes enforceable.

VIJAI SHANKER, Arbitrator and Assistant Labour Commissioner (Central)

[No. L 42012/31/74/LRIII]

Kanpur :
Dated 21st December, 1974

New. Delhi, the 1st January, 1975

S.O. 200.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)., the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workman, which was received by the Central Government on the 27th December, 1974.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE NO. 5 OF 1974

PARTIES :

Employers in relation to the Punjab National Bank.
And

Their Workmen

APPEARANCE :

On behalf of Employers.—Shri A. Roy Chaudhuri Senior Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Shri C. L. Bhardwaj, General Secretary, All India P.N.B. Employees Association.

State : Orissa Industry : Banking.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour by Order No. L. 12012/129/73/LRIII, dated 18th May, 1974, referred an existing industrial dispute between the Punjab National Bank and one of its employees, a clerk-cum-cashier, Sri S. K. Sen Gupta, in respect of the matter specified in the Schedule below under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Punjab National Bank in terminating the services of Shri S. K. Sen Gupta, Clerk-cum-Cashier at Sambalpur Branch of the Bank with effect from the 29th July, 1973 is justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. In pursuance of the notices issued to the respective parties they appeared before me and filed written statement.

3. The facts of the case which led upto the dispute in brief are as follows :—

The affected workman filed an application, Ext. M1 on 24-4-1972 before the Branch Manager of Punjab National Bank at Sambalpur (Orissa), on the basis of his knowledge of temporary vacancy of a clerk, praying that he may be appointed to that vacancy. On the strength of that application the workman was appoined vide Ext. W1—Order with effect from 24-4-72 for a period of 15 days ending with 8-5-72. The appointment was made in the transfer vacancy of one Sri B. P. Srivastava who was the clerk-cum-cashier of the Bank. That appointment was extended upto 12-5-1972 vide Ext. W2 Order. Thereafter the workman filed another application, Ext. M2, on 15-5-72 in a similar vacancy which occurred on account of a clerk Sri M. L. Gupta who went on casual leave. Ext. W3 is the Order under which the workman was appointed in that leave vacancy upto 17-6-72. Sri M. L. Gupta rejoined his duty on 19-6-72 after expiry of his leave. 18-6-72 happened to be a Sunday. The next vacancy under the Bank arose with effect from 3-7-72 when again the workman applied vide Ext. M3 that he should be appointed in that vacancy which arose in the Bank on account of Sri R. A. Sinha, clerk-cum-cashier transferred. Ext. W4 was the Order under which the workman was appointed in that vacancy from 3-7-72 to 18-7-72 That was extended till 31-7-72 under Ext. W5 and again to 19-8-1972 under Ext. W6 and lastly under Ext. W7 to 30-9-1972. The workman again applied vide Ext. M4 for an appointment on the basis of which he was appointed from 2-9-1972 to 15-9-72 in the same vacancy of Sri R. A. Sinha who was on transfer. That appointment was extended upto 31-10-1972 under Ext W9. A further appointment was made under Ext. W10 from 2-11-72 to 30-11-72 in the same arrangement of R. A. Sinha on the basis of Ext. M5, application which the workman made to the Bank. That appointment was further extended upto 19-12-1972. On 21-12-72 vide Ext. M6, the workman again applied for fresh appointment on the basis of which he was appointed from 21-12-1972 to 21-1-1973 for a period of 31 days in the same transfer vacancy of R. A. Sinha. That appointment was further extended to 31-1-73 vide Ext. W 13. On termination of that appointment the workman applied vide Ext. M7 on 2-2-1973 for a fresh appointment on the basis of which he was again appointed from 3-3-1973 for a period of 30 days under Ext. W15 the appointment order. That appointment was extended upto 2-4-1973.

4. The next appointment was on 4-4-1973 on the basis of Ext. W16 Order, for a period of 20 days ending with 23-4-73. That appointment was also made on the basis of Ext. M8, application made by the workman. The appointment was extended upto 11-5-73 and then to 31-5-73 and finally to 2-6-1973, vide Exts. W17, W18 and W19. That appointment was in the leave vacancy of one Sri M. L. Gupta who was a clerk-cum-cashier of the bank. The last appointment was under Ext. W20 for a period of 15 days from 5-6-73 to 21-6-73 in the leave vacancy of Shri R. T. Pandey. That appointment was extended from time to time ending with 28-7-73, vide Exts. W21 and W22. On the expiry of the period of service covered by the above appointment the bank issued Ext W23 Order to the effect that his temporary services was terminated with effect from 29-7-73 as Sri Pandey had rejoined duty after expiry of his leave.

5. On the whole the affected workman had put in 436 days' of service in the Bank. He wanted the bank to treat him as a permanent employee and continue in service even after his termination of service with effect from 29-7-73 as according to him the termination of his service was against the letter and spirit of the provisions contained in several Bank awards as well as the first Bi-partite Settlement dated 19-10-1966. Since the workman failed to get any relief from the Bank, he approached the General Secretary of the All India Punjab National Bank Employees Association at its Orissa State Unit at Cuttack with a representation dated 21-4-73 to get justice done to him. On the basis of that representation the State unit approached the Regional Manager of the Bank at Calcutta. But there was no effect to those representations and as such the Association approached the Assistant Labour Commissioner at Rourkela on 19-7-73 for a conciliation but the conciliation resulted in a failure and it was accordingly that the dispute was referred to this tribunal.

6. On the strength of the different orders referred to above the workman had served under the Bank during the following period :

1.	From	24.4.72	to	12.5.72	..	19 days.
2.	From	15.5.72	to	17.6.72	...	34 days.
3.	From	3.7.72	to	30.8.72	...	59 days.
4.	From	2.9.72	to	31.10.72	...	60 days.
5.	From	2.11.72	to	19.12.72	...	48 days.
6.	From	21.12.72	to	31.1.73	...	42 days.
7.	From	12.2.73	to	2.4.73	...	60 days.
8.	From	4.4.73	to	2.6.73	...	60 days.
9.	From	5.6.73	to	28.7.73	...	54 days.
						436 days.

The workman alleged that there was victimisation, unfair labour practice and malafide in the terms of his appointment as well as its termination. The workman was the only witness examined in the case. Both sides have also produced documents and marked exhibits. The workman was represented by the General Secretary to the All India Punjab National Bank Employees Association and the management was represented by its Senior Personnel Officer.

7. The Exts. M1 to M9 and W1 to W22 covered the entire period of service of the workman. It is admitted that the appointment covered by Exts. W1, W2 and W4 to W15 was in respect of the transfer vacancy of one Sri Srivastava and that of one Sri Sinha while the appointment under Exts. W 3 and W 16 to W 20 was in respect of leave vacancy of Svs. M. L. Gupta and R. T. Pandey. It is also relevant to point out that prior to each of these appointments beginning from Ext. W3 down to W20 there had been break of service. But the appointment covered by Ext. W4 in the transfer vacancy of R. A. Sinha in the first instance from 3-7-72 to 3-8-72 continued in the same vacancy from 2-9-72 to 15-9-72 though there was a break on 1-9-72. The first appointment in R. A. Sinha's place was on 3-7-72 vide Ext. W4 The next appointment was under Ext. W8 which was extended upto 31-10-72 On 1-11-72 there was again a break in service but he was appointed again under Ext. W10 on 2-11-72 which was extended upto 19-12-1972. There was a further break in service on 20-12-72. The next appointment in that vacancy was on 21-12-72 vide Ext. W12 which was extended upto 31-1-73 On 1-2-73 there was again a break in service. The next appointment vide Ext. W14 was with effect from 2-2-73 to 3-3-73 which was

extended upto 2-4-73 vide Ext. W15. So, the workman had worked from 3-7-72 to 2-4-73 in the transfer vacancy of R. A. Sinha with intermittent break. That the workman served under the Bank from 15-5-72 to 19-6-72 and from 4-4-1973 to 2-6-73 and then again from 5-6-73 to 21-6-73 upto 28-7-73 in the leave vacancy of M. L. Gupta and R. P. Pandey had not been disputed. Now, the question for us to consider is whether the workman is entitled to claim the status of a permanent employee in the Bank on the basis of these temporary appointments.

8. The contention raised on behalf of the workmen is that having worked in the Bank against a permanent sanctioned vacancy for more than 3 months he is deemed to have automatically attained the status of a permanent employee and as such he should have been given all the benefits available to such an employee without the termination of his service. Reliance has been placed upon paragraph 20.8 of the Bi-partite Settlement which reads as follows :

> "A temporary workman may also be appointed to fill a permanent vacancy provided that such temporary appointment shall not exceed a period of three months during which the bank shall make arrangements for filling up the vacancy permanently. If such a temporary workman is eventually selected for filling up the vacancy, the period of such temporary employment will be taken into account as part of his probationary period."

This paragraph shows that the bank has been empowered under the Bi-partite Settlement to appoint a temporary workman in order to fill up a permanent vacancy but this period shall not exceed three months during which the bank has to fill up the vacancy permanently. This paragraph, however, does not show that the temporary workman appointed against a permanent vacancy automatically becomes a permanent hand.

9. There is no material on hand to come to the conclusion that the workman in question was appointed to fill up a permanent vacancy. The application which the workman filed from time to time for getting himself employed in the Bank are also not to that effect. There is no other document to indicate that he was so appointed. The applications could not indicate that he was applying for any permanent vacancy. Except in the vacancy of Sri R. A. Sinha and Srivastava the other appointments were made in leave vacancies. So, when the permanent incumbent resumed duty after expiry of his leave the workman's service came to an end automatically. Para 20.8 of the Bi-partite Settlement says that a temporary appointment which is sought to be made to fiill a permanent vacancy shall not exceed a period of 3 months and during that period the Bank should make arrangement for filling up the vacancy permanently. But on no strength of imagination it can be held that if the appointment exceeds a period of 3 months the incumbent automatically enters into the probationery period which ultimatly lead; him to a position of permanent service. The paragraph is silent about the temporary employee or any right accruing to him in case he continues in such a permanent vacancy for a period exceeding 3 months. There is nothing in the oral evidence or in the documentary evidence to substantiate the contention of the workman in this regard. Paragraph 4.95 (Page 137) of Sastry award may be referred to. That relates to the probationery period. It states that after the expiry of the period of probation the affected workman shall be deemed to have been confirmed. Of course, it is subject to the termination of service on or before the expiry of the period of probation. There is no analogy between this para and that of paragraph 20.8 of the Bi-partite Settlement. Before the Desai award was made no demand was made in the case of temporary employees though some demand was made in the case of other employees (See paragraph 23 at page 289 of Desai award). The fourth item of the demand of the employees as regards temporary employees relates to their service condition including daily wages, etc. It was further demanded before that tribunal, "Where daily rated or temporary hands remained in employment for an aggregate period of 3 months during any 12 executive months they should be deemed to be probationer and shall be so covered and absorbed against permanent vacancies. All such employees working for more than 3 months or more should be deemed as confirmed". The Desai tribunal rejected both the demands as is evident from paragraph 23.19 at page 296 of the award. So it is clear that the case of temporary employees regarding their probationery right is not upheld by any tribunal or in the Settlement. This is an indication that the temporary employees are always temporary. So, reading paragraph 20.8 of the Bi-partite Settlement one comes to the conclusion that the temporary employee will continue to be a temporary employee even after 3 months as long as the employer does not choose to discharge him. In the instant case the services of the affected workman was dispensed with not due to any misconduct but as a termination simpliciter on the terms and conditions of his employment.

10. The Sastry award classified bank workmen in three categories as permanent employee, probationer and temporary employee. In the Desai award this classification was accepted. But a new clause was added to the effect as inclusive of employees other than a permanent employee then appointed in a temporary vacancy of a permanent workman'. In the Bi-partite settlement of 1966 the definition of the expression "temporary employee" can be found in paragraph 20.7 at pages 56 and 57 of the Settlement. Paragraph 20.7 reads as follows :

> "In supersession of paragraph 21.20 and sub-clause (c) of paragraph 23.15 of the Desai Award, "Temporary Employee" will mean a workman who has been appointed for a limited period for work which is of an essentially temporary nature or who is employed temporarily as an additional workman in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman."

The only improvement upon the definition of a "temporary employee" in the Bi-partite Settlement was the inclusion of paragraph 20.8 in relation to the definition already in existence. The Bi-partite Settlement is binding on all the parties.

11. In all the documents produced in the case the workman is referred to as a "temporary employee". It is not his case either in the written statement or in his evidence that he was a permanent employee or that he was a probationer. His contention is that the workman concerned should be deemed to have become a probationer and therefore a permanent employee. It could not be gathered from the documents produced in the case that he had been appointed to any permanent vacancy. Even on the first appointment evidenced by Ext. M1 the appointment was made temporarily not against a sanctioned permanent vacancy. The fact that Sri Srivastava was transferred to another station will not by itself create a permanent vacancy. The workman had been told that he was to be appointed in a temporary vacancy. The condition of his appointment was set-forth as below in almost all the appointment letters :—

> (i) That you have been appointed on purely temporary basis for a period of . . . days from.....to ..... during the arrangement ..... which period may be extended in writing from time to time. Your services will come to an automatic end on the expiry of the period for which you have been appointed. Your services, can, however, be untilised in any other arrangement of temporary nature if so required.
>
> (ii) Notwithstanding anything contained in this letter your services are liable to be terminated in the sole discretion of the Bank at any time during the period for which you have been appointed, without assigning any reason but by giving you one days' notice or salary in lieu of notice.
>
> (iii) Your appointment is purely for temporary vacancy and carry no assurance whatsoever for absorption in permanent vacancy.

A scrutiny of the attendance Register, Ext. M19 and the Paysheets Ext. M20, indicates that the workman did not receive any salary during the intermittent break period. If he is found to be a temporary employee he cannot claim the status of a probationer or permanent employee. The paragraphs 21.20 and sub-clause (c) of paragraph 23.15 of Desai

award are superseded by paragraph 20.7 of the Bi-partite Settlement of October, 1966. The definition of temporary employee as shown in Desai award was amended by paragraph 20.7 of the Bi-partite Settlement which has already been dealt with. That definition shows that workman who has been appointed for a limited period for work which is essentially temporary in nature or who is employed temporarily as an additional workman in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman. No violation of either paragraph 20.7 or 20.8 concerning temporary employees has taken place in this case. The workman examined as the sole witness in this case, was not able to establish by evidence that the Branch Manager or any other authority influenced him to file Ext. M1 series—application praying for appointments though he had alleged malafide and unfair labour practice in the written statement. No evidence has been led to prove that the Bank had exercised any undue influence or any other method against the appointments made from time to time in this case. It is mentioned in every Order of appointment that he was being appointed temporarily. The temporary appointment has been dealt with specifically in the various awards. As a result of the temporary appointment the workman cannot claim any right of a probationer or that of a permanent employee.

12. The appointment of the workman had been dispensed with effect from 29-7-73 under the terms and conditions of his service. Though Sri R. T. Pandey returned from leave on 27-7-73 and joined service, the affected workman was not dispensed with his service on 28-7-1973 but was dispensed only with effect from 29-7-1973. So, in lieu of one day's notice as provided in the appointment order he was deemed to have been paid one day's salary in lieu of notice. He is not entitled to notice as a probationer or in any other capacity. There is sufficient notice in this case to dispense with his services. The termination of his service is, therefore, valid.

13. The contention of the affected workman is that the termination of his service is hit by the provisions of Section 23 of the Industrial Disputes Act, 1947 as, according to him, the notice of the dispute had been referred to the Conciliation Officer with effect from 19-7-1973 and that from that date the dispute was said to be pending before the Conciliation Officer. That contention cannot be accepted. The date of commencement of the conciliation proceeding has to be computed on terms of provisions of Section 12(1) of the Industrial Disputes Act which lays down that "where an industrial dispute exists or is apprehended the conciliation may held conciliation proceedings in the prescribed manner". Rule 10 of Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 provides that "where the Conciliation Officer receives any information about an existing or apprehended industrial dispute which is not related to public utility service....he shall give formal intimation in writing to the parties concerned declaring his intention of commencing conciliation proceedings with effect from such date as may be specified therein". Commenting upon this Rule Sri O. P. Malhotra, the learned authority of the "Law of Industrial Disputes, Volume I, 2nd Edn." at page 661 observes, "From this provision it appears that the date of commencement of conciliation proceedings before a conciliation officer will be the date specified by him in his communication sent to the parties in writing intimating them of his intention to commence the proceedings. It is neither the date on which the conciliation officer receives the information nor the date on which he communicates his intention to the parties on which the conciliation commenced. Even if a date specified by the Conciliation Officer in his communication to the parties any or all the parties do not appear before him the conciliation proceedings before him shall still be deemed to have commenced on the date". I respectfully agree with this observation

14. In the instant case the workman's association sent a communication on 19-7-1973 to the Conciliation Officer and the Conciliation Officer called both the parties for a discussion on 20-8-1973 but the discussion could not be held on that date and he called them again on 28-9-1973. The discussion was held on the latter date and the concilation ended in a failure. It is only when the conciliation officer communicates his intention to the parties as to the beginning of the conciliation that the proceedings is said to be pending It is neither the date on which the Conciliation Officer received the information nor the date on which he sends the communication to the parties that is relevant, but it is the date on which the conciliation proceedings started by the Officer that is most important. In this case it was from 20-8-1973 that the conciliation proceeding was begun as it would appear from Ext. W30. That shows that the Conciliation Officer fixed the date first on 20-8-1973 and then on 28-9-1973 from which date the proceedings was said to have commenced. In view of these circumstances it cannot be said that the termination of service of affected workman with effect from 29-7-1973 is hit by the provisions of Section 23 of the Industrial Disputes Act, 1947.

15. The last question that arises for determination is whether the workman is entitled to any retrenchment compensation under Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 1947. The affected workman worked for a period of 436 days from 24-4-1972 to 28-7-1973, during which period there was interimittent break in service. The learned representative of the management stated that the allegation in the written statement of the workmen was not sufficient to support his claim for retrenchment compensation. However, there was no denial in the written statement of the Bank that the workman's claim is covered by Section 25 F of the Industrial Disputes Act. The workman on the other hand has made an allegation in paragraph 6 of the written statement that the termination order is hit by Section 25 F of the I.D. Act and he would be entitled to all the reliefs in consequence thereof. In the absence of any direct denial of the allegation by the Bank in their written statement there is no reason to deny the workman his legitimate claim of retrenchment compensation under Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 1947.

16. It is true that Sri Sen Gupta was appointed on temporary basis but the post he held was that of a permanent employee who went on transfer. The first appointment was in the transfer vacancy of Sri Srivastava and the other was that of Sri Sinha. The termination order with effect from 29-7-1973 was proceeded by his service as a clerk-cum-cashier during leave vacancy of one R. T. Pandey from 5-6-1973 to 28-7-1973. The evidence was that after Pandey returned from leave on 27-7-73 the service of the affected workman was terminated with effect from 29-7-1973. When Pandey returned to duty the services of the affected workman was found to be in surplus.

17. When a person is temporarily employed either to meet some additional work or to do the work of a permanent incumbent who is on leave or on deputation to some other branch or even on transfer and the services of that temporary employee are terminated, the order of termination amounts to discharge of surplus labour or staff in a continuing or running industry. It is admitted that Sri Sen Gupta is a workman under the Bank and that the Punjab National Bank is an industry It is also admitted that there has been a termination of his service. Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act reads, "retrenchment" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action. Ext. W 23 contains such a termination order. In the case of Murugesan Naiker Co. vs. Labour Court, 1963 (I)I LJ, Veeraswami, J, as he then was, held that the expression "retrenchment" must be understood in its ordinary sense and every termination would not be retrenchment and the termination in order to be retrenchment should be of surplus labour or staff and it would be in an industry which is continuing and not closed, or transferred. This view has been consistently upheld by the Supreme Court beginning from the case of Hariparsad Sivasankar Sukla vs. A. D. Devalkar, 1957 Supreme Court Reporter, 121.

18. In view of Section 25 B and 25 F read with Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act, 1947, the workman should have been paid retrenchment compensation before the self-operating order resulted in the termination of service on 28-7-1973. This is the trend of the opinion which was given expression to in the case of State of Bombay vs Hospital Mazdoor Sabha, 1960(I) LLJ 251. Even a badli workman is entitled to the benefits of the provisions contained in Section 25 F of the Act if the requisite conditions set-forth in Section 25 B, 25 F and 2(oo) are complied with (See Digwadih Colliery vs Their workmen, 1965 (3) Supreme Court Reporter, 448). It cannot be disputed in such cir-

cumstances that a temporary workman is also entitled to retrenchment compensation. On that point there is a direct Supreme Court case reported in the Management of Will Cot Buckwell India Ltd. vs. Jagannath & Ors., 1974(24) Indian Factories and Labour Reports, 1973. The workman is, therefore, entitled to get retrenchment compensation under Section 25 F of the Industrial Disputes Act.

19. It is not disputed that the affected workman was in the service of the bank for 436 days. Within the 12 calendar months he should, under Sec. 25 B of the Act, work at least for 240 days or at least 120 days within 6 months during the period of his service. The affected workman has satisfied the conditions set-forth in Section 25 B of the Act. The maximum salary drawn by the affected workman as per salary sheets, Ext. M. 20, was Rs. 347.75 P. The workman, therefore, would be entitled to this amount in lieu of notice for one month under Section 25 F(a) of the Act. Under Section 25(b) he would be entitled to get compensation which is equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of 6 months. Section 25(B)(2) provides that where a workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year on 6 months he shall be deemed to be in continuous service under an employer (a) for a period of one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than (i) one hundred and ninety days in the case of a workman employed below groud in a mine; and (ii) two hundred and forty days, in any other case. It is to be admitted that the affected workman has satisfied this condition having worked for 240 days within one calendar year of 12 months. The affected workmin is, therefore, entitled to retrenchment compensation under Section 25F, Which would be Rs. 173.88 P. and the total amount of compensation due is Rs. 521.63 P.

20. The case of the workman that he should be reinstated cannot be supported in view of the fact that he sat for an examination conducted by the Bank and that he failed in the said examination. Having failed in the examination, it would not be correct to reinstate the workman or to allow any back wages. He can claim only retrenchment compensation as allowed in the foregoing paragraph.

21. In the result, the reference is answered in favour of the workman allowing a sum of Rs. 521. 63 P. (Rupees Five hundred twentyone and Sixtythree paise) as retrenchment compensation and in other respects the reference is rejected.

The award is made accordingly.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

Dated, Calcutta,

The 20th December, 1974

[No. L. 12012/129/73/LR. III]

S.O. 201.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen which was received by the Central Government on the 30th December, 1974.

BEFORE SHRI H. R. SODHI, PRESIDING OFFICER,

INDUSTRIAL TRIBUNAL, PUNJAB, CHANDIGARH

Reference No. 6/C of 1974

BETWEEN

The workmen and the Central Bank of India, Chandigarh.

Appearances :

Shri R. K. Joshi—for the workmen.

Shri H. L. Chhibber—for the management

AWARD

Shri Amrik Singh was an employee with the respondent establishment and he had a grievance that he was being denied his due promotion. An industrial dispute was accordingly raised and the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act. 1947, published in the Gazette of India the following matter to this Tribunal for adjudication :—

> Whether the action of the management of Central Bank of India, Chandigarh in denying promotion to Shri Amrik Singh, clerk at Ambala Cantonment Branch of the Bank is legal and justified ? If not, to what relief is he entitled ?

2. Pleadings were filed by the parties and the management raised some preliminary objections as well. The case was fixed for striking issues, but before that could be done, both the parties conceded that the said workman had been given promotion with effect from 25-3-1974 and as a matter of fact the workman admitted in replication that the promotion had taken place with effect from 25-3-1974. It appears that the matter of making of reference was pending before the Central Government which was not given information about the promotion of the workman. The only point referred to me for adjudication is whether promotion could be denied to Shri Amrik Singh and now that he has been promoted, the reference becomes infructuous. I order accordingly with no order as to costs.

H. R. SODHI, Presiding Officer

[No. L. 12012/13/74/LRIII]

New Delhi, the 8th January, 1975

S.O. 202.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in respect of a complaint under Section 33A of the said Act filed by All India Life Insurance Corporation Supervisory Staff Association, Bombay against Life Insurance Corporation of India, Central Office, Bombay which was received by Central Government on 27th December, 1974.

NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, JABALPUR

(M. P.)

Dated December 7, 1974

PRESENT :

MR. JUSTICE S. N. KATJU—Presiding Officer.

Case No. NIT(A)(6) of 1973

PARTIES :

1. All India L.I.C. Supervisory Staff Association C/o Shri C. R. Naik, 10, St. Xavier School, Vile Parle (West), Bombay 56.
2. Vasudeo Mahadeo Sinkar of Bombay Indian inhabitant, residing at Kenalkar Premises, Pipe Road, Kurla, Bombay-70.
3. Bhulabhai Gandubhai Diwan of Bombay, Indian inhabitant, residing at K/12 Bima Nagar, Sir. M. V. Road, Andheri (E), Bombay 69.
4. Ramchandra Abaji Bhaway of Bombay Indian inhabitant, residing at 14/B, Such Sadan, 3rd Floor, Mangalwadi, Girgaon, Bombay-4.

Complainants

Versus

Life Insurance Corporation of India, Central Office at Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Bombay-20.

Opposite Party.

APPEARANCES :

For Complainants—Shri P. M. Hatkar.

For Opposite Party—S/Shri A. W. Dharwadkar and Y. Ramchandran.

INDUSTRY : Insurance DISTRICT : Bombay.

AWARD

This is a Complaint under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act).

The first complainant is the All India L.I.C. Supervisory Staff Association. The second, third and fourth complainants are Section Heads. The grievance of the complaints is that the opposite party, the Life Insurance Corporation of India (hereinafter called the Corporation) "allowed the Assistants and some Section Heads to officiate in the cadre of Higher Grade Assistants with the officiating allowance payable to them, thus treating unequals as equals." The complainants say that they have not been included in the said order and the said officiating arrangements are clearly in breach of the aforesaid Regulations and Establishment Manual of the opposite party. It has been contended, inter alia, that by making the aforesaid officiating arrangements the Corporation has committed breach of Section 33-A of the I.D. Act and it is prayed that this Tribunal should "decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper."

It appears that the contention in substance is that the appointment of some Assistants and Section Heads as officiating Higher Grade Assistants was irregular and it should be set aside.

The Corporation in its reply has contended, inter alia, that the first Complainant, the All India L.I.C. Supervisory Staff Association, not being an employee, is not entitled to file any complaint under Section 33-A either on its own or on behalf of the employees. It was also contended that the complaint does not fall within the ambit of Section 33A of the Act and question of officiating arrangements was not a matter in issue in the reference before the Tribunal and consequently the aforesaid grievance of the Complainants cannot be entertained by the Tribunal. It was also contended by the Corporation that :—

> "The officiating arrangements are temporary in nature, no employee can claim any right to promotion by virtue of his officiating appointment and no employee has any right to claim that he should be appointed to officiate in a higher post. Administrative instructions regarding officiating arrangements are issued from time to time to various offices of the Corporation to carry out the purposes of Regulation 17. The previous instructions on the subject were incorporated in the Establishment Manual which is nothing but a compilation of various administrative instructions. These instructions do not constitute or form part of the terms and conditions of service of workmen nor are they immutable. As this Hon'ble Tribunal is seized of the dispute in the matter of rules regarding promotion, it has become necessary for the Corporation to effect officiating arrangements on a large scale, as no promotion could be effected while the said dispute is pending."

Thus the Corporation in order to ensure its proper working had to make officiating arrangements under Regulation 17 of the (Staff) Regulation which runs thus :—

> "17 (1) Notwithstanding anything contained in Regulation 7, the competent authority may at its discretion appoint an employee to officiate in a vacancy in a sanctioned post in a higher cadre.
>
> (2) No person appointed to officiate under Sub-reg. (1) shall by virtue of such appointment be entitled to any claim for promotion or for any increment in the higher scale.
>
> (3) An employee appointed to officiate in a higher post shall be liable to be reverted without notice during the officiating period."

I have heard the learned representatives of the parties. It was strenuously argued on behalf of the Complainants that by attempting to follow the promotion procedure as laid down in the agreement dated 15th February, 1973 the Corporation had in substance altered the conditions of service of the Complainants and had also tried to give effect to the provisions of the aforesaid agreement of 1973 which had been assailed by several unions and the validity of which was a matter for adjudication by this Tribunal. I may mention that by my award the aforesaid agreement of 1973 has been struck down.

There appears to be force in the contention of the Corporation that the question of officiating arrangements was not a subject matter of controversy before this Tribunal and therefore any dispute arising therefrom cannot be a subject matter of complaints under Section 33-A of the Act before me. I need not go further into this aspect of the matter. Even assuming that the complaints are entertainable by me under Section 33-A of the Act the question remains whether it was within the powers of the Corporation to make officiating arrangements in the manner in which it has been done.

The Corporation has contended that by such officiating arrangements no prejudice has been caused to complainants. It has been contended that :—

> "...at officiating appointments have been made in accordance with specific rules laid down for the purpose which take into account the length of service, qualifications, merit, etc., of the employees, and if the complainants have not been selected, it is only because they did not come upto the requisite standard under the norms fixed for assessing such standard. It is not even the case of complainants that they have any claim to an officiating appointment or that they have been victimised or any favouritism has been shown to those who have been selected. The Corporation denies that there has been any breach of the provisions of the Regulations or of administrative instructions or of law."

To make officiating arrangements during the pendency of the reference was a matter within the managerial functions of the Corporation and even if I have jurisdiction to entertain the complaints I will be reluctant to interfere in such a matter particularly when there is no allegation of malafides or victimization on behalf of the complainants. I have, therefore, no hesitation in holding that the Corporation had acted within its powers in making the officiating appointments in the manner that it did and the complaint has no force. It is dismissed. I make no order as to costs.

S. N. KATJU, Presiding Officer.

[No. Dy. 3331/LRI/74/DO. II/A]

New Delhi, the 9th January, 1975

S.O. 203.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in respect of a complaint under Section 33A of the said Act filed by Shri Bipin C. Shah of the Ahmedabad Divisional Office of the Life Insurance Corporation of India (Policy Holders Servicing Department) against Life Insurance Corporation of India, Central Office, Bombay which was received by Central Government on the 27th December, 1974.

NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, JABALPUR.

Dated 7-12-1974.

Case No. NIT(A)(8) of 1973.

PARTIES :

Bipin C. Shah of Ahmedabad, Divisional Office Indian Inhabitant residing at Ahmedabad.—Complainant.

Versus

Life Insurance Corporation of India, Central Office, 'Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Bombay.—Opposition Party.

APPEARANCES.

For Complainant.—Shri Bipin C. Shah, Complainant.

For Opposite Party—S/Shri A. W. Dharwadkar and Y. Ramchandran

INDUSTRY : Insurance DISTRICT : Bombay.

AWARD

This is a Complaint under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act).

The Complainant Shri Bipin C. Shah was employed as an Assistant at the Ahmedabad Divisional Office of the Life Insurance Corporation of India (hereinafter called the Corporation) in the Policy Holders Servicing Department. By an office order dated 23-1-1973 the complainant was appointed as an officiating Section Head in the Policy Holders Servicing Department from 23-1-1973 onwards in a casual vacancy. The office letter further stated that during the period of the officiating appointment in the Section Head cadre the complainant will be paid an amount of Rs. 40 p.m. as officiating allowance in addition to his remuneration. By the office order dated 17-8-1973 the officiating appointment of the complainant was terminated on 17-8-1973. According to the Complainant the said post of Section Head which was held by him in his officiating capacity was offered to Shri N. M. Trivedi. The grievance of the complainant is that by terminating his officiating appointment the Corporation has made alteration in the terms and conditions applicable to him and that it is not authorised by the Regulations as regards the officiating arrangements to do so inasmuch it is contrary to the arrangement prescribed in the Manual.

The Corporation in its reply has contended, inter alia, that the complaint does not fall within the ambit of Section 33-A of the Act and the question of officiating arrangement was not a matter in issue in the reference before this Tribunal and consequently the aforesaid grievance of the applicant cannot be entertained by this Tribunal. It was also contended by the Corporation that :—

"The officiating arrangements are temporary in nature, no employee can claim any right to promotion by virtue of his officiating appointment and no employee has any right to claim that he should be appointed to officiate in a higher post. Administrative instructions regarding officiating arrangements are issued from time to time to various offices of the Corporation to carry out the purposes of Regulation 17. The previous instructions on the subject were incorporated in the Establishment Manual which is nothing but a Compilation of various administrative instructions. These instructions do not constitute or form part of the terms and conditions of service of workmen nor are they immutable. As This Hon'ble Tribunal is seized of the dispute in the matter of rules regarding promotion, it has become necessary for the Corporation to effect officiating arrangements on a large scale, as no promotion could be effected while the said dispute is pending."

Thus the Corporation in order to ensure its proper working had to make officiating arrangements under Regulation 17 of the (Staff) Regulation which runs thus :—

"17 (1) Notwithstanding anything contained in Reg. 7, the competent authority may at its discretion appoint an employee to officiate in a vacancy in a sanctioned post in a higher cadre.

(2) No person appointed to officiate under Sub Reg. (1) shall by virtue of such appointment be entitled to any claim for promotion or for any increment in the higher scale.

(3) An employee appointed to officiate in a higher post shall be liable to be reverted without notice during the officiating period."

I have heard the arguments of the parties. It was strenuously argued by the complainant that by attempting to follow the promotion procedure as laid down in the agreement dated 15th February 1973 the Corporation had in substance altered the conditions of service of the complainant and had also tried to give effect to the provisions of the aforesaid agreement of 1973 which had been assailed by several unions and the validity of which was a matter for adjudication by this Tribunal. I may mention that by my award the aforesaid agreement of 1973 has been struck down.

There appears to be force in the contention of the Corporation that the question of officiating arrangements was not a subject matter of controversy before this Tribunal and therefore it cannot raise any dispute arising under Section 33-A of the Act before me. I need not go further into this aspect of the matter. Even assuming that the complaint is entertainable by me under Section 33-A of the Act the question remains whether it was within the powers of the Corporation to make officiating arrangement in the manner in which it has been done.

The Corporation has contended that by such officiating arrangements no prejudice has been caused to the complaint. It has been contended that :—

"..all the officiating arrangements to the cadre of Section Heads have been made according to the formula laid down in the aforesaid Circular dated 16th May, 1973 governing officiating arrangements to the cadre of Section Head and the complainant has not been prejudiced in any way whatsoever"

To make officiating arrangements during the pendency of the reference was a matter within the managerial functions of the Corporation and even if I have jurisdiction to entertain the complaint I will be reluctant to interfere in such a matter particularly when there is no allegation of *malafides* or victimization on behalf of the complaint. I have, therefore, no hesitation in holding that the Corporation had acted within its powers in making the officiating appointments in the manner that it did and the complaint has no force.

The complainant is possessed of sufficient educational and technical qualifications. He has already acted as a Section Head in an officiating capacity. He may well qualify himself for the post of Section Head as also of Higher Grade Assistant. It will be desirable that the Corporation takes into account the necessary eligibility conditions for promotion of the complainant in the light of the observations made by me above as also in my award and give the complainant such relief as it can. With the aforesaid observations the complaint is dismissed. I make no order as to costs.

Sd/-

S. N. KATJU, Presiding Officer

[Dy No. 3330/LRI/74/DO. II(A)]

R. KUNHAPADAM, Under Secy

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1975

का. आ. 204.—कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 371 तारीख 17 दिसम्बर 1971, को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री वे. एस. नायक के स्थान पर

श्री वी. वेमचन्द्र राव को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिए, समस्त महाराष्ट्र राज्य तथा गोवा दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त करती है ।

[स का 12016/(7)/72-पी. एफ. 1(i)]

New Delhi, the 2nd January, 1975

S.O. 204.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 371, dated the 17th December, 1971, the Central Government hereby appoints Shri V. Hemachandra Rao, as Regional Provident Fund Commissioner for the whole of the State of Maharashtra and the Union territory of Goa, Daman and Diu to assist the Central Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties vice Shri K. S. Naik.

[No. A. 12016(7)/72-PF-I(i)]

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1975

का०आ० 205.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री पी० महादेवन को उक्त अधिनियम और स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कंपनी, महापत्तन खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण केरल राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के महाक्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[संख्या ए-12016/11/72-पी०एफ०-I]
आर०पी० नरूला, अवर सचिव

New Delhi, the 6th January, 1975

S.O. 205.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri P. Mahadevan to be an Inspector for the whole of the State of Kerala and Mahe area of the Union Territory of Pondicherry for the purposes of the said Act, and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company; a major port, a mine or an oil field or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A 12016(11)/72-PFI]
R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1975

का०आ० 206.—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार के पर्यटन और विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विद्युत और यांत्रिक कर्मशाला, मद्रास हवाई पत्तन, मद्रास के कर्मचारियों को, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित प्रसुविधाएं जैसी सारतः प्रसुविधाएं प्राप्त है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1526, तारीख 20 मार्च, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् उक्त वर्णित कारखाना को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 फरवरी, 1973 से 31 जनवरी, 1975 तक, जिनमें यह दिन भी सम्मिलित हैं, छूट देती है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि इस कारखाने को छूट देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की सिफारिश केवल अगस्त, 1974 में ही प्राप्त हुई थी। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में इस कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी वे अभी तक भी बनी हुई हैं और यह कारखाना छूट के लिए पात्र है।

[फा० सं० एस-38017/7(11)/74-एच० आई०]
टी०एस० कृष्णामूर्ती
अवर सचिव

New Delhi, the 3rd January, 1975

S.O. 206.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Electrical and Mechanical Workshop Madras Airport, Madras under the control of the Ministry of Tourism and Civil Aviation, Government of India are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1526, dated the 20th March, 1972 the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period with effect from the 1st February, 1973 upto and inclusive of the 31st January, 1975.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees' State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received only in August, 1974. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption.

[No. S-38017/11/74-HI]
T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy

New Delhi, the 9th January, 1975

S.O. 207.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to Messrs Ivan Milutinovic-PIM, Vasco-da-Gama (Goa) and their workmen which was received by the Central Government on the 3rd January, 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

REFERENCE No. CGIT-2/22 OF 1974

Employees in relation to the Management of Messrs Ivan Milutinovic-PIM, Vasco-da-Gama, (GOA).

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Management—Shri Miodrag Dosljak, Project Manager.

Miss K. Arijana, Secretary.

For the Workmen.—Shri Mohan Nair, General Secretary, Goa Dock Labour Union.

Shri R. V. Gaundalkar, Assistant Secretary.

Industry : Ports and Docks.

State : Goa, Daman and Diu.

Bombay, the 11th December, 1974.

AWARD

By order No. L. 36011/10/74/P&D/LRIII, dated 5-8-1974 the Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) made a reference to this Tribunal to decide whether the management of Messrs. Ivan Milutinovic-PIM, Vasco-do-Gama (Goa) are justified in not paying Variable Dearness Allowance to their workmen in view of the increase in cost of living index ? If not to what relief are they entitled ?'

The reference was posted for written statement of the parties.

But the parties have not filed a settlement signed by the management and the Union and request that the Award be passed in the light of the settlement.

A reading of the settlement shows that the terms are reasonable and fair and not prejudicial to the workman. Award is made in terms of the settlement. Reference is answered accordingly. A copy of the settlement is annexed herewith as annexure 'X'.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer.

'ANNEXURE X'

MEMORANDUM OF SETTLEMENT SIGNED UNDER SUB-SECTION 1 OF SECTION 18 READ WITH SECTION 2(P) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 BETWEEN THE MANAGEMENT OF M/S. IVAN MILUTINOVIC-PIM, VASCO-DA-GAMA AND THEIR WORKMEN REPRESENTED BY GOA DOCK LABOUR UNION (INTUC), VASCO-DA-GAMA.

PRESENT :

Representing the Management.—1. Mr. Miodrag Dosljak, Project Manager.

2. Miss K. Arijana, Secretary.

Representing the Workman.—1. Shri Mohan Nair, General Secretary, Goa Dock Labour Union.

2. Shri R. V. Gaundalkar, Assistant Secretary, Goa Dock Labour Union.

3. Shri P. N. Pappachan.

4. Shri Y. Y. Ling.

Short Recital of the case

The Goa Dock Labour Union, hereinafter called the "Union" vide its letter No. GDLU/PIM/243/74, dated 18-3-1974 placed before the Management of M/s Ivan Milutinovic PIM, hereinafter called the "Management" certain grievances/demands concerning the employees employed by and under them. The demands were, Payment of Bonus for the year 1973, payment of V.D.A., issue of uniform for the year 1974, marking of present on 6th February, 1974, curtailment of the existing practice, payment of injury compensation to Shri Asgar Ibrahim Dadarkar, violation of Section 25(H) of the I.D. Act etc. The negotiations between the parties did not bring any result and, therefore, the Union approached the Assistant Labour Commissioner (C), Vasco-da-Gama for his intervention. The Assistant Labour Commissioner (C) vide his letter No. V-16(1)/73-18, dated 27th March, 1974 fixed conciliation proceedings in the office on 30-3-1974. During the course of discussions before the Assistant Labour Commissioner (C) and the Management stated that on 11th April, 1974, they have paid bonus to their workmen for the year 1973. The question of issue of surf and soap etc. was also mutually settled. As regards supply of uniform, the Management agreed to issue the same to the workmen within 2-1/2 months from the date of signing the contract with the Marmogoa Port Trust and the remaining matters were kept for discussion on a future date. On 6-6-1974, a settlement was signed under Section 12(3) of the Industrial disputes Act, 1947 and a copy of the same is enclosed and marked as Annexure 'A'. As the parties could not arrive at a settlement on all the 8 points Demands, a Failure of conciliation was recorded and the Assistant Labour Commissioner (C) vide his letter No. V-16(1)/74-18, dated 12th June, 1974 submitted his Failure Report to the appropriate Government. The Government of India vide its order No. L. 36011/10/74/P&D/LRIII, dated 5th August, 1974, referred the matter of payment of Variable Dearness Allowance to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay for Adjudication. The Central Government Industrial Tribunal vide its letter No. Ref./CGIT-2/22 of 1974/2083/74, dated 19-8-1974 directed the parties to file their Statement of Claim under Section 10B(1) and 10B(2) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957. In the meantime, the Management and the Union have again negotiated on the issue in order to maintain industrial peace. After prolonged discussions, both the parties have arrived at the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

1. The Management agrees to introduce V.D.A. to all the workmen at the rate of Rs. 55 per head per month from 1-10-1974. The Management agrees to review the V.D.A. next in 1st April, 1975 and that the Union agrees not to raise any demand in respect of V.D.A. between the period of 1-10-1974 till 31-3-1975. Both the parties agree to discuss this issue on or before 25th March, 1975 so as to finalise the V.D.A. payable from 1-4-1975 onwards. The above payment wil be made only to those who are on the rolls of the Company as and on 1-10-1974, and to those who are subsequently recruited.

2. The Management agrees to pay a lumpsum of Rs. 250 to each workmen towards their claim for payment of V.D.A., for the past period upto 30th September, 1974, i.e. the claim for the payment of V.D.A. from 1-1-1973 till 30th September, 1974 has been amicably settled between the parties towards this payment of Rs. 250 per head.

3. The Management and the Union agrees to abide by the Additional Emoluments (Compulsory Deposits) Act, 1974, applicable to the construction workers while effecting the payment mentioned in Clause (1) and (2) above.

4. Both the parties agree to file this Memorandum of Settlement before the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal No. 2 as Reference No. CGIT-2/22 of 1974 is pending before the Hon'ble Industrial Tribunal and both the parties further agree to request the Hon'ble Tribunal for a Consent Award in the light of the above Settlement.

Representing the Management	Representing the workmen
Sd/-	Sd/-
1. (Miodrag Dosljak)	1 Mohan Nair)
2 (Miss K Arijana)	2 (R. V Gaundalkar)
	3. (P. N. Pappachan)
	4 (Y. Y. Ling)

Witness : 1. Sd/-

2 Sd/-

Vasco-da-Gama, Goa,

Dated : this 4th day of December, 1974.

ANNEXURE 'A'

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT UNDER SEC. 12(3) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947, BEFORE THE ASSTT. LABOUR COMMISSIONER (C), VASCO-DA-GAMA, BETWEEN M/S IVAN MILUTINOVIC-PIM AND THEIR WORKMEN REPRESENTED BY GOA DOCK LABOUR UNION

Representing Management.—Shri Kosta Jeremic.

Shri D. B. Johney.

Representing Workmen.—Shri S. V. Rao, Executive Committee Member of Goa Dock Labour Union.

PRESENT :

Shri S. B. Singh, Asst. Labour Commissioner (C) Vasco-da-Gama

Short Recital of the Case

Goa Dock Labour Union (INTUC), under their letter, dated 23rd March, 1974 raised an industrial dispute on a Charter of 8-Demands. Before raising the dispute, the Union had represented their case before the management, under their letter, dated 18-3-1974. After discussions held on 30-3-1974, 11-4-1974, 19-4-1974, 30-4-1974, 10-5-1974 6-6-1794, the dispute was seized in conciliation 6-6-1974

Demand No. 1.

Demand for Payment of Bonus for the year 1973 has already been met by the management and the Bonus has also been paid on 11-4-74 Hence the demand stands settled Demand No 2 regarding payment of V.D.A. After prolonged discussions, no settlement could be arrived at, hence conciliation in respect of this demand has ended in failure on 6-6-1974. Demand No. 5 regarding marking attendance on 6-2-1974 has been withdrawn by the Union. Demand No. 6 regarding grant of benefits of retrenched employee to Shri Agnel Gomes has been withdrawn by the Union. Demand No. 7 regarding payment of injury compensation to Shri Asger Ibrahim Dadarker, After discussions in this office, the parties have referred this demand to the Commissioner, Workmens' Compensation Act. Demand No. 8 regarding alleged violation of Sec. 25(H) of the I.D. Act, 1947. No amicable settlement could be arrived at and hence failure has been recorded on 6-6-1974 in respect of Demand No. 8 Settlement have, however, been arrived at in respect of the following demands.

Terms of Settlement

Demand No 3 regarding supply of Surf, Soap & Uniforms :

(i) The management has agreed to supply surf and soap from January, 1974.

(ii) Supply of Uniforms for the year 1974 : The management has agreed to supply the Uniforms for the year 1974 by 5th July, 1974.

(iii) The parties will submit their implementation report to the Asstt Labour Commissioner (C), by 15-7-1974 failing which it will be presumed that the Settlement has been implemented.

Sd/-	Sd/-
(Kosta Jeremic)	(S. V. Rao)
(D B Johney)	

Witness :

1. Sd/-

2. Sd/-

Sd/-
S. B. SINGH,
Asst. Labour Commissioner (C),
Vasco-da-Gama (Sambhaji)
Vasco-da-Gama
6-6-1974

[No L. 36011/10/74/P&D/CMT/D. IV(A)]
NAND LAL, Section Officer (Special)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1974